

JOTI JOURNAL
SUBJECT – INDEX
FEBRUARY – DECEMBER, 2023

Editorial	1
Editorial	55
Editorial	107
Editorial	155
Editorial	197
Editorial	235

PART – I
(ARTICLES & MISC.)

1	Photographs	3
2	Photographs	57
3	Photographs	109
4	Photographs	157
5	Photographs	199
6	Photographs	237
7	Republic Day Message of the Hon’ble Chief Justice	9
8	Address of the Hon’ble Chief Justice Shri Ravi Malimath on Independence Day	163
9	Appointment of Judges in High Court of Madhya Pradesh	116
9(i)	Hon’ble Shri Justice Raj Mohan Singh, Hon’ble Shri Justice Rajendra Kumar-IV and Hon’ble Shri Justice Duppala Venkata Ramana assume charge	243(i)
10	Appointment of Judges in High Court of Madhya Pradesh	244
11	Transfer of Hon’ble Shri Justice Atul Sreedharan to Jammu & Kashmir and Ladakh High Court	115
12	Hon’ble Shri Justice Virender Singh demits office	60

13	Hon'ble Smt. Justice Anjuli Palo and Hon'ble Shri Justice Rajendra Kumar (Verma) demit office	120
14	Hon'ble Shri Justice Arun Kumar Sharma demits office	162
15	Hon'ble Smt. Justice Nandita Dubey, Hon'ble Shri Justice Deepak Kumar Agarwal and Hon'ble Shri Justice Satyendra Kumar Singh demit office	206
16	OUR LEGENDS - Justice Mohammad Hidayatullah	22
17	OUR LEGENDS - Hon'ble Shri Justice G.P. Bhutt	61
18	OUR LEGENDS - Hon'ble Shri Justice P.V. Dixit	121
19	OUR LEGENDS - Hon'ble Shri Justice Bishambhar Dayal	168
20	OUR LEGENDS - Hon'ble Shri Justice P.K. Tare	209
21	OUR LEGENDS - Hon'ble Shri Justice Shivdayal Shrivastava	249
22	Annual Report of the Academic Activities of the Madhya Pradesh State Judicial Academy in the year 2023	256
23	Analysis of the Probation of Offenders Act, 1958	81
24	Commercial disputes under the Commercial Courts Act, 2015: An overview	213
25	Conference of Principal District & Sessions Judges: Summation & Resolution	19
26	Criminal Appeal <i>vis-a-vis</i> Right to be heard	171
27	DNA Evidence in Contemporary Legal Perspective	41
28	Effective rehabilitative diversion programmes under Juvenile Justice System: Need of the hour	221
29	Forgery and Fabrication cases: An Overview	28
30	Hindu Temples & Law of Public Trust	124
31	Inheritance in Muslim Law relating to Shia Law	178
32	Jurisdiction of Court <i>vis-a-vis</i> bar against suit	64
33	Law of Accomplice	282
34	Law relating to Statutory Notice u/s 80 CPC	91
35	Section 9 of Arbitration and Conciliation Act, 1996: An overview	274

36	Statement of accused : A vital piece of a Legal Puzzle	140
37	कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण : क्षेत्र एवं विस्तार	187
38	विधिक समस्याएं एवं समाधान	
(1)	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) प्रस्तुत होने पर विधिक स्थिति क्या होगी?	52
(2)	मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत मोटर साईकिल पर पीछे बैठे हुए यात्री (पिलीयन राईडर) की मृत्यु या उपहति होने की दशा में, क्या वह अनुग्रह यात्री की श्रेणी में आयेगा या वह प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है?	53
(3)	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आवेदन करने की क्या परिसीमा है?	104
(4)	व्यतिक्रम जमानत के आवेदन का निराकरण करते समय रिमाण्ड दिये जाने वाले दिन की गणना कैसे की जायेगी?	105
(5)	क्या ऐसा दस्तावेज जिसका स्टाम्पित होना आपेक्षित है, में स्टाम्प की कमी या उसका अभाव, ऐसे दस्तावेज में लिखे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को भी अप्रभावी बना देता है?	106
(6)	अचल संपत्ति के विक्रय करार में कब्जा परिदत्त होने की दशा में दस्तावेज कि प्रकृति क्या होगी, उस पर कितना स्टाम्प शुल्क का संदाय अपेक्षित है तथा अपर्याप्त स्टाम्पित होने की दशा में विधि क्या है?	152
(7)	वाणिज्यिक न्यायालयों में लंबित माध्यस्थम संबंधी प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।	153
(8)	पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में यदि न्यायालय द्वारा धारा 244 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने से पूर्व अभियोजन को सुने बिना और आरोप पूर्व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आरोप विरचित कर दिये जाते हैं तो क्या उपचार उपलब्ध है?	154
(9)	क्या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में, वर्ष 2018 में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप संशोधन पूर्व लंबित मामलों के संबंध में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्ली पारित किया जाना आदेशात्मक है?	194

- (10) जब दण्डादेश के निष्पादन के संबंध में अपीलिय न्यायालय द्वारा सशर्त स्थगन दिया गया है तब शर्त के अपालन की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी? **195**
- (11) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास की शर्तों के उल्लंघन में जब्तशुदा मदिरा के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा कब संज्ञान लिया जा सकता है **195**
- (12) क्या शून्य अथवा शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न संताने अपने माता-पिता की स्वअर्जित संपत्ति के अतिरिक्त पैतृक संपत्ति से भी अंश प्राप्त करने के अधिकारी हैं? **232**
- (13) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत पारित मौद्रिक अनुतोष या अंतरिम मौद्रिक अनुतोष (भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण) आदेश के भंग के संबंध में क्या सीधे पुलिस रिपोर्ट की जा सकती है? **233**
- (14) किसी लोक न्यास द्वारा संचालित धर्मस्थलों के रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक अधिकारिता वाले जिला न्यायाधीश को क्या अधिकार प्राप्त हैं? **295**
- (15) लोक अदालत में समझौता होने की स्थिति में न्यायालय शुल्क वापसी के संबंध में क्या प्रावधान है? **295**

PART - II

(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

Act/ Topic	Note No.	Page No.
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)		
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)		
Sections 3 (1) (b) and 12 (1) – Exempted premises – Such exemption is provided to the premises itself, regardless of the relation and status of landlord and tenant.		
धाराएं 3 (1) (ब) एवं 12 (1) – छूट प्राप्त परिसर – इस तरह की छूट मकान मालिक और किरायेदार के संबंध और प्रास्थिति पर विचार किए बिना परिसर को ही प्रदान की जाती है।	164	229
Sections 12 (1) (a), (f) and (g) – Eviction suit – Bona fide requirement – Non-disclosure of availability of alternate accommodation – Effect.		

धाराएं 12 (1) (क), (च) और (छ) – निष्कासन हेतु वाद – वास्तविक आवश्यकता – वैकल्पिक आवास की उपलब्धता का अप्रकटीकरण – प्रभाव।

123 175

Section 12(1) (e) – Eviction – *Bona fide* requirement – Date of institution of suit is a crucial date for ascertaining *bona fide* need – Subsequent event which affects the need should be such that it may over shadow the *bona fide* need.

धारा 12(1) (ड) – निष्कासन – वास्तविक आवश्यकता – वाद संस्थित करने की तिथि वास्तविक आवश्यकता अभिनिर्धारित करने हेतु निर्णायक तिथि है – पश्चातवर्ती घटना जो आवश्यकता को प्रभावित करती है, ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक आवश्यकता के महत्व को निष्प्रभावी कर दे।

215 309

Section 12(1)(f) – Availability of alternative vacant non-residential accommodation and its unsuitability – When necessarily required to be pleaded?

धारा 12 (1) (च) – वैकल्पिक रिक्त अनिवासिक स्थान की उपलब्धता और इसकी अनुपयुक्तता – कब अभिवचन किया जाना आवश्यक है ?

216 310

ADVERSE POSSESSION:

प्रतिकूल कब्जा:

Adverse possession against Government – Principles summarized.

शासन के विरुद्ध प्रतिकूल आधिपत्य – सिद्धांत सारांशित। 78 115

ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996

Sections 2 (1) (e), 9, 14 and 34 – See sections 3, 3-A, 3(1a), 10, 15 and 21 of the Commercial Court Act, 2015.

धाराएं 2 (1) (ड), 9, 14 और 34 – देखें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धाराएं 3, 3-क, 3(1क), 10, 15 एवं 21।

86 128

Sections 7 and 8 – Arbitration agreement – Effect of absence of any of the attributes in an arbitration agreement.

धाराएं 7 एवं 8 – माध्यस्थम करार – माध्यस्थम करार के आवश्यक गुणों का करार में अभाव का प्रभाव।

1 1

Sections 8 and 11 – Reference to arbitration – Where suit involves non-signatories to arbitration agreement and substantive relief claimed in suit falls outside the arbitration clause, such arbitration agreement not binding on non-signatories – Application for reference not acceptable – Partial reference of suit to arbitration impermissible.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 8 एवं 11 – मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाना – जहाँ वाद में मध्यस्थता करार के गैर-हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं और वाद में दावा किया गया वास्तविक अनुतोष मध्यस्थता खंड के बाहर है, ऐसा मध्यस्थता करार गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं – संदर्भित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं – मध्यस्थता के लिए वाद का आंशिक संदर्भ अनुमत नहीं।	165	230
Section 9 – Commercial Court – Territorial jurisdiction in claim regarding rendition of accounts, explained.		
धारा 9 – वाणिज्यिक न्यायालय – लेखा प्रस्तुत करने के दावे में भौतिक क्षेत्राधिकार समझाया गया।	124	176
Section 9 – Interim injunction – While deciding the question of irreparable loss, the aspect of negative impact on future prospects must be considered as well – Mere consideration of getting compensated in terms of money is not enough.		
धारा 9 – अंतरिम निषेधाज्ञा – अपूर्णीय क्षति के प्रश्न को निर्णीत करते समय भावी संभावनाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी विचार में लेना चाहिए – धन से क्षतिपूर्ति हो सकने के बिंदु मात्र पर विचार पर्याप्त नहीं है।	166	231
Section 9 – Interim relief – Grant of.		
धारा 9 – अंतरिम अनुतोष – अनुदान।	2	3
Section 11 (6) – Arbitration agreement – Effect of non-renewal of lease on arbitration agreement.		
धारा 11 (6) – मध्यस्थता अनुबंध – पट्टे का नवीनीकरण न होना का मध्यस्थता अनुबंध पर प्रभाव।	3	4
Sections 12 (5) and 34 – (i) Arbitral award – Challenged on the ground that appointment of arbitrator is violative of section 12 (5) – Appointment of arbitrator was prior to the amendment – Section 12 (5) applicable only prospectively – <i>Bharat Broadband Network Limited v. United Telecoms Limited (2019) 5 SCC 755</i> relied upon.		
(ii) Delay in deciding application – Directions issued.		
धाराएं 12 (5) एवं 34 – (i) माध्यस्थ पंचाट – धारा 12 (5) के अतिलंघन के आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती – मध्यस्थ की नियुक्ति संशोधन पूर्व से – धारा 12 (5) केवल भविष्यवर्ती रूप से लागू – <i>भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड विरुद्ध यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड, (2019) 5 एससीसी 755</i> पर विश्वास किया गया।		
(ii) आवेदन के निराकरण में विलंब – निर्देश जारी किए गए।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
	79	116
Sections 16, 34 and 35 – Arbitral award – Effect of raising issue of jurisdiction before executing court for the first time.		
धाराएं 16, 34 एवं 35 – माध्यस्थम अधिनिर्णय – क्षेत्राधिकार का विषय निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रथम बार उठाए जाने का प्रभाव।	125	177
Section 34 (2)(a) and (b) – Arbitral award – When application for adducing additional evidence can be allowed?		
धारा 34 (2)(क) एवं (ख) – माध्यस्थम पंचाट – कब अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है?	167	231
Section 34 (3) – Application for setting aside award – Delay – Condonation – The benefit of Limitation Act and General Clauses Act available only when application is filed within 30 days of extended period.		
धारा 34 (3) – पंचाट को अपास्त कराने हेतु आवेदन – विलंब – क्षमा – परिसीमा अधिनियम और साधारण खण्ड अधिनियम का लाभ केवल तब उपलब्ध है जब आवेदन 30 दिवस के बढी हुई अवधि के भीतर किया गया हो।	217	311

BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) ACT, 1988

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988

Section 4 (3) (a) – (i) Benami transaction – Burden of proof lies on one who alleges transaction to be benami.

(ii) Circumstances which can be taken as a guideline to determine the nature of transaction – Principles reiterated.

धारा 4 (3) (क) – (i) बेनामी संव्यवहार – सबूत का भार उस पक्ष पर होता है, जो संव्यवहार का बेनामी होना अभिकथित करता है।

(ii) संव्यवहार की प्रकृति ज्ञात करने हेतु परिस्थितियाँ जिन्हें मार्गदर्शक के रूप में विचार में लिया जा सकता है – सिद्धांत दोहराया गया। **38** **55**

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Section 11 – *Res Judicata* – Issue not arising for consideration in previous suit cannot operate as *res judicata* in subsequent suit.

धारा 11 – पूर्व न्याय – पूर्ववर्ती प्रकरण में विचार के लिए उत्पन्न नहीं होने वाला विवाद्यक पश्चात्वर्ती प्रकरण में पूर्व न्याय के रूप में प्रभाव नहीं रखेगा।

126 **178**

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 11 and Order 7 Rule 11 – (i) <i>Res Judicata</i> – <i>Lis</i> between parties decided by the Writ Court – Order would operate as <i>res judicata</i> on subsequent proceeding – Party precluded from filing civil suit seeking the same relief.		
(ii) Doctrine of merger – Writ Court decided the matter on merits – In writ appeal, liberty to file civil suit was allowed – Order passed by Writ Court on merits shall survive – Doctrine of merger not applicable.		
धारा 11 एवं आदेश 7 नियम 11 – (i) पूर्व न्याय – रिट न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य का विवाद निराकृत किया गया – आदेश पश्चात्वर्ती कार्यवाही पर पूर्वन्याय के रूप में प्रभावी – पक्षकार समान अनुतोष हेतु सिविल वाद दायर करने से बाधित।		
(ii) विलयन का सिद्धांत – रिट न्यायालय द्वारा विषय गुण-दोष पर निराकृत – रिट अपील में सिविल वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता को अनुज्ञा दी गई – रिट न्यायालय का गुण-दोष पर पारित आदेश जीवित रहेगा – विलयन का सिद्धांत लागू नहीं।	127	179
Section 11, Order 33 Rules 5 & 15-A and Order 7 Rule 11 –		
(i) Application to sue as indigent person – Can be rejected on the ground that suit is vexatious, barred by <i>res judicata</i> or on no cause of action – Observation confined to decision of such application only.		
(ii) Rejection of an application to sue as indigent person – Applicant may institute suit after paying requisite court fees – Defendant may object under Order 7 Rule 11 of the Code on such grounds.		
धारा 11, आदेश 33 नियम 5, 15-क एवं आदेश 7 नियम 11 – (i) निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने का आवेदन – वाद तंग करने वाला, पूर्वन्याय से बाधित अथवा बिना वाद कारण के आधार पर निरस्त किया जा सकेगा – टिप्पणी केवल आवेदन के निराकरण तक सीमित।		
(ii) निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के आवेदन का नामंजूर किया जाना – आवेदक आवश्यक न्याय शुल्क संदाय कर वाद संस्थित कर सकता है – तथापि प्रतिवादी संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन ऐसे आधारों पर आपत्ति कर सकेगा।	39	56
Section 16 (d) – See section 9 of Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
धारा 16 (घ) – देखें माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9।	124	176
Section 47 and Order 21 – Powers of Executing Court – Scope.		
धारा 47ए वं आदेश 21 – निष्पादन न्यायालय की शक्तियाँ – विस्तार।	168	234

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 54, Order 6 Rule 4, Order 20 Rule 18 and Order 21 Rules 97 to 101		
– (i) Suit for partition – Preliminary decree – Merely declaring shares that parties are entitled to – Does not confer right to trade in such share of properties.		
(ii) Dispute as to title – Such dispute cannot be resolved in a partition suit, unless the same is incidental to fundamentals of claim – Title cannot be decided in favour of parties claiming partition <i>qua</i> strangers – Same logic would apply to the claim petitioners <i>qua</i> the State Government.		
(iii) Enquiry under Order 21, Rules 97 to 101 CPC – Scope.		
धारा 54, आदेश 6 नियम 4, आदेश 20 नियम 18 एवं आदेश 21 नियम 97 से 101 –		
(i) विभाजन का वाद – प्रारंभिक डिक्री – केवल अंश की घोषणा करती है, जिसके लिए पक्षकार हकदार हैं – संपत्ति के उस अंश पर व्यापार के अधिकार को प्रदान नहीं करती।		
(ii) स्वत्व के संबंध में विवाद – ऐसे विवाद का निराकरण विभाजन के वाद में नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह दावे के आधारों से आनुषंगिक ना हो – ऐसे पक्षकारों के पक्ष में स्वत्व निराकृत नहीं किया जा सकता, जो अपरिचित की हैसियत से विभाजन का दावा करते हैं – यही तर्क राज्य सरकार की हैसियत से दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए भी लागू होगा।		
(iii) आदेश 21 नियम 97 से 101 व्य.प्र.सं. के अधीन जाँच – विस्तार।	218	314
Section 89 – See section 16 of the Court Fees Act, 1870.		
धारा 89 – देखें न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16।	133	187
Section 89 – See section 16 of the Court Fees Act, 1870.		
धारा 89 – देखें न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16।	173	242
Section 96 and Order 9 Rule 13 – Ex parte decree – Maintainability of appeal		
धारा 96 और आदेश 9 नियम 13 – एकपक्षीय आज्ञाप्ती – अपील की प्रचलनीलता	4	5
Sections 96 and 100 – (i) Civil appeal filed against findings in the judgment – Not maintainable as it lies only against the decree.		
(ii) Multiple civil appeals – Arising from a single judgment – Appellate Court is bound to decide all such appeals by a common judgment.		
धाराएं 96 एवं 100 – (i) निर्णय में निष्कर्ष के विरुद्ध प्रस्तुत सिविल अपील – पोषणीय नहीं क्योंकि अपील केवल डिक्री के विरुद्ध की जा सकती है।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) एकाधिक सिविल अपीलें – एकल निर्णय से उत्पन्न – अपील न्यायालय ऐसी सभी अपीलों को एक ही निर्णय द्वारा विनिश्चय करने हेतु बाध्य है ।	80	118
Section 96 (2) and Order 9 Rule 13 – (i) <i>Ex parte</i> decree of divorce – Appeal filed on the ground that the matter has been swiftly decided by the Family Court – No ground for appeal.		
(ii) Appeal u/s 96 (2) of CPC against <i>ex parte</i> decree of divorce – Finding given on merit or on jurisdiction of Court below, may be challenged.		
(iii) Setting aside <i>ex parte</i> decree – Recourse to special procedure under Order 9 Rule 13 CPC is available.		
धारा 96 (2) आदेश 9 नियम 13 – (i) विवाह विच्छेद की एकपक्षीय आज्ञाप्ति – कुटुम्ब न्यायालय द्वारा तीव्र गति से प्रकरण के निराकरण के आधार पर अपील संस्थित – अपील का आधार नहीं ।		
(ii) एकपक्षीय विवाह विच्छेद आज्ञाप्ति के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(2) में अपील – गुण-दोष पर अथवा विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में आक्षेप अनुज्ञेय ।		
(iii) एकपक्षीय विवाह विच्छेद आज्ञाप्ति को अपास्त कराना – सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 की विशेष प्रक्रिया उपलब्ध ।	72	108
Section 100 – (i) Admission of title – Effect – In absence of a deed of conveyance, duly stamped and registered as required by law, no right, title or interest in immovable property can be transferred by mere admission of the parties.		
(ii) Rights of possession-holder – Plaintiff can on strength of his possession resist interference from persons who have no better title than himself to the suit property.		
धारा 100 – (i) स्वत्व की स्वीकृति – प्रभाव – विधि अनुसार स्टांपित एवं पंजीकृत, विक्रय पत्र के अभाव में, केवल पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर अचल संपत्ति में हित, स्वत्व या अधिकार अंतरित नहीं हो सकते ।		
(ii) आधिपत्यधारी के अधिकार – वादी आधिपत्य के बल पर ऐसे अन्य व्यक्ति जिसके पास उससे अच्छा स्वत्व नहीं है, को विवादित संपत्ति पर किये जा रहे हस्तक्षेप को रोक सकता है ।	128	181
Section 100 – See section 12 (1) (a), (f) and (g) of the Accommodation Control Act, 1961 (M.P.)		
धारा 100 – देखें स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.) की धारा 12 (1) (क), (च) और (छ) ।	123	175

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 104, Order 9 Rule 13 and Order 43 Rule 1 (d) – <i>Ex parte</i> decree – On refusal under Order 9 Rule 13 CPC, regular first appeal is available under Order 43 Rule 1(d).		
धारा 104, आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 43 नियम 1 (घ) – एकपक्षीय डिक्री – आदेश 9 नियम 13 संहिता के आवेदन के नामंजूर किये जाने की दशा में, नियमितप्रथम अपील आदेश 43 नियम 1 (घ) संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है।	40	58
Section 114 and Order 47 Rule 1 and 9 – Review – Whether review of review petition is allowed? Held, No		
धारा 114 और आदेश 47 नियम 1 एवं 9 – पुनर्विलोकन – क्या पुनर्विलोकन याचिका की पुनर्विलोकन की अनुमति है? अवधारित, नहीं	5	5
Section 148 – See section 148 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 148 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 28।	209	299
Section 151 and Order 7 Rule 11 & Order 9 Rule 4 – Scope of Section 151 CPC – Can suit be dismissed under Order 7 Rule 11 of CPC for non-payment of requisite Court fees?		
धारा 151 एवं आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 9 नियम 4 – धारा 151 सीपीसी का विस्तार – क्या आवश्यक न्याय शुल्क अदा न किये जाने पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गतवाद खारिज किया जा सकता है?	6	6
Order 1 Rule 10 – Application by defendant to add subsequent purchaser as party – Whether such application maintainable under Order 1 Rule 10? Held, No.		
आदेश 1 नियम 10 – प्रतिवादी द्वारा पक्षकार के रूप में पश्चातवर्ती क्रेताओं को संयोजित करने के लिए आवेदन – क्या ऐसा आवेदन आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रचलन योग्य है? अवधारित, नहीं।	7	6
Order 1 Rule 10 – Necessary and proper party – Held, third party can be joined only if there is a possibility to suffer any injury due to adjudication of the suit.		
आदेश 1 नियम 10 – आवश्यक और उचित पक्षकार – अवधारित, तृतीय पक्षकार केवल तभी सम्मिलित हो सकता है जब वाद के निर्णय के कारण उसे कोई क्षति पहुँचने की संभावना हो।	169	235
Order 2 Rule 2 and Order 6 Rule 17 – Principle of constructive <i>res judicata</i> – Applicability.		
आदेश 2 नियम 2 और आदेश 6 नियम 17 – आन्वयिकप्रांड, न्याय का सिद्धांत – प्रयोज्यता।	8 (i)	7

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

- Order 6 Rule 2** – (i) Deposition in lieu of principal party – Effect of.
(ii) Admission – Effect of admission of a party in the proceedings.
(iii) Non-examination of party – Adverse inference can be drawn against such party that they have no case.

- आदेश 6 नियम 2** – (i) मुख्य पक्षकार के स्थान पर अभिसाक्ष्य – प्रभाव ।
(ii) स्वीकृति – कार्यवाही में किसी पक्षकार के अभिवचन या मौखिक रूप से स्वीकृति का प्रभाव ।
(iii) पक्षकार का परीक्षण न कराया जाना – ऐसे पक्षकार के विरुद्ध यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका कोई मामला नहीं है ।

81 119

- Order 6 Rule 17 and Order 8 Rule 1** – (i) Amendment in written statement – By way of amendment, defendant submitted a counter-claim and virtually withdrew the admission of execution of sale deed and receipt of sale consideration – Amendment cannot be brought on record.

- (ii) Document – If the proposed amendment application has been declined, document filed in support of such application cannot be taken on record.

- आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 8 नियम 1** – (i) लिखित कथन में संशोधन – संशोधन के माध्यम से प्रतिवादी ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर विक्रय विलेख के निष्पादन और विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति की स्वीकृति वापिस ले ली – संशोधन अभिलेख पर नहीं लाया जा सकता ।

- (ii) दस्तावेज – यदि प्रस्तावित संशोधन आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है तब ऐसे आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता ।

219 316

- Order 6 Rule 17 and Order 8 Rule 1** – Whether the question of a person being the sole heir, can be determined at first appellate stage?

- आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 8 नियम 1** – क्या प्रथम अपील के स्तर पर इस बात का निर्धारण कि संबंधित व्यक्ति एक मात्र उत्तराधिकारी है या नहीं किया जा सकता है?

9 10

- Order 7 Rule 11** – Fraud – Mere pleading of fraud is not enough.

- आदेश 7 नियम 11** – कपट – वाद में केवल कपट किये जाने का अभिवचन करना पर्याप्त नहीं है ।

83 (i) 123

- Order 7 Rule 11** – Rejection of plaint – Non-disclosure of cause of action – Failure to demonstrate clear right to claim relief – Mere possibility that a right may be infringed without any legitimate basis for that right would not disclose a cause of action – Plaint can be rejected.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
आदेश 7 नियम 11 – वादपत्र नामंजूर किया जाना – वाद कारण प्रकट न किया जाना – अनुतोष प्राप्त करने के स्पष्ट अधिकार को प्रदर्शित करने में विफलता – बिना किसी विधिसंगत आधार के केवल इस बात की संभावना कि किसी अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, वाद कारण को प्रकट नहीं करेगा – वादपत्र नामंजूर किया जा सकता है।	220	321
• Order 7 Rule 11 – (i) Rejection of plaint – Objection on limitation – Despite the fact that objection of limitation is mixed question of fact and law, if Court comes to the conclusion that on averment of plaint, suit is barred by limitation, plaint can be rejected. (ii) Application to reject plaint – Lengthier the application, there is a likelihood of being dismissed as it leads to arena of disputed question of facts.		
आदेश 7 नियम 11 – (i) वादपत्र नामंजूर किया जाना – परिसीमा पर आक्षेप – इस तथ्य के बावजूद कि परिसीमा का आक्षेप विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादपत्र के प्रकथन पर वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है, वादपत्र नामंजूर किया जा सकता है। (ii) वादपत्र नामंजूर करने हेतु आवेदन – आवेदन के विस्तृत होने पर तथ्यों के विवादित प्रश्न उद्भूत हो जाने से इसके खारिज होने की संभावना होगी।	221	323
Order 7 Rule 11 and Order 39 Rules 1 & 2 – See sections 6, 7 and 12-A of the Commercial Courts Act, 2015.		
आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 39 नियम 1 और 2 – देखें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धाराएं 6, 7 एवं 12-क।	82	121
Order 9 Rules 9 & 13 and sections 141 & 151 – (i) Dismissal of application – Concurrent remedies. (ii) Dismissal of application – Restoration.		
आदेश 9 नियम 9 और 13 एवं धाराएं 141 एवं 151 – (i) आवेदन का निरस्त किया जाना – समवर्ती उपचार। (ii) आवेदन का निरस्त किया जाना – प्रत्यावर्तन।	170	236
Order 14 Rule 5 – (i) Additional issue – Parties can plead inconsistent or alternative pleas but not to the extent of being mutually destructive to each other. (ii) Meaning of the expressions ‘alternative’ and ‘inconsistent’ explained.		
आदेश 14 नियम 5 – (i) अतिरिक्त वाद प्रश्न – पक्षकार असंगत अथवा वैकल्पिक अभिवाक् इस सीमा तक ले सकते हैं कि वह परस्पर विरोधाभासी न हों।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) 'वैकल्पिक' एवं 'असंगत' शब्दों का अर्थ बताया गया।	129	182
Order 16 Rules 2 & 3 – (i) Summoning of relevant witness – Delay – In every case, an application to summon a relevant witness cannot be rejected on ground of delay – It depends on facts and circumstances of case as well as the necessity and relevance of witness sought to be introduced.		
(ii) Procedural law – Object – It is the brain child of law makers in order to advance the cause of justice and therefore, all the rules of procedure are made with the object to attain justice.		
आदेश 16 नियम 2 एवं 3 – (i) सुसंगत साक्षी को समन – विलंब – हर मामले में किसी सुसंगत साक्षी को समन करने के आवेदन को विलम्ब के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता – यह मामले के तथ्य और परिस्थितियों के साथ-साथ पेश किए जाने वाले साक्षी की आवश्यकता और सुसंगतता पर निर्भर करता है।		
(ii) प्रक्रियात्मक विधि – उद्देश्य – यह न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विधि निर्माताओं के दिमाग की उपज है और इसलिए प्रक्रिया के सभी नियम न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिये बने हैं।	222	324
Order 21 Rules 32 & 34 – Execution – Breach of decree conditions		
आदेश 21 नियम 32 एवं 34 – निष्पादन-डिक्री की शर्तों का उल्लंघन।	10	11
Order 21 Rules 84, 85 & 90 – Execution proceedings – Sale of property by auction – Effect when deposit of 25% amount not made as per Order 21 Rule 84.		
आदेश 21 नियम 84, 85 और 90 – निष्पादन कार्यवाहियां – संपत्ति का नीलामी द्वारा विक्रय – आदेश 21 नियम 84 के अनुसार 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं किये जाने का प्रभाव।	84	125
Order 21 Rules 97 to 101 – Execution – Decree of possession – Order dismissing execution application on the ground that encroachers were not party to the suit and as decree was unexecutable, was set aside.		
आदेश 21 नियम 97 से 101 – निष्पादन – आधिपत्य की आज्ञाप्ति – निष्पादन आवेदन को इस आधार पर निरस्त करने का आदेश कि अतिक्रमणकारी को पक्षकार न बनाए जाने से आज्ञाप्ति निष्पादन योग्य नहीं, अपास्त किया गया।	223	325
Order 22 Rules 3 & 4 – Abatement of suit/appeal – Effect of Non-substitution of legal representatives after demise of some of the respondents during pendency of appeal.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
आदेश 22 नियम 3 एवं 4 – वाद/अपील का उपशमन – अपील के लंबित रहते हुये कुछ प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण की मृत्यु होने पर वैध प्रतिनिधियों की प्रतिस्थापना न किये जाने का प्रभाव।	41	60
Order 22 Rules 3, 4 & 11 and Order 43 Rule 1(r) – Legal representative – Effect of substitution of legal representatives in miscellaneous appeal and not in main suit.		
आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 11 एवं आदेश 43 नियम 1(द) – विधिक प्रतिनिधि – विधिक प्रतिनिधी को केवल विविध अपील में जोडने एवं मूल वाद मे नहीं जोड़े जाने का प्रभाव।	*130	184
Order 22 Rules 3 & 5 – Legal representative – Application filed on the basis of Will – If any enquiry is required to be made, court can determine the question as provided under Order 22 Rule 5.		
आदेश 22 नियम 3 एवं 5 – विधिक प्रतिनिधि – वसीयत के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया – यदि कोई जाँच की जाना आवश्यक है तब न्यायालय आदेश 22 नियम 5 में उपबंधित रीति से प्रश्न का अवधारण कर सकती है।	42	61
Order 23 Rule 1-A and Order 1 Rule 10 – Transposition of defendant as plaintiff, when permissible?		
आदेश 23 नियम 1-क एवं आदेश 1 नियम 10 – प्रतिवादी का वादी के रूप में प्रतिस्थापन, कब अनुमत?	171	239
Order 23 Rule 1 (3) (b) – Withdrawal of suit along with permission to file fresh suit – Whether failure to make necessary averments in plaint amounts to “sufficient grounds” ?		
आदेश 23 नियम 1 (3) (ख) – नवीन वाद संस्थित करने की अनुमति सहित वाद का प्रत्याहरण – क्या वाद में आवश्यक प्रकथन करने में विफलता “पर्याप्त आधार” की परिधि में आता है?	85	127
Order 38 Rule 5 – See section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
आदेश 38 नियम 5 – देखें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9।	2	3
Order 39 Rules 1 & 2 – Dispute relating to identity of land – How to address the discrepancy?		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – भूमि की पहचान का विवाद – विसंगति को कैसे विचार में लिया जाए?	172	240
Order 39 Rules 1 & 2 – See section 29 (2) (c) of the Trade Marks Act, 1999.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – देखें व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 29 (2) (ग)।	163	226
Order 39 Rules 1 & 2 – Temporary injunction – Effect when possession of the suit property and essential elements are not established.		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – अस्थायी निषेधाज्ञा – वादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य एवं आवश्यक तत्व स्थापित नहीं होने पर प्रभाव।	43	62
Order 39 Rules 1 & 2 – Temporary injunction – <i>Prima facie</i> case – How to determine?		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – अस्थायी निषेधाज्ञा – प्रथम दृष्टया मामला – निर्धारण कैसे करें?	131	184
Order 39 Rule 2A – Disobedience of order of temporary injunction – Agreement of license for 5 years was executed by defendant after order of injunction – As order for maintaining <i>status quo</i> was not specific, it cannot be extended to the other things beyond prayer made in original application – No disobedience by defendant as suit property is not alienated.		
आदेश 39 नियम 2क – अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा – निषेधाज्ञा के आदेश के बाद प्रतिवादी द्वारा 5 साल के लिए लाइसेंस का करार निष्पादित किया गया – यथास्थिति बनाए रखने का आदेश विशिष्ट नहीं था, इसे मूल आवेदन में की गई प्रार्थना से परे अन्य सहायता तक विस्तारित नहीं किया जा सकता – प्रतिवादी द्वारा कोई अवज्ञा नहीं की गई क्योंकि विवादित संपत्ति का अंतरण नहीं किया गया।	224	327
Order 41 Rule 1 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963.		
आदेश 41 नियम 1 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34।	210	301
Order 41 Rule 3A – See section 5 of the Limitation Act, 1963.		
आदेश 41 नियम 3क – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5।	109	155
Order 41 Rule 22 – (i) Appeal against original decree – Remedies available to respondent – Right to file cross-objection and cross appeal exist – Respondent may also opt to fully support the original decree.		
(ii) Cross-objection – Duty – Appellate court must consider cross-objection in full while deciding appeal, as it has all the trapping of regular appeal.		
आदेश 41 नियम 22 – (i) मूल डिक्री के विरुद्ध अपील – प्रत्यर्थी को उपलब्ध उपचार – प्रत्याक्षेप एवं प्रति-अपील के अधिकार का होना – प्रत्यर्थी मूल डिक्री के पूर्ण समर्थन के विकल्प को भी चुन सकता है।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) प्रत्याक्षेप – कर्तव्य – अपीलीय न्यायालय को अपील का निराकरण करते समय प्रत्याक्षेप को पूर्ण रूप से विचार में अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उसमें नियमित अपील के सभी लक्षण होते हैं।	225	328
Order 41 Rules 23 to 29 – (i) Non-joinder of necessary party at appellate stage – Ample opportunity was available to the plaintiff at trial stage to rectify the defect, but failed to implead the necessary party – Seeking impleadment at appellate stage not permissible.		
(ii) Remand – Power and procedure.		
आदेश 41 नियम 23 से 29 – (i) अपीलीय स्तर पर आवश्यक पक्षकार का असंयोजन – त्रुटि सुधार के लिए विचारण के प्रक्रम पर वादी के पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध था, किन्तु आवश्यक पक्षकार को संयोजित करने में असफल रहा – अपील प्रक्रम पर पक्षकार संयोजित किये जाने की माँग करना अनुमत नहीं।		
(ii) प्रतिप्रेषण – शक्ति और प्रक्रिया।	226	330
Order 41 Rules 25 to 29 – (i) Additional documents taken on record – Appellate Court can take additional evidence or direct the trial court to record evidence and send it back – Remand after setting aside judgment and decree wholly unwarranted.		
(ii) Resettlement of issues – After framing of new issues, matter is to be referred to the trial court with direction to take additional evidence on newly framed issues and return with findings.		
आदेश 41 नियम 25 से 29 – (i) अतिरिक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिए गये – अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकती है या विचारण न्यायालय को साक्ष्य लेने और वापस भेजने के लिये निर्देशित कर सकती है – निर्णय तथा डिक्री को अपास्त कर प्रतिप्रेषण, पूर्ण रूप से अनुचित।		
(ii) विवाघकों की पुनर्स्थापना – नए विवाघक विरचित करने के बाद मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ भेजा जाना चाहिये था कि नए विरचित विवाघकों पर अतिरिक्त साक्ष्य लेकर निष्कर्षों के साथ वापस भेजे।		
	132	185
Order 41 Rule 27 – See sections 13(1)(i), 13(1)(i-a) and 13(1)(i-b) of the Hindu Marriage Act, 1955.		
आदेश 41 नियम 27 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धाराएं 13(1)(i), 13(1)(i-क) एवं 13(1)(i-ख)।	101	145
Order 43 Rule 1 (r) and Order 39 Rules 1 & 2 – Interim injunction – Restrictions on power of Appellate Court.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
आदेश 43 नियम 1 (द) एवं आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – अंतरिम निषेधाज्ञा – अपीलीय न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिबंध।	44	63

COMMERCIAL COURTS ACT, 2015

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

Sections 3, 3-A, 3 (1a), 10, 15 and 21 – (i) Commercial Courts – Whether all matters under Arbitration and Conciliation Act, 1996 other than international commercial arbitration can be heard by designated Commercial Court/Judge below the rank of Principal Civil Court in the District? Held, Yes.

(ii) Contradictory/divergent provisions in the statutes – Act of 2015 will have overriding effect.

धाराएं 3, 3-क, 3 (1क), 10, 15 एवं 21 – (i) वाणिज्यिक न्यायालय – क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मामलों के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों की सुनवाई मनोनीत वाणिज्यिक न्यायालय/न्यायाधीश जो कि जिले में प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न पद के हैं, की जा सकती है? अवधारित, हाँ।

(ii) अधिनियमों में विरोधाभासपूर्ण/भिन्न प्रावधान – अधिनियम, 2015 का अधिभावी प्रभाव रहेगा।

86 128

Sections 6, 7 and 12A – (i) Rejection of plaint – Court has to take into account the averments and documents meticulously to decide whether cause of action has arisen in its jurisdiction.

(ii) Pre-institution mediation – Pre-condition only in a class of suits.

धाराएं 6, 7 और 12क – (i) वाद का नामंजूर किया जाना – न्यायालय को सावधानी से अभिकथनों एवं दस्तावेजों पर विचार कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वादकारण उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है या नहीं।

(ii) संस्थापन पूर्व मध्यस्थता – केवल कुछ श्रेणी के वादों की एक पूर्ववर्ती शर्त है।

82 121

Section 12A – (i) Commercial suit – Whether the statutory pre-litigation mediation contemplated u/s 12A of the Act, 2015 is mandatory? Held, Yes.

(ii) Commercial suit – Settlement to be treated as an award u/s 30(4) of the Act, 1996.

धारा 12क – (i) वाणिज्यिक वाद – क्या अधिनियम, 2015 में धारा 12अ के अंतर्गत प्रावधानित प्रीलिटीगेशन मध्यस्थता आज्ञापक प्रावधान है? अभिनिर्धारित, हाँ

(ii) वाणिज्यिकवाद – समझौते को अधिनियम, 1996 की धारा 30(4) के अंतर्गत पंचाट माना जायेगा।

11 12

CONSTITUTION OF INDIA

भारत का संविधान

Article 21 – See sections 41, 41A, 167(2), 170, 437 and 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.

अनुच्छेद 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 41, 41क, 167(2), 170, 437 एवं 439 ।

13

15

CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971

Section 2 (b) – (i) Civil contempt – “Undertaking given to the court” and “consent order” or “order passed on compromise petition” – Distinction explained.

(ii) Contempt of court – Undertaking given by appellant that disputed property shall not be transferred during the pendency of suit – Despite the undertaking, disputed property was sold – Act falls within the ambit of ‘wilful disobedience’ – Meaning explained.

(iii) Civil contempt – Contempt is between the court and the contemnor – Third party cannot claim himself to be a necessary party.

धारा 2 (ख) – (i) सिविल अवमानना – “न्यायालय को वचन देना” एवं सहमति आदेश अथवा राजीनामा आवेदन पर आदेश।

(ii) न्यायालय की अवमानना – अपीलार्थी ने न्यायालय में यह वचन दिया कि वह विवादित संपत्ति वाद लंबन के दौरान अंतरित नहीं करेगा – ऐसे वचन के उपरांत भी विवादित संपत्ति का विक्रय कर दिया गया – आचरण ‘जानबूझकर की गई अवज्ञा’ की श्रेणी में आता है – अर्थ समझाया गया।

(iii) सिविल अवमानना – अवमानना की कार्यवाही न्यायालय एवं अवमाननाकारी के मध्य की है – तृतीय पक्ष स्वयं के आवश्यक पक्षकार होने का दावा नहीं कर सकता।

227

333

Section 12 – Contempt of Court – Disobedience of order of superior Court – When amounts to contempt?

धारा 12 – न्यायालय की अवमानना – वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवज्ञा – कब अवमानना के तुल्य होगी ?

87

129

CONTRACT ACT, 1872

संविदा अधिनियम, 1872

Section 74 – See sections 9 and 22 of the Specific Relief Act, 1963.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 74 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 9 एवं 22।	120	171

COURT FEES ACT, 1870

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870

Section 16 – Compromise – Whether court fees can be refunded if out of court settlement takes place? Held, Yes.

धारा 16 – समझौता – क्या न्यायालय के बाहर समझौता होने की स्थिति में भी न्यायालय शुल्क वापस किया जा सकता है? अवधारित, हाँ **173** **242**

Section 16 – Refund of court fees – Even if the matter is settled outside the Court by the parties without invoking provisions of section 89 CPC, they are entitled to the refund of full court fees u/s 16 of the Act.

धारा 16 – न्यायशुल्क की वापसी – यदि पक्षकारों द्वारा धारा 89 सीपीसी के प्रावधान का आह्वान किये बिना न्यायालय के बाहर मामला सुलझा लिया है तो भी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सम्पूर्ण न्यायालय शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। **133** **187**

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

Sections 41 and 439 – (i) Interim bail – Where multiple FIRs were filed against the accused on account of the tweets put out by him.

(ii) Arrest – Power must be exercised cautiously.

धाराएं 41 एवं 439 (i) अंतरिम जमानत—जहां अभियुक्त द्वारा किए गए ट्वीट्स के फलस्वरूप उसके विरुद्ध कई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

(ii) गिरफ्तारी—शक्ति का सतर्कता से प्रयोग किया जाना चाहिए।

12 **14**

Sections 41, 41A, 167(2), 170, 437 and 439 – (i) Arrest – Whether arrest in cognizable offence mandatory? Held, No.

(ii) Bail – Meaning of.

(iii) Compliance of section 436A mandatory.

(iv) Bail applications – To be disposed of within two weeks and anticipatory bail within six weeks.

धाराएं 41, 41क, 167(2), 170, 437, 439 – (i) गिरफ्तारी – क्या संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी अनिवार्य है? अवधारित, नहीं।

(ii) जमानत – आशय।

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(iii) धारा 436क का अनुपालन अनिवार्य।		
(iv) जमानत आवेदन – दो सप्ताह के भीतर एवं अग्रिम जमानत आवेदन छः सप्ताह के भीतर निराकृत किये जाने चाहिए।	13	15
Sections 53, 164-A (2), 167 (2) and 173 (2) (h) – Default bail – Non-filing of FSL report or DNA report along with chargesheet – Not a ground for bail.		
धाराएं 53, 164-क (2), 167 (2) एवं 173 (2) (ज) – व्यतिक्रम जमानत – अभियोग-पत्र के साथ एफ.एस.एल. या डी.एन.ए. प्रतिवेदन का प्रस्तुत न किया जाना – जमानत का आधार नहीं।	88	131
Sections 54A and 162 – Test Identification Parade – Whether accused can refuse to participate in test identification parade? Held, No.		
धाराएं 54क एवं 162 – शिनाख्त परीक्षण परेड – क्या अभियुक्त शिनाख्त परीक्षण परेड में सम्मिलित होने से इंकार कर सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।	237 (i)	359
Sections 91 and 482 – See section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.		
धाराएं 91 एवं 482 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138।	159	223
Sections 110, 111 and 116 (3) – When can order of interim bond for maintaining peace and good behaviour can be passed?		
धाराएं 110, 111 एवं 116 (3) – शांति और अच्छा आचरण बनाये रखने हेतु अंतरिम बंधपत्र का आदेश कब पारित किया जा सकता है?	134	189
Section 125 – (i) Maintenance – Issue of overlapping jurisdiction addressed.		
(ii) Parties to the application are required to file affidavit of disclosure of assets as mentioned in Enclosures I, II and III of the judgment in all maintenance proceedings.		
(iii) Factors to be considered for determining quantum, enumerated.		
(iv) Grant of maintenance – Period when it can be granted – Maintenance to be awarded from the date of filing of application		
(v) Execution – Order of maintenance may be enforced like a decree of civil court.		
धारा 125 – (i) भरण पोषण – क्षेत्राधिकार के अतिव्यापन होने का विवाद संबोधित।		
(ii) आवेदन के पक्षकारों को निर्णय में दिये गये प्रारूप I, II एवं III के अनुसार भरण पोषण की समस्त कार्यवाहियों में शपथ-पत्र पर संपत्ति का प्रकटीकरण करना आवश्यक है।		
(iii) भरण पोषण के निर्धारण हेतु विचार योग्य कारक बताये गये।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(iv) भरण पोषण कब से देय होगा? भरण पोषण आवेदन प्रस्तुति दिनांक से देय होगा।		
(v) निष्पादन – भरण पोषण के आदेश का निष्पादन व्यवहार न्यायालय की डिक्री के समान हो सकेगा।	45	64
Section 154 – Murder – Ante-timing of FIR – Interpolation in the time of lodging of FIR – Chick FIR sent with 4 days delay to the Court – Such infirmities casts doubt on authenticity of FIR.		
धारा 154 – हत्या – समय पूर्व एफ.आई.आर. – एफ.आई.आर. के दायर होने के समय में छेड़छाड़ – चिक एफ.आई.आर. 4 दिन के विलंब से न्यायालय को प्रेषित की गई – ऐसी कमियां एफ.आई.आर. की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करती हैं।	228 (i)	335
Section 154 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 154 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	14	20
Sections 154, 173, 156 (3) and 327 – (i) Complaint – Power u/s 156(3) CrPC in a sexual harassment case.		
(ii) Police Officer cannot decline registration of FIR on receipt of a complaint disclosing cognizable offence – If no offence is made out, can file a report u/s 173 CrPC.		
(iii) Duties and responsibilities of trial court – Enumerated.		
धाराएं 154, 173, 156 (3) एवं 327 – (i) शिकायत – यौन उत्पीड़न के मामले में धारा 156(3) दं.प्र.सं. की शक्ति।		
(ii) पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामले की शिकायत मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इंकार नहीं कर सकता – यदि अपराध बनना नहीं पाया जाता तो धारा 173 सी.आर.पी.सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।		
(iii) विचारण न्यायालय के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की गणना।	15	22
Sections 154 and 482 – See sections 406, 417, 418, 420, 467 and 468 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 154 एवं 482 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 406, 417, 418, 420, 467 एवं 468।	188	266
Section 156 – See sections 141 and 302 r/w/s 149 of the Indian Penal Code, 1860.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 156 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 141 एवं 302 सहपठित धारा 149।	142	199
Sections 156 (3) and 190 – (i) Information regarding commission of cognizable/non-cognizable offence furnished to police – No action taken – Four different independent remedies available to informant/victim to initiate prosecution.		
(ii) Application u/s 156 (3) CrPC – Maintainability – Can be directly filed before Magistrate without filing a criminal complaint u/s 190 CrPC.		
धाराएं 156 (3) एवं 190 – (i) संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध कारित किये जाने के संबंध में पुलिस को सूचना उपलब्ध कराई गई – कार्यवाही नहीं की गई – सूचनाकर्ता/पीड़ित के पास अभियोजन प्रारंभ करने के लिए चार भिन्न स्वतंत्र उपचार उपलब्ध हैं।		
(ii) धारा 156 (3) सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन – पोषणीयता – धारा 190 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत परिवाद दायर किये बिना सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।	229	338
Section 164 – (i) Non-examination of witness – Effect – Quality and not quantity of witnesses matter.		
(ii) Statement u/s 164 CrPC – Discretion of investigating officer.		
धारा 164 – (i) साक्षी का परीक्षण न कराया जाना – प्रभाव – साक्षीगण की गुणवत्ता का महत्व है न की संख्या का।		
(ii) धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन – अनुसंधान अधिकारी का विवेकाधिकार।	89	131
Section 164 – (i) Voluntary statement of accused – Extent and ambit.		
(ii) Confession – Investigating officer could facilitate recording of confession only by producing the accused before Magistrate – Deviation from that procedure not acceptable.		
धारा 164 – (i) आरोपी का स्वैच्छिक कथन – विस्तार एवं क्षेत्र।		
(ii) संस्वीकृति – अनुसंधान अधिकारी केवल अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर संस्वीकृति कथन करा सकता है – प्रक्रिया से विचलन स्वीकार योग्य नहीं।	135	190
Section 167 (2) – Police remand – Beyond period of first 15 days – When permissible?		
धारा 167 (2) – पुलिस अभिरक्षा – पहले 15 दिनों की अवधि के पश्चात् – कब अनुमत है?	174	243

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 173 and 207 – Copy of chargesheet – Can neither be said to be a ‘Public document’ nor fall under definition of section 4(1)(b) of the RTI Act.		
धाराएं 173 एवं 207 – अभियोग पत्र की प्रति – न तो ‘लोक दस्तावेज’ कही जा सकती है और न ही सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की परिभाषा के अंतर्गत आती है।	90	132
Sections 173 and 272 – Charge-sheet filed in English language – Prayer to supply it in language of the Court – No provision in the Code to file charge-sheet in the language of Court or furnishing translated copy of the charge-sheet – Where Code requires a particular act to be done in the language of the Court but is done in any other language – Such act will not vitiate the proceedings unless it has caused failure of justice – Accused duly represented by an advocate who understands English – No failure of justice caused – Request to supply translated copy of charge-sheet was disallowed.		
धाराएं 173 एवं 272 – अभियोगपत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत – उसे न्यायालय की भाषा (हिन्दी) में प्रदाय किये जाने की प्रार्थना की गई – संहिता में अभियोगपत्र को न्यायालय की भाषा में अथवा अभियोगपत्र के अनुवाद की प्रति प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं – जहां संहिता यह प्रावधानित करती है कि कोई कृत्य न्यायालय की भाषा में किया जाना चाहिए परन्तु वह किसी और भाषा में किया जाता है – ऐसा कृत्य कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा जब तक कि उसके कारण न्याय की विफलता न हुई हो – अभियुक्त का प्रतिनिधित्व ऐसे अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा था जो कि अंग्रेजी समझता था – न्याय की विफलता नहीं हुई – अभियोगपत्र के अनुवाद की प्रति देने का निवेदन अस्वीकार किया गया।	230	340
Section 173 (8) – Burden of proof – Motor vehicle accident claims must be decided on basis of preponderance of probabilities and not on the basis of proof beyond reasonable doubt.		
धारा 173 (8) – सबूत का भार – मोटर यान दुर्घटना दावों का निराकरण संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाना आवश्यक है, न कि युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किये जाने के आधार पर।	260 (ii)	405
Section 188 – Offence committed by Indian citizen outside India – Previous sanction not required at cognizance stage – However, trial cannot commence without sanction.		
धारा 188 – भारत के बाहर भारतीय नागरिक द्वारा अपराध – पूर्व मंजूरीसंज्ञान स्तर पर आवश्यक नहीं – यद्यपि मंजूरी के बिना विचारण प्रारंभ नहीं किया जा सकता।	46	67
Section 190 – See sections 18, 32 and 37(2) of the Society Registrkaran Adhiniyam, 1973 (M.P.).		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 190 – देखें सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (म.प्र.) की धाराएं 18, 32 एवं 37(2)।	208	298
Section 196 – Sanction for prosecution – No bar for registering FIR, investigation or submission of report by police.		
धारा 196 – अभियोजन की स्वीकृति/मंजूरी – प्राथमिकी दर्ज करने, जांच करने या पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं।	16	24
Sections 197 and 200 – Complaint – Absence of sanction – At the stage of charge, there is no necessity of previous sanction – Final view can be taken only after evidence is led during trial.		
धाराएं 197 एवं 200 – परिवाद – मंजूरी का अभाव – आरोप के स्तर पर पूर्व मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है – साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के बाद ही अंतिम विचार किया जा सकता है।	175	244
Sections 202 and 204 – See sections 405 and 406 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 202 एवं 204 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 405 एवं 406।	150	212
Section 204 – Issuance of process – Effect when no specific averments were made against the appellants in the complaint.		
धारा 204 – आदेशिका जारी की जाना – प्रभाव जहां परिवादमें अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिवचन नहीं किये गये।	47	67
Sections 211, 212, 213, 313 and 464 – (i) Improper charge – Effect – The decisive point would be whether failure of justice occasioned due to improper charge? Conviction or sentence would be invalid only if there was failure of justice as per section 464 CrPC.		
(ii) Examination of accused – Section 313 of the CrPC not an empty formality.		
(iii) Unlawful assembly – One out of five convicts have been acquitted, charge under section 148 or 149 IPC cannot be sustained against other four accused.		
धाराएं 211, 212, 213, 313 एवं 464 – (i) अनुचित आरोप – प्रभाव – निर्णायक बिन्दु यह होगा कि, क्या अनुचित आरोप के कारण न्याय की विफलता हुई ? धारा 464 द.प्र.सं. के आलोक में दोषसिद्धि व दण्डादेश केवल तभी अवैध होंगे जब न्याय विफल हुआ हो।		
(ii) अभियुक्त का परीक्षण – द.प्र.सं. की धारा 313 मात्र औपचारिकता नहीं है।		
(iii) विधि विरुद्ध जमाव – पांच में से एक की दोषमुक्ति होने पर धारा 148 या 149 भ.द.सं. के अंतर्गत अन्य चार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप स्थिर नहीं रखा जा सकता।	91	134

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 216 – See sections 363, 364 and 364-A of the Indian Penal Code, 860. धारा 216 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 363, 364 एवं 364-क।	187	263
Section 227 – Discharge – Appreciation of. धारा 227 – उन्मोचन-मूल्यांकन।	17	24
Sections 227 and 228 – See sections 107 and 306 of the Indian Penal Code 1860. धाराएं 227 एवं 228 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 107 एवं 306।	141	197
Sections 227 and 228 – See sections 107 and 306 of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 227 एवं 228 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 107 एवं 306।	184	259
Section 239 – Discharge – Effect when <i>prima facie</i> case not made out. धारा 239 – उन्मोचन – प्रभाव जहां प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता।	18	26
Sections 239 and 240 – (i) Framing of charge – Facts to be considered. (ii) Word “groundless”– Connotation of. (iii) “Known sources of income” – Meaning explained. धाराएं 239 एवं 240 – (i) आरोप विरचित करना – तथ्य जिनपर विचार किया जाना है। (ii) शब्द “निराधार”– अभिप्राय। (iii) “आय के ज्ञात स्रोत” – अर्थ समझाया गया।	48	68
Section 256 – See section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. धारा 256 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138।	113	160
Section 311 – Recalling of witness – Effect when no objection was taken at the time of recording of evidence. धारा 311 – साक्षी को पुनः आहुत करना – प्रभाव जहाँ अभियुक्त ने साक्ष्य लेखन करते समय आपत्ति नहीं ली।	176	245
Section 313 – Examination of accused – Accused allegedly offered false explanation – Conditions to use explanation as an additional link laid down. Injury – Accused had injuries at the time of arrest – It is the duty of prosecution to explain such injury – Failure to explain indicates innocence of accused.		

धारा 313 – अभियुक्त परीक्षण – अभियुक्त ने कथित रूप से असत्य स्पष्टीकरण दिया – ऐसे स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग हेतु शर्तें प्रतिपादित की गईं।

उपहति – अभियुक्त को गिरफ्तारी के समय शरीर पर उपहति कारित थी – अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी उपहति का स्पष्टीकरण दें – स्पष्टीकरण ना देना अभियुक्त के निर्दोष होने की ओर इंगित करता है।

59 (v) & (vi) 87

Section 313 – (i) Examination of accused – Every Criminal Court has to shoulder the onerous responsibility of scanning the evidence and preparing questionnaire – Principles summarized.

(ii) Written statement filed by accused u/s 313 (5) of the Code – Court marked it as an exhibit – Such statement has to be considered in the light of evidence led by prosecution and as a part of accused statement.

धारा 313 – (i) अभियुक्त परीक्षण – प्रत्येक दाण्डिक न्यायालय का यह गंभीर दायित्व है कि वह साक्ष्य का परिशीलन कर प्रश्नावली निर्मित करे – सिद्धांत सारांशित।

(ii) अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 313 (5) के अंतर्गत लिखित कथन प्रस्तुत किया गया – न्यायालय द्वारा उसे प्रदर्श अंकित किया गया – ऐसे कथन को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के प्रकाश में विचार में लेना चाहिए एवं इसे अभियुक्त परीक्षण का भाग माना जाएगा।

177 246

Section 319 – (i) Power to summon a person who is not an accused – Whether such power can be exercised after judgment has been rendered? Held, No.

(ii) Whether it is appropriate to consider the evidence of main case to summon additional accused in split up case? Held, No.

(iii) Guidelines to follow while exercising power under section 319 Cr.P.C issued.

(iv) Criminal trial – When can it be said that trial is concluded? Explained.

धारा 319 – (i) ऐसे व्यक्ति को आहूत करने की शक्ति जो अभियुक्त नहीं है – क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग निर्णय देने के बाद किया जा सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।

(ii) क्या विभाजित मामले हेतु अतिरिक्त अभियुक्त को आहूत करने के लिये मुख्य मामले के साक्ष्य पर विचार करना उचित है? अभिनिर्धारित, नहीं।

(iii) द.प्र.स. की धारा 319 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पालन कियेजाने वाले दिशा निर्देश जारी किये गये।

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(iv) आपराधिक विचारण – विचारण समाप्त हो गया है, ऐसा कब कहा जा सकता है? स्पष्ट किया गया।	50	71
Section 319 – Summoning of additional accused – Test – If available material, more or less, carries the same weightage and value as has been testified against those accused facing trial, power u/s 319 CrPC can be invoked.		
धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को आहूत करना – कसौटी – यदि उपलब्ध तथ्य, उनकी गुणवत्ता एवं महत्व अन्य विचारित अभियुक्तों के समान ही है – धारा 319 दं.प्र.सं. की शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।	136	191
Section 319 – Summoning of additional accused – When permissible?		
धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को समन – कब अनुमत?	231	342
Section 319 – Summoning of co-accused – Held, for adding a co-accused under section 319 of the Code, crucial test is that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction.		
धारा 319 – सहअभियुक्तगण को आहूत किया जाना – अभिनिर्धारित, संहिता की धारा 319 में सह अभियुक्त को संयोजित करने हेतु निर्णायक परीक्षण यह है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य, यदि अखंडित रह जाती है, तो दोषसिद्धि होगी।	49	70
Section 389 (1) – Suspension of conviction – Can be exercised only when exceptional hardship is shown.		
धारा 389 (1) – दोषसिद्धि का निलंबन – केवल तब प्रयोग में लाई जा सकती है जब आपवादिक कठिनाई दर्शायी जाए।	92	136
Section 389 (1) – Suspension of sentence – Endeavour on the part of the court should be to see whether the convict has fair chances of acquittal.		
धारा 389 (1) – दण्डादेश का निलंबन – न्यायालय की ओर से यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या दोषी के दोषमुक्त होने की उचित संभावना है।	178	248
Sections 408 and 439 (2) – (i) Transfer of case – Only because of an unfavourable order passed by the court, cannot be transferred to the other court.		
(ii) Cancellation of bail – Jurisdiction – When liberty has been misused by accused, application for cancellation of bail would lie before the same court – However, when bail has been granted erroneously without considering material on record, application would lie to superior court.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 408 एवं 439 (2) – (i) प्रकरण का अंतरण – केवल इसलिये कि न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है – प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित नहीं किया जा सकता।		
(ii) जमानत रद्द करना – क्षेत्राधिकार – जब अभियुक्त द्वारा आजादी का दुरुपयोग किया गया तब जमानत रद्द करने हेतु कार्यवाही उसी न्यायालय में होगी – परंतु जब जमानत अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार किये बिना त्रुटिपूर्ण रूप से दी गई तब आवेदन वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पोषणीय।	137	192
Sections 432, 433 and 433A – See sections 201, 302 and 376 of the Indian Penal Code, 1860 and sections 3, 27 and 106 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 432, 433 एवं 433क – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302 एवं 376 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 27 एवं 106।	56	82
Sections 437 and 439 – Bail order – Necessity to pass reasoned/speaking order.		
धाराएं 437 एवं 439 – जमानत आदेश – तार्किक आदेश पारित करने की आवश्यकता।	19	27
Section 438 – Anticipatory bail – Multiple accused – How to be considered?		
धारा 438 – अग्रिम जमानत – एक से अधिक अभियुक्त – कैसे विचार किया जाएगा ?	51	75
Section 438 – Pre-arrest bail – Discretion is required to be exercised with reference to material on record and parameters governing bail considerations.		
धारा 438 – गिरफ्तारी पूर्व जमानत – जमानत के संदर्भ में निर्धारित मानको एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधारों पर ही विवेकाधिकार का उपयोग करना चाहिये।	93	136
Section 438 – See sections 43(1), 44 (1) (a) and 44 (1) (c) r/w/s 4 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002		
धारा 438 – देखे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धाराएं 43 (1), 44 (1) (क) एवं 44 (1) (ग) सहपठित धारा 4।	118	168
Sections 438 and 439 – (i) Grant of anticipatory bail – Factors to be considered.		
(ii) Accused co-operated throughout investigation – Charge-sheet filed and there was no impediment on the part of the accused – Yet, the Court mechanically rejected the bail application and directed the accused to surrender and seek regular bail before the trial court – As the impugned order does not found to be sustainable, therefore set aside.		
धाराएं 438 एवं 439 – (i) अग्रिम जमानत प्रदान करना – विचारणीय तत्व।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) संपूर्ण अन्वेषण के दौरान अभियुक्त ने सहयोग किया – अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त की ओर से कोई अवरोध नहीं – फिर भी न्यायालय ने यंत्रवत रूप से जमानत आवेदन निरस्त किया और अभियुक्त को समर्पण करने और विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत की प्रार्थना करने के लिए निर्देशित किया – आलोच्य आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं पाया गया इसलिए अपास्त किया गया।	232	344
Section 438 (2) – (i) Anticipatory bail – Grant of – Condition(s) that may/may not be imposed.		
(ii) Whether complainant has ‘locus standi’ at the time of deciding anticipatory bail application? Held, No – Complainant has no right of audience unless the situation for compounding with permission of court arises.		
धारा 438 (2) – (i) अग्रिम जमानत – दिया जाना – शर्तें जो लगाई/नहीं लगाई जा सकती।		
(ii) क्या अग्रिम जमानत आवेदन निराकृत करते समय परिवादी को सुनवाई का अधिकार है? अभिनिर्धारित, नहीं – जब तक कि न्यायालय की अनुमति से शमन करने की स्थिति उत्पन्न न हो, परिवादी को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।	233	347
Section 439 – (i) Bail – Cancellation of – While granting bail, Court did not consider prosecutrix’s statement recorded u/s 161 and 164 of the Code, her testimony and allegations in the FIR – Order granting bail was set aside.		
(ii) Bail – Grant of – Guiding parameters laid down.		
धारा 439 – (i) जमानत – निरस्त किया जाना – जमानत देते समय न्यायालय ने अभियोक्त्री के संहिता की धारा 161 एवं 164 के कथन, उसकी अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आक्षेप पर विचार नहीं किया – जमानत देने का आदेश अपास्त किया गया।		
(ii) जमानत – स्वीकार किया जाना – मार्गदर्शक मापदण्ड बताए गए।	235	352
Section 439 – (i) Bail – Factors to be considered by a Court – Requirement of recording reasons – Principles reiterated.		
(ii) Bail – Cancellation of.		
धारा 439 – (i) जमानत – न्यायालय द्वारा विचार योग्य तत्व – कारण अभिलिखित किये जाने की आवश्यकता – सिद्धांत पुनरुद्धित।		
(ii) जमानत – निरस्त किया जाना।	234	350
Section 439 – Bail – The length of the period of custody or the fact that the charge-sheet has been filed and trial has commenced are by themselves not considerations that can be treated as persuasive grounds for granting bail to the accused.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 439 – जमानत – अभिरक्षा की लंबी अवधि अथवा यह तथ्य कि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है और विचारण आरंभ हो गया है, अभियुक्त को जमानत प्रदान करने के प्रेरक आधारों के रूप में नहीं माना जा सकता।	69	103
Section 439 (2) – (i) Cancellation of bail – When liberty granted to a citizen is being taken away it would call for interference only when the findings of trial court was either perverse or impossible.		
(ii) Consideration for bail – For rejecting the bail under Chapters V and VI of the Act, Court must believe that the allegations are <i>prima facie</i> true.		
धारा 439 (2) – (i) जमानत निरस्त करना – जब किसी नागरिक को दी गई स्वतंत्रता छीन ली जा रही हो, तो हस्तक्षेप केवल तभी किया जाएगा जब विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण या तो विकृत या असंभव हो।		
(ii) जमानत पर विचार – अधिनियम के अध्याय V एवं VI के अंतर्गत जमानत को अस्वीकार करने के लिए, न्यायालय को यह विश्वास करना आवश्यक है कि आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।	179	250
Sections 451 and 457 – Interim custody of vehicle – Effect of confiscation by Collector.		
धाराएं 451 एवं 457 – वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी – कलेक्टर द्वारा अधिग्रहण का प्रभाव।	138	193
Sections 451 and 457 – Intimation to Court – Magistrate has no jurisdiction to pass order of confiscation or release of vehicle, if intimation has been sent by the Collector.		
धाराएं 451 एवं 457 – न्यायालय को सूचना – यदि सूचना कलेक्टर द्वारा प्रेषित की गई है तो मजिस्ट्रेट को वाहन को अधिहरित करने या छोड़ने का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।	239 (ii)	364
Section 482 – See sections 120B 419, 420, 467, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860		
धारा 482 – देखें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएं 120बी, 419, 420, 467, 468 एवं 471।	27	42
Section 482 – See sections 138 and 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881.		
धारा 482 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138 एवं 142।	*200	283

CRIMINAL TRIAL:

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

आपराधिक विचारणः

– Circumstantial evidence – Proof – Suspicion cannot form basis of guilt of accused – Conditions required to be fulfilled before conviction of accused – Principles reiterated.

– परिस्थितिजन्य साक्ष्य – प्रमाण – संदेह अभियुक्त की दोषिता का आधार नहीं बन सकता – अभियुक्त की दोषसिद्धि के पूर्व पालन किये जाने हेतु शर्तें – सिद्धांतों को दोहराया गया।

244 (i) 374

– See section 164 of the Criminal Procedure Code, 1973.

– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164।

89

131

DIVORCE ACT, 1869

विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869

Section 10-A – Divorce by mutual consent – A secular concept – Discrimination not allowed on the ground of religion.

धारा 10-क – पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद – एक पंथनिरपेक्ष प्रावधान है – पंथ के आधार पर विभेद अनुमत नहीं।

94

137

DOWRY PROHIBITION ACT, 1961

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

Sections 3 and 4 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 3 एवं 4 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।

93

136

DRUGS AND COSMETICS ACT, 1940

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

Sections 27(d) and 34 – See section 204 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 27 (घ) एवं 34 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204।

47

67

ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

Section 7 – Power of investigation – Act does not authorize Sub-Inspector of Police to take action unless authorised for this purpose by Central or State Government – Proceeding initiated is unauthorised.

धारा 7 – अन्वेषण की शक्ति – अधिनियम पुलिस उप निरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत नहीं करता जब तक कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत न

Act/ Topic	Note No.	Page No.
किया गया हो – प्रारंभ की गई कार्यवाही अनधिकृत है।	96	140
EVIDENCE ACT, 1872		
साक्ष्य अधिनियम, 1872		
Section 3 – (i) Non-recovery of weapon – Effect. (ii) Contradiction, when material?		
धारा 3 – (i) हथियार का बरामद न होना – प्रभाव। (ii) विरोधाभास कब तात्विक है?	58	85
Section 3 – See section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 302 of the Indian Penal Code, 1860		
धारा 3 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302	228	335
Section 3 – See sections 300 Exception 4, 302 and 304 Part I of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 300 अपवाद 4, 302 एवं 304 भाग 1।	249	385
Section 3 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	105	149
Sections 3, 8, 24, 27, 101 and 106 – Last seen theory – Long time gap when deceased was last seen and when dead body was found – Autopsy report raising doubt that death might have occurred much later after deceased was last seen alive – No evidence as to when accused left the place of incidence and that no one else could have entered that place – Last seen circumstance becomes inconclusive.		
Recovery of weapon – Denied by accused – Not supported with serologist report to connect it with the crime – In such a situation recovery of weapon had very little value to sustain conviction on its own.		
Extra-judicial confession – Reliability – No evidence to demonstrate that accused had any prior relations with Panchayat member and that the accused hoped for or sought any help from him and therefore, made the confession to him – Weak type of evidence – Conviction on sole basis of extra-judicial confession is not ordinarily permissible.		

Credibility of witness – Prior enmity with accused – Not proved – Not having much relevance in cases based on circumstantial evidence which have settled mode of proof.

धाराएं 3, 8, 24, 27, 101 एवं 106 – अंतिम बार देखा गया का सिद्धांत – मृतक के अंतिम बार देखे जाने और मृत शरीर के मिलने के मध्य लंबा समय अंतराल – शव परीक्षण प्रतिवेदन संदेह उत्पन्न कर रहा है कि मृतक के अंतिम बार जीवित देखे जाने के बहुत बाद मृत्यु हुई होगी – कोई साक्ष्य नहीं कि अभियुक्त कब घटना स्थल को छोड़कर गया एवं यह कि अन्य कोई उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकता था – अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति अनिश्चायक हो जाती है।

आयुध की जब्ती – अभियुक्त द्वारा इंकार – अपराध से संबंध करने हेतु सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट से समर्थित नहीं – ऐसी स्थिति में आयुध की जब्ती अपने आप में दोषसिद्धि के लिए बहुत कम महत्व रखेगी।

न्यायिकेत्तर संस्वीकृति – विश्वसनीयता – यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं कि अभियुक्त के पंचायत सदस्य से कोई पूर्व संबंध थे और यह कि अभियुक्त ने उससे किसी सहायता की आशा की थी अथवा मांग की एवं इसलिए उसके समक्ष संस्वीकृति की – कमजोर प्रकृति की साक्ष्य – मात्र न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि सामान्यतः अनुज्ञात नहीं।

साक्षी की विश्वसनीयता – अभियुक्त से पूर्व रंजिश – प्रमाणित नहीं – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में अधिक सुसंगत नहीं, जिन्हें प्रमाणित करने का स्थापित तरीका हैं।

250 (ii) to (v) 387

Sections 3, 27 and 106 – Circumstantial evidence – Last seen theory – Five golden principles, named as *panchsheel* of proving a case based upon circumstantial evidence, reiterated.

Recovery of dead body – Extent of admission u/s 27 – Failure of accused to explain incriminating circumstances established against him – False explanation – When can be taken as an additional link in support of prosecution case? Explained.

धाराएं 3, 27 एवं 106 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले को प्रमाणित करने वाले पाँच स्वर्णिम सिद्धांत जिन्हें पंचशील कहा जाता है, दोहराये गये।

शव की बरामदगी – धारा 27 के अंतर्गत कथन की स्वीकारोक्ती की सीमा – आरोपी द्वारा संलिप्त करने वाले साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका – असत्य स्पष्टीकरण – अपीलार्थी के विरुद्ध कब अतिरिक्त कड़ी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? बताया गया।

56 (i) & (ii) 82

Sections 3 and 32 – (i) Oral dying declaration – When can be relied upon?

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) Examination of accused – Relevancy.		
धाराएं 3 एवं 32 – (i) मौखिक मृत्युकालिक कथन – कब विश्वास किया जा सकता है?		
(ii) अभियुक्त का परीक्षण – सुसंगति।	55	80
Sections 6 and 24 – Criminal trial – Circumstantial evidence – When conviction can be based? Principles restated.		
Extra-judicial confession – When extra-judicial confession can be relied upon – Circumstances clarified.		
धाराएं 6 और 24 – दांडिक विचारण – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – कब दोषसिद्धी आधारित की जा सकती है – सिद्धांत पुनः बताये गये।		
न्यायिकेत्तर संस्वीकृति – कब न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर विश्वास किया जा सकता है – परिस्थितियाँ स्पष्ट की गईं।	236 (i) & (ii)	355
Sections 8, 9 and 27 – Eye-witness identified the accused in the court during evidence – Challenge to the identification is not open to the accused who has denied participation in the identification parade.		
Disclosure statement – Accused made a statement regarding weapon of offence – Accused pointing to the police officer, the place where he had concealed the weapon, is relevant fact of his conduct u/s 8 of the Evidence Act.		
धाराएं 8, 9 एवं 27 – चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियुक्त को साक्ष्य के दौरान न्यायालय में पहचाना – पहचान कार्यवाही को वह अभियुक्त चुनौती नहीं दे सकता जिसने शिनाख्त परेड में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया था।		
प्रकटीकरण कथन – अभियुक्त ने अपराध के आयुध के संबंध में कथन किया – अभियुक्त का पुलिस अधिकारी को वह स्थान बताना जहाँ उसने आयुध छुपाया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उसके आचरण का सुसंगत तथ्य है।	237 (ii) & (iii)	359
Section 9 – Identification – Non-conduction of TIP – Effect of.		
धारा 9 – पहचान – पहचान परेड आयोजित नहीं किये जाने का प्रभाव।		
	20	28
Sections 9 and 118 – (i) Child witness – Evidence not to be rejected straight away – But needs careful evaluation and greater circumspection.		
(ii) Identification of accused in Court – Peculiar procedure adopted – When found unfair to accused?		
धाराएं 9 एवं 118 – (i) बाल साक्षी – साक्ष्य सीधे खारिज नहीं होगी – किंतु, सावधानीपूर्वक मूल्यांकन एवं अधिक एहतियात आवश्यक।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) न्यायालय में अभियुक्त की पहचान – विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई गई – कब अभियुक्त के लिए अन्यायपूर्ण पाई गई?	180	251
Sections 17 and 103 – Burden of proof – Registered sale deed whose execution is not in dispute, carries presumption that transaction was genuine – Only dispute regarding nature of transaction – Burden lies on defendant to establish that it did not reflect the true nature of transaction.		
धाराएं 17 और 103 – सबूत का भार – रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, जिसका निष्पादन विवादित नहीं है, के साथ उपधारणा रहती हैं कि अंतरण वास्तविक था – विवाद केवल संव्यवहार की प्रकृति से सम्बंधित – यह स्थापित करने का भार प्रतिवादी पर है कि वह संव्यवहार की वास्तविक प्रकृति को नहीं दर्शाता।	268	421
Sections 24 and 27 – Circumstantial evidence – Accused convicted for committing crime of murder – Tests to apply for conviction on the basis of circumstantial evidence laid down.		
Disclosure statement – Effect when Investigating Officer did not mention the exact words uttered by the accused in his oral evidence.		
Extra-judicial confession – Accused allegedly made an extra-judicial confession that he had brutally killed his wife – Extra-judicial confession can be relied only when it passes the test of credibility.		
Motive – Chain of circumstantial evidence snapped – Disclosure statement was not relied – Consideration of other circumstances such as motive not necessary.		
धाराएं 24 एवं 27 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अभियुक्त को हत्या कारित करने वाले अपराध में दोषसिद्ध किया गया – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने हेतु परीक्षण की विधि प्रतिपादित।		
प्रकटीकरण कथन – अनुसंधान अधिकारी द्वारा मौखिक साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा बोले गये शब्दों को नहीं बताये जाने का प्रभाव।		
न्यायिकेत्तर संस्वीकृति – अभियुक्त ने कथित रूप से न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी कि उसने अपनी पत्नि की निर्दयीता पूर्वक हत्या की थी – न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर तभी विश्वास किया जा सकता है जब वह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरे।		
हेतुक – परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला टूटगई – प्रकटीकरण कथन पर भी अविश्वास किया गया – अन्य तथ्यों जैसे किहेतुक पर विचार आवश्यक नहीं।	59 (i) to (iv)	87
Sections 27 and 30 – See section 164 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 27 एवं 30 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
	135	190
Section 32 – Dying declaration – When is there a need of medical certification? धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – कब चिकित्सीय प्रमाणन की आवश्यकता है?	181	252
Section 32 – See sections 84, 300, 302 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860 धारा 32 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 84, 300, 302, 498-क।	103	146
Section 45 – DNA test – Permissibility of – Conducting DNA test is violative of privacy of a person – Unless the Court reaches a conclusion that without DNA test it is not possible to come to the truth then only such permission should be granted. धारा 45 – डीएनए परीक्षण – अनुज्ञेयता – डीएनए परीक्षण किया जाना किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन है – जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि डीएनए परीक्षण के बिना सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है, केवल तभी ऐसे परीक्षण की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।	238	362
Section 45 – See sections 138 and 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881. धारा 45 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138 और 139।	70	104
Section 65 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963. धारा 65 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34।	37	53
Sections 65-A and 65-B – Electronic evidence – Analysis of CDR and method of proof – Principles summarised. धाराएं 65-क एवं 65-ख – इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य – सीडीआर का विश्लेषण और प्रमाणित करने की विधि – सिद्धांत सारांशित।	97	141
Section 65 (c) – (i) Admissibility of evidence when production of photocopy of document is produced without revealing its source. (ii) Photocopy of the instrument insufficiently stamped – Cannot be admitted as secondary evidence. (iii) Consideration of photocopy as secondary evidence – Requisites laid down. धारा 65 (ग) – (i) साक्ष्य की ग्राह्यता जहाँ दस्तावेज की छायाप्रति के स्रोत की जानकारी दिये बिना उसका प्रकटीकरण किया गया हो। (ii) अपर्याप्त रूप से स्टांम्पित लिखत की छायाप्रति – द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(iii) छायाप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में विचार में लिया जाना – वादी के लिये आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति का परीक्षण कराये, जिसने मूल की छायाप्रति तैयार की – कब और कहां छायाप्रति ली गई तथा यह कि छायाप्रति मूल की समान और सटीक प्रति है।	95	139
Section 68 – Burden of proving a Will shall always lie on the propounder.		
धारा 68 – वसीयत को प्रमाणित करने का भार हमेशा प्रतिपादक पर होता है।	76 (ii)	113
Section 74 – Public document – Merely because documents are filed in Court, they cannot be treated as public documents unless it is exhibited or it is an act of Court.		
धारा 74 – लोक दस्तावेज – जब तक प्रदर्श अंकित न हो या न्यायिक कार्य के अभिलेख के रूप में कोई दस्तावेज न हो, केवल इस आधार पर कि वह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उसे लोक दस्तावेज नहीं माना जा सकता।	*139	195
Section 74 – See sections 173 and 207 of Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 74 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 173 एवं 207।	90	132
Section 101 – (i) Execution of Will – Burden of proof – Lies on the party which substantially asserts the issue affirmatively.		
(ii) Proof of Will – Two rules enumerated.		
धारा 101 – (i) वसीयत का निष्पादन – सबूत का भार – उस पक्षकार पर होता है, जो विवाद्यक के सकारात्मक रूप का सारतः प्राख्यान करता है।		
(ii) वसीयत का साबित किया जाना – दो नियम प्रगणित।	98	141
Sections 101, 102 and 114 – See Order 6 Rule 2 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धाराएं 101, 102 एवं 114 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 6 नियम 2।	81	119
Section 106 – Circumstantial evidence – To invoke section 106 of Evidence Act, prosecution must prove that the victim was last seen in company of accused – In heinous offence, court is required to put material evidence under higher scrutiny.		
धारा 106 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का अवलम्ब लेने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि पीड़िता को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था – जघन्य अपराध में, न्यायालय द्वारा तात्त्विक साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना आवश्यक है।	253 (ii)	393

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 114 A – Rape – Misconception of fact – Distinction between false promise and breach of promise, explained.		
धारा 114 क – बलात्संग – तथ्य का भ्रम – मिथ्या वचन करने और वचन भंग करने में अंतर बताया गया ।	104	149
Section 115 – See section 8 (a) of the Hindu Succession Act, 1956.		
धारा 115 – देखें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 (क)।	140	195
Section 134 – (i) Defective investigation – When non-examination of a witness causes prejudice to the defence?		
(ii) Non-examination of material witness by I.O. and failure to seize weapon – Effect.		
धारा 134 – (i) दोषपूर्ण विवेचना – साक्षी का परीक्षण न होने से बचाव पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव कब पड़ता है ?		
(ii) विवेचक द्वारा तात्त्विक साक्षी को परीक्षित न किया जाना एवं आयुध जब्त करने में असफलता – प्रभाव ।	106	150
EXCISE ACT, 1915 (M.P.)		
आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.)		
Sections 47, 47A and 47D – Confiscation proceedings – Jurisdiction of Collector – Proceedings for confiscation of vehicle and trial have to proceed simultaneously – Collector can pass order of confiscation even if trial is pending before Criminal Court.		
धाराएं 47, 47-क एवं 47-घ – अधिहरण की कार्यवाही – कलेक्टर का क्षेत्राधिकार – वाहन के अधिहरण की कार्यवाही और विचारण एक साथ चलेंगे – कलेक्टर अधिहरण का आदेश पारित कर सकता है भले ही दण्डिक न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित हो ।	239 (i)	364
GOVANSH VADH PRATISHEDH ADHINIYAM, 2004 (M.P.)		
गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (म.प्र.)		
Sections 4, 6, 9 and 11 (5) – See sections 451 and 457 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 4, 6, 9 एवं 11 (5) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 451 एवं 457 ।	138	193
GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890		
संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 6 – See sections 6 and 13 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956		
धारा 6 – देखे हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धाराएं 6 एवं 13।	54	78

HINDU MARRIAGE ACT, 1955

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

Sections 5 (i), 11, 13(1) (i) (ia) and 23A – Suit for dissolution of marriage on ground of adultery and cruelty u/s 13 (1) (i) & (ia) of the Act – Counter-claim by wife u/s 23-A of the Act is maintainable to declare second marriage of her husband as illegal, *void-ab-initio* u/s 11 of the Act.

धाराएं 5 (i), 11, 13(1) (i) (िक) एवं 23क – जारकर्म एवं क्रूरता के व्यवहार के आधार पर अधिनियम की धारा 13 (1) (i) एवं (िक) के अंतर्गत विवाह विघटन हेतु वाद – प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अधिनियम की धारा – 11 के अधीन पति के दूसरे विवाह को अवैध, प्रारम्भ से शून्य घोषित कराने हेतु धारा 23क के अधीन प्रतिदावा पोषणीय।

52 75

Sections 9 and 13 – (i) Divorce on the ground of cruelty – Allegation about illicit relationship without any basis and prohibiting the in-laws to meet their grandson – Amounts to cruelty.

(ii) Subsequent events – When subsequent events and entire backdrop shows that it is not possible for the parties to live together, decree of divorce should be granted.

(iii) Permanent alimony – No application u/s 25 of the Act is made to the Court – Family Court cannot decide the aspect of alimony.

धाराएं 9 एवं 13 – (i) क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद – बिना किसी आधार के अवैध संबंधों आक्षेप लगाया जाना और ससुरालजन को उनके पोते से मिलने से रोकना – क्रूरता की श्रेणी में आता है।

(ii) पश्चात्वर्ती घटनाक्रम – जब पश्चात्वर्ती घटनाएं एवं संपूर्ण पृष्ठभूमि यह दर्शाती हो कि पक्षकारों का एकसाथ रहना संभव नहीं है, तब विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) स्थायी गुजारा भत्ता – अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं – कुटुम्ब न्यायालय गुजारा भत्ता के विषय में निर्णय नहीं कर सकता।

99 142

Section 13 (1A) – Irretrievable breakdown of marriage – Divorce on this ground is not a right but a discretion to be exercised with great caution.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 13 (1क) – विवाह का अपूर्णाय विघटन – इस आधार पर विवाह-विच्छेद एक अधिकार नहीं है किन्तु विवेकाधिकार है, जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ।	240	365
Sections 13 and 24 – Divorce proceeding – Duty of Court to ensure compliance of the maintenance order before passing any final order/judgment.		
धाराएं 13 एवं 24 – विवाह-विच्छेद कार्यवाही – न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह कोई भी अंतिम आदेश/निर्णय पारित करने से पूर्व उस भरण पोषण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।	100	144
Sections 13 (1)(i), 13 (1) (i-a) and 13 (1) (i-b) – Divorce – Ground of adultery – Essentials.		
धाराएं 13 (1)(i), 13 (1)(i-क) एवं 13 (1)(i-ख) – विवाह विच्छेद – जारता का आधार – आवश्यकताएँ।	101	145
Section 13-B (2) – See section 10-A of the Divorce Act, 1869.		
धारा 13-(ख) (2) – देखें विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10-क।	94	137
Section 13(1) (ia) – Decree of divorce – Effect when criminal complaints and prosecution lodged by wife found baseless.		
धारा 13(1) (iक) – विवाह विच्छेद की आज्ञाप्ति – पत्नी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक परिवाद एवं अभियोजन निराधार पाये जाने पर प्रभाव।	53	77
HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT, 1956		
हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956		
Sections 6 and 13 – (i) Custody of child – Provisions of both Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 and Guardians & Wards Act, 1890 are to be considered.		
(ii) Guiding principles – Reiterated.		
(iii) Custody of child – Factors to be considered		
धाराएं 6 एवं 13 – (i) अवयस्क की अभिरक्षा – हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 एवं संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 दोनों के प्रावधान को विचार में लिया जाएगा।		
(ii) मार्गदर्शक सिद्धांत – दोहराया गया ।		
(iii) अवयस्क की अभिरक्षा – विचार योग्य कारक।	54	78
HINDU SUCCESSION ACT, 1956		
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 2 (2) – Female belonging to Scheduled Tribe – Claim of share in compensation on the basis of survivorship – Compensation awarded for acquisition of ancestral land – Such claim may be in accordance with equity but not maintainable u/s 2 (2) of the Act – Not applicable on female members of Scheduled Tribes – Central Government directed to consider amendment.		
धारा 2 (2) – अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिला – उत्तरजीविता के आधार पर मुआवजे में हिस्सेदारी का दावा – मुआवजा पैतृक भूमि के अधिग्रहण के लिए दिया गया – ऐसा दावा साम्या के अनुरूप हो सकता है लेकिन अधिनियम की धारा 2(2) के अंतर्गत प्रचलनशील नहीं – अधिनियम अनुसूचित जनजाति की महिला पर लागू नहीं – केन्द्र सरकार को संशोधन पर विचार करने का निर्देश दिया गया।	102	145
Sections 6 and 8 – Division of share – Mitakshara co-parcenary property.		
धाराएं 6 एवं 8 – अंश का विभाजन – मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति।	241	369
Section 6 (5) – See section 110 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.)		
धारा 6 (5) – देखें भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 110	257	400
Section 8 – Hindu Law – Applicability when birth prior to the year 1956 is proved or undisputed.		
धारा 8 – हिन्दू विधि – प्रयोज्यता जहां वर्ष 1956 से पहले जन्म स्थापित या निर्विवाद हैं।	21	29
Section 8 (a) – (i) Suit for partition – Claim for share in property of grandfather who died intestate – Self-acquired property of grandfather – Pre-deceased father of the claimant did not have any right by birth – Father relinquished his right for some consideration – Claimants not entitled for share in grandfather's property.		
(ii) Doctrine of estoppel – When pre-deceased father relinquished his share in lieu of valuable consideration, claimants being the heirs of the deceased, are bound to the same extent.		
धारा 8 (क) – (i) विभाजन के लिए वाद – दादा की निर्वसीयत मृत्यु के बाद संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दावा – दादा की स्व अर्जित संपत्ति – दावेदार के पूर्व-मृत पिता के पास जन्म से अधिकार नहीं – पिता ने कुछ प्रतिफल के लिए अपने अधिकारों का अधित्याग किया – दावेदार दादा की संपत्ति में हिस्से का हकदार नहीं।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) विबंध का सिद्धांत – जब पूर्व मृत पिता के मूल्यवान प्रतिफल के बदले में अपना हिस्सा छोड़ दिया – दावेदार मृतक के उत्तराधिकारी होने के नाते उसी सीमा तक बाध्य होंगे।	140	195
Section 14 – Ownership – Disputed land given for maintenance to the plaintiff – Plaintiff becomes full owner of the land by virtue of Section 14 of the Act.		
धारा 14 – स्वामित्व – वादी को वादग्रस्त संपत्ति भरण-पोषण हेतु प्रदाय की गई – अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत वादी भूमि की पूर्ण भूमि-स्वामी बन जाती है।	182	257

INDIAN PENAL CODE, 1860

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

Section 34 – Common intention – Co-accused – As the presence of co-accused at the place of incident and participation in action has been established, it is clear that the co-accused shared the common intention to kill the deceased.

धारा 34 – सामान्य आशय – सह-अभियुक्त – घटनास्थल पर सह-अभियुक्त की उपस्थिति और कृत्य में सहभागिता स्थापित, अतः यह स्पष्ट है कि सह-अभियुक्त ने मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय साझा किया। **183** **258**

Section 34 – (i) Common intention – Meaning of the word “furtherance”

(ii) Common intention – Liability.

धारा 34 – (i) सामान्य आशय – शब्दांश ‘अग्रसरण में’ का अर्थ।

(ii) सामान्य आशय – दायित्व। **22** **31**

Sections 34 and 302 – See sections 3 and 32 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 34 एवं 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 32।

55 **80**

Sections 84, 300, 302 and 498-A – (i) Multiple dying declarations – When dying declarations are trustworthy?

(ii) Murder – Deceased succumbed to the furious behaviour of the accused – Case does not fall in the Fourth Exception.

धारा 84, 300, 302, 498-क – (i) एकाधिक मृत्युकालीन कथन – मृत्युकालीन कथन कब विश्वसनीय हैं ?

(ii) हत्या – अभियुक्त के उग्र व्यवहार के कारण मृतिका की मृत्यु हुई – प्रकरण चौथे अपवाद की परिधि में नहीं आता। **103** **146**

Sections 86, 300 and 302 – Murder – Intention and knowledge.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 86, 300 एवं 302 – हत्या – आशय एवं जानकारी।	23	35
Sections 90 and 375 – See section 114 A of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 90 एवं 375 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114क।		
	104	148
Sections 107 and 306 – Abetment to suicide – Essential ingredients discussed.		
धाराएं 107 एवं 306 – आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण – आवश्यक तत्व समझाये गये।		
	184	259
Sections 107 and 306 – Framing of charge – Abetment to suicide – Deceased was having legal remedy against harassment for repayment of loan, but instead of choosing legal remedy, ended his life thereby implicating the accused.		
धाराएं 107 एवं 306 – आरोप विरचित किया जाना – आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण – मृतक के पास उधार की राशि अदा न करने से होने वाले उत्प्रेरण से बचने का विधिक उपचार उपलब्ध था परन्तु उसके द्वारा ऐसा न करके अपने जीवन को समाप्त करने का चयन किया गया और अभियुक्त को आलिप्त किया।		
	141	197
Sections 120B, 419, 420, 467, 468 and 471 – Cognizance of offence where there is no <i>prima facie</i> evidence.		
धाराएं 120ख, 419, 420, 467, 468 और 471 – अपराध का संज्ञान जहां प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं।		
	27	42
Sections 141 and 302 r/w/s 149 – (i) Unlawful assembly – Five persons, whose names were mentioned in the FIR, were tried separately – Whether section 149 IPC attracted? Held, Yes.		
(ii) Unlawful assembly – Whether less than five persons can be convicted?		
(iii) Delay in filing FIR – Effect of – If the delay has been sufficiently and properly explained, no benefit of doubt should be given to the accused.		
धाराएं 141 एवं 302 सहपठित धारा 149 – (i) विधि विरुद्ध जमाव – प्रथम सूचना रिपोर्ट में पांच लोगों के नाम वर्णित थे और उनका अलग अलग विचारण किया जा रहा था – क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 आकर्षित होगी? अभिनिर्धारित, हाँ।		
(ii) विधि विरुद्ध जमाव – क्या पांच से कम लोगों की दोषसिद्धि की जा सकती है?		
(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब – प्रभाव – यदि देरी का पर्याप्त और उचित कारण स्पष्ट किया गया हो तो अभियुक्त को संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।		
	142	199

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 147, 323, 342, 504 and 506 Part-II – See sections 197 and 200 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 147, 323, 342, 504 एवं 506 भाग-II – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 197 एवं 200।	175	244
Sections 148, 300 Exception 4, 302, 304 Pt. II and 323 r/w/s 149 –		
(i) Criminal Trial – Sentencing process – Adequate sentence – Principle of proportionality should guide the sentencing process .		
(ii) Sentencing – Eight accused persons convicted for murder – Role played by each accused in the offence was indistinguishable – Huge disparity in the period of imprisonment served by the accused – All accused persons are sentenced to 5 years rigorous imprisonment.		
धाराएं 148, 300 अपवाद 4, 302, 304 भाग दो एवं 323 सहपठित 149 –		
(i) आपराधिक विचारण – दंडादेश प्रक्रिया – पर्याप्त दंडादेश – दंडादेश प्रक्रिया, आनुपातिकता के सिद्धांत से मार्गदर्शित होनी चाहिए।		
(ii) दंडादेश – आठ अभियुक्त व्यक्तियों को हत्या के लिए दोषसिद्ध किया गया – अपराध में प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका प्रभेद किये जाने योग्य नहीं थी – अभियुक्तगण द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि में अत्यधिक असमानता – सभी अभियुक्त व्यक्तियों को 5 वर्ष के कठिन कारावास से दण्डित किया गया।	242	371
Section 180 – Refusal from signing statement – Offence when constituted – Only where public servant is legally competent to obtain signature on the statement – Signature of person making the statement during investigation is not required u/s 162 CrPC – Offence not constituted.		
धारा 180 – कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार – अपराध कब गठित होगा – केवल वहीं जहां लोक सेवक कथन पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है – संहिता की धारा 162 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान कथन देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है – अपराध गठित नहीं।	243	373
Sections 201 and 302 – Allegation that appellant murdered his wife and disappeared the dead body by dumping it in the well – Circumstances connecting the appellant with the murder not proved beyond reasonable doubt – Investigating officer not examined – Rendered entire prosecution case doubtful – It is bounden duty of the courts to ensure that miscarriage of justice is avoided at all costs and the benefit of doubt, if any, be given to the accused.		
धाराएं 201 एवं 302 – अपीलार्थी पर अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंककर गायब करने का आरोप – अपीलार्थी को हत्या से संबद्ध करने		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
वाली परिस्थितियां युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं – अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया गया – पूरे अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाता है – न्यायालय का यह आवश्यक कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि हर कीमत पर न्याय की विफलता को रोका जाए और संदेह का लाभ, यदि कोई हो, तो अभियुक्त को दिया जाए।	244 (ii)	374
Sections 201 and 302 – Circumstantial evidence – Complete chain must be established meticulously with forensic clarity.		
धाराएं 201 एवं 302 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – पूरी श्रृंखला को सावधानीपूर्वक और न्यायक-विज्ञान की स्पष्टता के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।	143	201
Sections 201 and 302 – Murder – Circumstantial evidence – Dead body of victim exhumed after several months – No medical proof of homicidal death but chain of circumstances fully established – Conviction held proper.		
धाराएं 201 एवं 302 – हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – पीड़ित का शव कब्र से कई माह बाद निकाला गया – मानव वध का कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं – पोस्टमॉर्टम में मृत्यु के कारण का पता नहीं चल सका परन्तु परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित – दोषसिद्धि उचित।	144	202
Sections 201, 302 and 364 – Circumstantial evidence – When sole reliance on the “last seen” circumstance to convict accused is not justified.		
धाराएं 201, 302 एवं 364 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – कब मात्र “अंतिम बार देखे जाने” की परिस्थिति पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं।	185	260
Sections 201, 302 and 376 – Death penalty – Permissibility of awarding capital punishment in case of conviction based on circumstantial evidence.		
धाराएं 201, 302 एवं 376 – मृत्यु दण्ड – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में मृत्युदण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुज्ञेयता।	56 (iii)	82
Sections 299 and 300 – Murder – Significance of the word “likely” – Intention to cause death – Can be gathered from combination of a few or several circumstances – Explained.		
धाराएं 299 एवं 300 – हत्या– ‘संभाव्य’ शब्द का महत्व – मृत्यु कारित करने का आशय – अन्य परिस्थितियों के साथ कुछ या अनेक के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है – समझाया गया।	24	36
Sections 300, 302 and 304 Part 1 and Part 2 – (i) Culpable homicide and murder – Distinction – Intention or knowledge to kill – How to determine? Case falls		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

under which clause of Section 299 and whether Part 1 or Part 2 of section 304 would apply? Test to determine – Principles reiterated and law summarized.

(ii) Culpable homicide not amounting to murder – On the day of the incident, the father and son were working in their agricultural field – They wanted to transport the crop however, the deceased did not allow the driver of the lorry to use the disputed pathway – This led to a verbal altercation between the accused and the deceased – After quite some time the accused hit a blow on the head of the deceased with weed axe resulting in his death – In such circumstances, the case does not fall within clause thirdly of Section 300 of the IPC – Conviction of accused u/s 304 Part I of the IPC is altered to one u/s 304 Part II of the IPC.

धाराएं 300, 302 एवं 304 भाग 1 एवं भाग 2 – (i) आपराधिक मानववध और हत्या – विभेद – मृत्यु कारित करने का आशय या ज्ञान – कैसे विनिश्चय किया जाए? प्रकरण धारा 299 के किस खण्ड के अन्तर्गत आता है और क्या धारा 304 का भाग 1 या भाग 2 प्रयोज्य होगा? विनिश्चय की कसौटी, सिद्धांत पुनरुद्धित और विधि सारांशित की गई।

(ii) हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध – घटना के दिन पिता और पुत्र अपनी कृषि भूमि पर कार्य कर रहे थे – वे अपनी फसल का परिवहन करना चाहते थे लेकिन मृतक ने वाहन के चालक को विवादित रास्ते का प्रयोग की अनुमति नहीं दी – इसके कारण अभियुक्त और मृतक के बीच मौखिक तकरार हुई – इसके काफी समय बाद अभियुक्त ने खरपतवार साफ करने वाली कुल्हाड़ी से मृतक के सिर पर आघात किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई – ऐसी परिस्थितियों में प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के खण्ड तीन के अंतर्गत नहीं आएगा – अभियुक्त की दोषसिद्धि धारा 304 भाग 1 से परिवर्तित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत की गई।

246

377

Section 300 Exception 1 – Murder – Grave and sudden provocation – Factors to be considered.

धारा 300 अपवाद 1 – हत्या – गंभीर और अचानक प्रकोपन – विचार में लिए जाने वाले तथ्य।

25

40

Sections 300 Exception 1, 302 and 304 Part I – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Possibility of the appellant causing death while being deprived of the power of self control, due to the provocation on account of the deceased not agreeing to pay money to daughter, cannot be ruled out – Case falls under Exception I of section 300 IPC – Conviction, therefore altered from section 302 to section 304 Part I of IPC.

धाराएं 300 अपवाद 1, 302 एवं 304 भाग-I – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध – इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक द्वारा पुत्री को राशि देने के लिए सहमत न होने से उत्पन्न हुए प्रकोपन के आवेश में आकर अभियुक्त ने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया हो और मृत्यु कारित की हो – प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है – परिणामस्वरूप दोषसिद्धि धारा 302 से परिवर्तित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग 1 में की गई।

248 384

Sections 300 Exception 4 and 302 – (i) When benefit of Exception 4 can be claimed? Essential ingredients – Sudden quarrel, absence of premeditation and the offender should not have taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner.

(ii) Sudden quarrel and absence of premeditation established – Appellant repeatedly gave seven brutal blows by axe on upper vital parts of the body of deceased – Taken undue advantage and acted in a cruel and unusual manner – Whether benefit of Exception 4 is available? Held, No, as appellant had caused injuries with the intention of causing death – Appellant rightly convicted u/s 302 IPC.

धाराएं 300 अपवाद 4 एवं 302 – (i) अपवाद 4 के लाभ का दावा कब किया जा सकता है? आवश्यक तत्व – अचानक झगड़ा, पूर्वचिन्तन का अभाव और अपराधी को असम्यक् फायदा नहीं उठाना चाहिए या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए।

(ii) अचानक झगड़ा और पूर्वचिन्तन का अभाव स्थापित – अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के ऊपरी मर्म हिस्सों पर बार-बार कुल्हाड़ी से सात क्रूर वार किए – उसने अनुचित लाभ उठाया और क्रूर और असामान्य तरीके से कार्य किया – क्या अपवाद 4 का लाभ उपलब्ध है? अभिनिर्धारित नहीं, क्योंकि अपीलार्थी ने मृत्यु कारित करने के आशय से चोट पहुंचाई है – अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत सही दोष सिद्ध किया गया।

245 375

Sections 300 Exception 4, 302 and 304 Part I – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Exception 4 to section 300 when attracted ?

धाराएं 300 अपवाद 4, 302 एवं 304 भाग-I – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध – धारा 300 का अपवाद 4 आकर्षित ?

249 385

Sections 300 and 304A – Culpable homicide or causing death by negligence – Culpable homicide not proved – However, accused found to be gross negligent in not keeping the change lever in safety position – Accused, therefore guilty of lesser offence punishable u/s 304 A of IPC.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 300 एवं 304क – आपराधिक मानववध या उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – आपराधिक मानववध प्रमाणित नहीं – तथापि अभियुक्त चैंज लीवर को सुरक्षित अवस्था में नहीं रखने पर घोर उपेक्षावान पाया गया – परिणामस्वरूप अपीलार्थी 304-क भारतीय दण्ड संहिता के लघुत्तर अपराध हेतु दोषी पाया गया।	247	382
Section 302 – (i) Identification parade – Value – If the accused are previously known to the witness, holding of identification parade has no value. (ii) Judgment – Basis of – To avoid miscarriage of justice, it should consist of reasons and appreciation of evidence but should not be based on the principle of preponderance of probability.		
धारा 302 – (i) शिनाख्त परेड – महत्व – यदि साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता है तब शिनाख्त परेड किया जाना अनुपयोगी है। (ii) निर्णय – आधार – न्याय के दुरुपयोग से बचने के लिये निर्णय में कारणों और साक्ष्य के मूल्यांकन को शामिल किया जाना चाहिए न कि अधिसंभावना की प्रबलता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।	145	203
Section 302 – Murder – Circumstantial evidence – Burden of proof – Primary burden is on prosecution to prove the prosecution case beyond reasonable doubt – Only thereafter question arises of placing the burden on accused to prove his innocence – Before proof of foundational facts, provision as contained in section 106 of Evidence Act cannot be made applicable.		
धारा 302 – हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – सबूत का भार – अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का प्राथमिक भार अभियोजन पर – केवल इसके उपरांत ही अभियुक्त पर उसकी निदोषिता प्रमाणित करने के भार का प्रश्न उत्पन्न होता है – आधारभूत तथ्यों के प्रमाणित होने के पूर्व, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में वर्णित प्रावधान प्रयोज्य नहीं किया जा सकता।	250 (i)	387
Section 302 – Murder – There can be conviction even on the basis of deposition of sole eye-witness.		
धारा 302 – हत्या – एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धी की जा सकती है।	57	84
Section 302 – Circumstantial evidence – When chain of circumstances is complete?		
धारा 302 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – परिस्थितियों की श्रृंखला कब पूर्ण होती हैं?	105	149
Section 302 – (i) Identification parade – Value – If the accused is previously known to the witness, holding of identification parade is of no use.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) Judgment – Basis – To avoid miscarriage of justice, it should consist of reasons and appreciation of evidence but should not be based on the principle of preponderance of probability.		
धारा 302 – (i) शिनाख्त परेड – मूल्य – यदि साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता है तब शिनाख्त परेड किया जाना अनुपयोगी है।		
(ii) निर्णय – आधार – न्यायहानि से बचने के लिये निर्णय में कारण और साक्ष्य के मूल्यांकन को समाविष्ट होना चाहिए न कि अधिसंभाव्यता की प्रबलता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।	108	154
Section 302 – (i) Murder by unlawful assembly – Allegations of unlawful assembly, common object, trespass, rioting, etc. held not proved against all of them – Remaining charge of murder too cannot be sustained.		
(ii) Doctrine of <i>falsus in uno falsus in omnibus</i> – Applicability of.		
धारा 302 – (i) विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हत्या की गई – विधि विरुद्ध जमाव, सामान्य उद्देश्य, आपराधिक हथियार, बल्वा आदि के आरोप किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं पाए गए – हत्या का आरोप भी सिद्ध नहीं माना जा सकता।		
(ii) फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनीबस का सिद्धांत – प्रयोज्यता।	14	20
Section 302 – Murder – Proof.		
धारा 302 – हत्या – प्रमाण।	228 (ii)	335
Section 302 – See section 3 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	58	85
Section 302 – See sections 24 and 27 of the Evidence Act, 1872, section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 24 एवं 27, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 एवं विधिक सेवाप्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9।	59	87
Section 302 – See section 134 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134।	106	150
Section 302 r/w/s 34 – Murder – Suspicion cannot take the place of proof – Conviction set aside – Principles reiterated.		
धारा 302 सहपठित धारा 34 – हत्या – संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता – दोषसिद्धि अपास्त की गई।	236(iii)	355

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 302 r/w/s 149 – (i) Non-recovery of weapon – Effect – This cannot be a ground to discard the evidence of injured eye witness.		
(ii) Vicarious liability – Number of convicts below five on account of death of co-accused – Still applicable on surviving co-accused.		
धारा 302 सहपठित 149 – (i) आयुध की बरामदगी न होना – प्रभाव – यह आहत चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता।		
(ii) प्रतिनिधिक दायित्व – सह-अभियुक्त की मृत्यु के कारण दोषियों की संख्या पांच से कम – जीवित सह-अभियुक्तों पर अभी भी लागू।	107	152
Sections 302 and 201 – (i) Circumstantial evidence – Motive – Absence of motive cannot by itself a ground to reject the prosecution case.		
(ii) Unsoundness of mind – Consideration of.		
धाराएं 302 एवं 201 – (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – हेतुक – हेतुक का अभाव स्वयमेव ही अभियोजन का मामला अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।		
(ii) विकृत चित्त – विचारणीय।	186	261
Sections 302 and 304 Part-I – (i) Premeditation and intention – Incident had taken place suddenly – Appellant caused single injury – Premeditation on the part of appellant, could not be established – Conviction of appellant deserves to be modified from section 302 IPC to section 304-Part-I of IPC.		
(ii) Recovery of weapon – Merely because blood stained iron rod recovered from open space, its recovery does not become doubtful in absence of any reasonable explanation.		
(iii) Credibility of eye witness – He took refuge behind <i>imli</i> tree in order to witness the incident – Human behavior cannot be measured on any golden scale – In the given fact situation of danger, the response may vary from person to person – Conduct of eyewitness is to be judged on the basis of fact and circumstances of each case.		
धाराएं 302 एवं 304 भाग-1 – (i) पूर्वचिन्तन एवं आशय – घटना अचानक घटित हुई थी – अपीलार्थी ने एकल चोट पहुंचाई – अपीलार्थी द्वारा पूर्व-चिंतन किया जाना, स्थापित नहीं किया जा सका – अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 302 आईपीसी से धारा 304 भाग- 1 आईपीसी में परिवर्तित किये जाने योग्य है।		
(ii) हथियार की बरामदगी – केवल इसलिए कि खून से सनी लोहे की छड़ खुली जगह से बरामद हुई, किसी उचित स्पष्टीकरण के अभाव में उसकी बरामदगी संदिग्ध नहीं हो जाती।		
(iii) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता – उसने घटना को देखने के लिए इमली के पेड़ के पीछे शरण ली – मानव व्यवहार को किसी भी सुनहरे पैमाने पर नहीं		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

मापा जा सकता है – खतरे की स्थिति में, एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है – प्रत्यक्षदर्शी के आचरण का मूल्यांकन प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

251 390

Sections 302 and 304 Part-II – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Determination.

धाराएं 302 एवं 304 भाग-2 – हत्या अथवा हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध – निर्धारण।

252 392

Sections 302, 363, 365 and 376 (2) (f) – (i) Death sentence – Rape and murder of 7-8 year old physically and mentally challenged minor victim – Punishment based on “crime test”, “criminal test” and “rarest of the rare test” – Possibility of reformation ruled out – Conviction and sentence held proper.

(ii) Life imprisonment – Imposition – Minimum or non-remittable term of imprisonment – Condition when can be imposed? Explained.

धाराएं 302, 363, 365 एवं 376 (2) (च) – (i) मृत्युदंड – शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त 7-8 वर्ष की अव्यस्क पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या – “अपराध परीक्षण”, “अपराधी परीक्षण” और “दुर्लभ से भी दुर्लभतम परीक्षण” के आधार पर सजा- सुधार की संभावना नहीं – दोषसिद्धि एवं दण्डादेश उचित अभिनिर्धारित।

(ii) आजीवन कारावास – आरोपण – कारावास की न्यूनतम या गैर परिहार योग्य अवधि – शर्त कब लगाई जा सकती है ? व्याख्या की गई।

146 204

Sections 302 and 364-A – (i) Sentencing – Right to be heard – A meaningful, real and effective hearing should be offered to the accused, even if the Court is to be adjourned for a separate hearing.

(ii) Capital punishment – What are mitigating circumstances?

धाराएं 302 एवं 364-क – (i) दण्डादेश – सुनने का अधिकार – अभियुक्त को एक सार्थक, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई की पेशकश की जानी चाहिए, भले ही न्यायालय को अलग सुनवाई हेतु स्थगन करना पड़े।

(ii) मृत्युदण्ड – कौन सी परिस्थितियां लघुतरकारी होंगी ? 147 206

Sections 302 and 376 – Circumstantial evidence – Rape and murder of minor – Absence of DNA/ medical examination – Effect of.

धाराएं 302 एवं 376 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – नाबालिग से बलात्कार और हत्या – डीएनए/चिकित्सीय परीक्षण का अभाव – प्रभाव। 253 (i) 393

Sections 302 and 498A – See section 32 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 302 एवं 498क – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।

181 252

Sections 324, 366 and 376-AB – (i) Sentencing – Death sentence – Even if one circumstance favours accused including his young age, imposition of capital punishment is not proper.

(ii) DNA report – Chain of custody – Blood samples were collected and sent to FSL promptly – Seal of hospital was intact – No procedural impropriety found – DNA report cannot be doubted – Conviction can solely be based on DNA report.

(iii) Recovery from open place – Recovery was made from bushes and open place which was not accessible to public; it can be relied upon – No straight jacket formula that every recovery from open space is vitiated.

धाराएं 324, 366 एवं 376-कख – (i) दण्डादेश – मृत्युदण्ड – यदि अभियुक्त के हित में केवल एक परिस्थिति हो जिसमें उसका अल्प आयु का होना हो, तब भी मृत्युदण्ड उचित नहीं है।

(ii) डी.एन.ए. प्रतिवेदन – परिस्थितियों की श्रृंखला – रक्त का नमूना एकत्रित कर एफ.एस.एल. जाँच हेतु शीघ्रता से भेजा गया – अस्पताल की मुद्रा अखंडित – कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाई गई – डी.एन.ए. प्रतिवेदन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता – दोषसिद्धि केवल डी.एन.ए. प्रतिवेदन के आधार पर की जा सकती है।

(iii) खुले स्थान से वस्तु की बरामदगी – बरामदगी खुले स्थान से की गई जहाँ घांस थी, पर आम जन की पहुँच नहीं थी; इस पर विश्वास किया जा सकता है – ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है कि खुले स्थान से की गई हर बरामदगी दूषित होती है।

148 208

Section 326 – Criminal practice – Testimony of injured witness – Injury to a witness is an inbuilt guarantee of his presence at the scene of crime – Unless there are strong grounds for its rejection based on major contradictions and discrepancies, it should be relied upon.

धारा 326 – आपराधिक प्रथा – आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य- साक्षी को आई हुई चोट स्वतः प्रमाण है कि वह घटना स्थल पर मौजूद था – जब तक तात्विक श्रेणी के विरोधाभास एवं विसंगतियों जैसे ठोस आधार उसे खारिज करने के न हो, विश्वास किया जाना चाहिये।

*149 212

Sections 363, 364 and 364 – A – (i) Distinction between “kidnapping” and “kidnapping for ransom” – Explained.

(ii) Alteration of charges – Stage of trial not relevant – Only constraint is the prejudice likely to be caused to the accused.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 363, 364 एवं 364-क – (i) “अपहरण” और “फिरौती के लिए अपहरण” के बीच अंतर – स्पष्ट किया गया।		
(ii) आरोपों में परिवर्तन – विचारण का प्रक्रम प्रासंगिक नहीं है – अभियुक्त के प्रति होने वाले पूर्वाग्रह की संभावना ही केवल बाधा है।	187	263
Section 376 – See sections 53, 164-A (2), 167 (2) and 173 (2) (h) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 376 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 53, 164-क (2), 167(2) एवं 173(2)(ज)।	88	131
Sections 390, 395, 504 and 506 – (i) When theft is not robbery? If hurt, is caused at the time of the commission of the theft but for an object other than the one referred to in section 390 of IPC, theft would not amount to robbery.		
(ii) Intentional insult – Mere abuse, discourtesy, rudeness or insolence, may not amount to an intentional insult within the meaning of section 504, IPC if it does not have the necessary element of being likely to incite the person insulted to commit breach of the peace.		
(iii) Criminal intimidation – Before an offence of criminal intimidation is made out, it must be established that the accused had an intention to cause harm to the complainant.		
धाराएं 390, 395, 504 एवं 506 – (i) चोरी कब लूट नहीं है? – यदि उपहति चोरी का अपराध कारित करते समय कारित की गई हो परन्तु वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 में वर्णित उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य हेतु हो तब वह लूट नहीं मानी जाएगी।		
(ii) साशय अपमान – केवल अपशब्द, अशिष्ट व्यवहार, असभ्यता या बेअदबी मात्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 की परिभाषा के अंतर्गत साशय अनादर के तुल्य नहीं होती जब तक कि किसी व्यक्ति को लोक शांति भंग करने के लिए प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान न किया गया हो।		
(iii) आपराधिक अभित्रास – आपराधिक अभित्रास का अपराध गठित करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त का आशय परिवादी को भयभीत करना था।	254	395
Sections 405 and 406 – (i) Issuance of process – Facts to be considered.		
(ii) Accused resides outside the jurisdiction of court – It is obligatory upon the Magistrate to inquire into the case himself or direct investigation be made by a police officer for finding out whether or not there is sufficient ground for proceeding against the accused.		
धाराएं 405 एवं 406 – (i) आदेशिका जारी किया जाना – विचार में लिये जाने वाले तथ्य।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) अभियुक्त का न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर निवास – मजिस्ट्रेट के लिए बाध्यकारी है कि वह प्रकरण की जांच स्वयं करे या पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के लिए निर्देशित करें कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए पर्याप्त आधार दर्शित होते हैं।	150	212
Sections 406, 417, 418, 420, 467 and 468 – Quashing of FIR – Fraudulent or dishonest intention shown right at the beginning of transaction – The allegation of failure to keep a promise, not enough to initiate criminal proceeding.		
धाराएं 406, 417, 418 420, 467 एवं 468 – प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपास्त करना – जब तक कि संव्यवहार की शुरुआत में कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण आशय को नहीं दर्शाया जाता है तब केवल वचन पूरा करने में विफलता आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त नहीं है।	188	266
Sections 406 and 420 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 406 एवं 420 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।	93	136
Section 411 – Possession of stolen articles – Ingredients of crime.		
धारा 411 – चोरी की गई संपत्ति का आधिपत्य – अपराध के तत्व।	26	42
Section 420 – Cheat or defraud? Effect when there is absence of intention.		
धारा 420 – छल या धोखा – प्रभाव जहां आशय का अभाव हो।	28	43
Sections 420, 463, 465, 468 and 471 r/w/s 120 B – Offence of cheating – <i>Prima facie</i> case.		
(ii) Offence of forgery – Essential ingredients – Making false document is <i>sine qua non</i> – Making false claim and creating false document are both different and distinct – Law explained.		
धाराएं 420, 463, 465, 468 एवं 471 सहपठित 120ख – (i) छल का अपराध – प्रथम दृष्टया मामला।		
(ii) कूटरचना का अपराध – आवश्यक संघटक – मिथ्या दस्तावेज रचना अनिवार्य है – मिथ्या दावा करना एवं मिथ्या दस्तावेज रचना दोनों भिन्न और पृथक हैं – विधि की व्याख्या की गई।	255	397
INTERPRETATION OF STATUTES:		
संविधियों का निर्वचन:		
– See Order 14 Rule 5 of the Civil Procedure Code, 1908.		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 14 नियम 5।	129	182

Act/ Topic	Note No.	Page No.
– While interpreting a statute, the court has to prefer an interpretation which advances the purpose of the statute. – किसी भी प्रावधान के निर्वचन के समय न्यायालय को ऐसी व्याख्या को प्रधानता देना चाहिए जो कि संविधि के उद्देश्य को अग्रेषित करे।	60 (ii)	91
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015		
किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015		
Sections 2 (12), 18 (1)(a) to (g) and (2) – Trial of juvenile as an adult – An accused after conviction held to be a juvenile at the stage of appeal – What would be the status of trial?		
धाराएं 2 (12), 18(1)(क) से (छ) एवं (2) – बालक का वयस्क के रूप में विचारण – अभियुक्त को दोषसिद्धि उपरांत अपील के स्तर पर बालक निर्धारित किया गया – विचारण की क्या स्थिति होगी?	189	267
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2007		
किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम, 2007		
Rule 12(3) – See section 2(d) of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.		
नियम 12 (3) – देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(घ)।	204	290
LAND ACQUISITION ACT, 1894		
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894		
Section 4 – See section 24 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.		
धारा 4 – देखें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1)।	206	294
Section 23 – (i) Ready reckoner – Purpose – For calculation of stamp duty – Cannot be the basis for determination of compensation.		
(ii) Determination of compensation – Factors to be considered.		
धारा 23 – (i) तैयार संगणक – प्रयोजन – स्टाम्प शुल्क के आंकलन के लिए – प्रतिकर के निर्धारण के लिए आधार नहीं माना जा सकता।		
(ii) प्रतिकर का निर्धारण – विचारित किये जाने वाले कारक।		
	61	93

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 23 and 28A – Determination of compensation – When land acquired under the same notification.		
धाराएं 23 और 28क – प्रतिकर निर्धारण – जहां एक ही अधिसूचना द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई हो।	29	44
Section 28A – Land acquisition – An award passed u/s 20 of the Legal Services Authorities Act, 1987 by the Lok Adalat cannot be the basis for invoking section 28A of the Act.		
धारा 28क – भूमि अधिग्रहण – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 28 क को आकर्षित करने का आधार नहीं बन सकता है।	30	45

LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)

Sections 109 and 111 – Mutation on basis of Will – Naib-tehsildar did mutation on the basis of Will – It is the domain of civil court – Mutation proceeding was quashed.

धाराएं 109 एवं 111 – वसीयत के आधार पर नामांतरण – नायब तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर नामांतरण कर दिया – यह व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार है – नामांतरण को अपास्त किया गया।

190 **268**

Section 110 – (i) Adverse possession – Article 65 would not apply to property belonging to undivided joint Hindu family – Every co-sharer is deemed to be in constructive possession – No *animus* or hostile possession against co-sharer – Title of co-sharer will not extinguish even if such sharer is not in actual possession – Claim on such property on basis of adverse possession cannot be accepted.

(ii) Mutation – Effect – Entry in revenue record neither creates nor extinguishes any right or title – Merely because co-sharer did not take steps to get her name mutated, would not deprive her from her share or title in property.

धारा 110 – (i) प्रतिकूल कब्जा – अनुच्छेद 65 अविभक्त संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति पर लागू नहीं होगा – प्रत्येक सह-अंशधारी को आन्वयिक कब्जे में समझा जाएगा – सह-अंशधारी के विरुद्ध कोई विद्वेष अथवा प्रतिकूल कब्जा नहीं हो सकता – सह-अंशधारी का स्वत्व कभी भी समाप्त नहीं होगा भले ही अन्य सह-अंशधारी वास्तविक आधिपत्य में न हो – ऐसी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(ii) नामान्तरण – प्रभाव – राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टि किसी अधिकार अथवा हक को न तो सृजित करेगी और न ही समाप्त करेगी – केवल इस कारण

Act/ Topic	Note No.	Page No.
से कि सह-अंशधारी ने स्वयं का नामांतरण कराने हेतु कोई कदम नहीं उठाया, उसे संपत्ति में उसके अंश अथवा स्वामित्व से वंचित नहीं किया जा सकता।	257	400
Section 131 – Easementary right – Where decree of title and possession of Civil Court exists therein, Tehsildar will not have any power u/s 131 to pass contrary order.		
धारा 131 – सुखाधिकार – जहां सिविल न्यायालय की स्वत्व एवं आधिपत्य की डिक्री अस्तित्व में है वहां तहसीलदार को धारा 131 के अंतर्गत विपरीत आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है।	191	269

LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987 (M.P.)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (म.प्र.)

Section 9 – Legal aid – It is the duty of court to ensure that an accused put on a criminal trial is effectively represented by a defense counsel.

धारा 9 – विधिक सहायता – न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि एक अभियुक्त जिसे आपराधिक विचारण में लाया गया है को विचारण के दौरान प्रभावशील रूप से बचाव अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किया जाए।

59 (vii) 87

LIMITATION ACT, 1963

परिसीमा अधिनियम, 1963

Section 5 – Civil Appeal – Ground for delay was incapability to deposit court fees – Not a sufficient ground.

धारा 5 – सिविल अपील – विलम्ब का आधार न्यायालय शुल्क जमा करने में असमर्थता – पर्याप्त आधार नहीं।

109 155

Sections 5, 12 and 14 – (i) Effect when conduct of party lacks due diligence and is negligent on condonation of delay u/s 5 of the Act and exclusion of time spent in wrong forum u/s 14 of the Act.

(ii) No appeal in the eyes of law – Unless delay in filing appeal is condoned.

(iii) Exclusion of time u/s 14 of the Act rejected – Condonation of delay u/s 5 of the Act – Not permissible on same set of facts.

धाराएं 5, 12 एवं 14 – (i) पक्षकार के आचरण में सम्यक सतर्कता का अभाव अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब से क्षमा एवं गलत मंच पर व्यतीत किया गया समय धारा 14 के अधीन समय के अपवर्जन का अधिकारी नहीं।

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षमा किये जाने तक – विधिक दृष्टि में अपील का अस्तित्व नहीं।		
(iii) अधिनियम की धारा 14 के अधीन समय का अपवर्जन निरस्त – अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब क्षमा करना – उन्हीं तथ्यों पर अनुज्ञात नहीं।		
	62	94
Section 14 – (i) Condonation of delay u/s 5 of the Act and exclusion of time u/s 14 of the Act – Cannot be equated.		
(ii) Period once excluded u/s 14 of the Act – Cannot be counted for purpose of computing the period of condonation of delay u/s 5 of the Act.		
धारा 14 – (i) अधिनियम की धारा 5 के अधीन परिसीमा की छूट तथा अधिनियम की धारा 14 के अधीन समय का अपवर्जन – एकसमान नहीं माने जा सकते।		
(ii) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत एक बार अपवर्जित समय – अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब के क्षमा करने की अवधि की गणना हेतु विचार में नहीं लिया जा सकता।		
	63	95
Section 17 – Rejection of plaint – Limitation – By clever drafting, plaintiff tried to bring the suit within the period of limitation which otherwise is barred by limitation – Such plaint should be rejected.		
धारा 17 – वाद का नामंजूर किया जाना – परिसीमा – परिसीमा से वर्जित वाद को चतुराई पूर्वक लेख कर वादी ने वाद को परिसीमा के भीतर लाने का प्रयास किया – ऐसा वाद नामंजूर किया जाना चाहिए।		
	83(ii)	123
Article 54 – See section 20 of the Specific Relief Act, 1963		
अनुच्छेद 54 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20		
	256	399
Article 58 – (i) Suit for partition – Limitation – Right to sue for partition is a recurring right and its cause of action arises on a day-to-day basis, which will be governed by Article 58 of the Act.		
(ii) Suit for partition – Requirement of separate relief – Suit inherently includes relief of delivery of separate possession – Not necessary for plaintiff to independently seek such relief.		
अनुच्छेद 58 – (i) विभाजन के लिए वाद – परिसीमा – विभाजन के लिये वाद का अधिकार एक निरंतर अधिकार है और इसके लिये वाद कारण दिन प्रतिदिन के आधार पर उत्पन्न होता है जो अधिनियम के अनुच्छेद 58 से शासित होगा।		
(ii) विभाजन के लिए वाद – पृथक अनुतोष की आवश्यकता – वाद में पृथक से आधिपत्य प्रदान किये जाने का अनुतोष अन्तर्निहित है – वादी के लिये ऐसा अनुतोष स्वतंत्र रूप से प्रार्थित किया जाना आवश्यक नहीं है।		
	151	213

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Article 65 – See section 110 of the Land Revenue Code (M.P.) अनुच्छेद 65 – देखें भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.), 1963 की धारा 110	257	400
Article 65 – See section 53-A of the Transfer of Property Act, 1882. अनुच्छेद 65 – देखें सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53-क।	214	307

MOTOR VEHICLES ACT, 1988

मोटर यान अधिनियम, 1988

Sections 128 and 194 (c) – Contributory negligence – Whether tripling on bike without helmet amounts to negligence?

धाराएं 128 एवं 194 (ग) – योगदायी उपेक्षा – क्या दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के तीन सवारी करना उपेक्षा की परिधि में आता है?

110 **156**

Section 147 (1) – Liabilities of Insurance Company – Tractor trolley insured for agricultural purpose – No premium was paid for carrying the passenger – Use of tractor for other business activities – Insurance Company cannot be held liable.

धारा 147 (1) – बीमा कम्पनी का दायित्व – ट्रैक्टर ट्राली कृषि प्रयोजन के लिये बीमित – यात्री के संबंध में कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया – ट्रैक्टर का उपयोग अन्य व्यापारिक गतिविधियों हेतु किया गया – बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं मानी जा सकती।

153 **216**

Section 147 (1) – Pay and Recover – Goods vehicle – Liability of insurance company – “Owner of goods” means the person who travels in the cabin of the vehicle – Deceased was not sitting in the cabin – Insurance Company not liable – However, Tribunal can order for pay and recover.

धारा 147 (1) – भुगतान करें और वसूलें – मालवाहक वाहन – बीमा कंपनी का दायित्व – “माल का स्वामी” के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति आएगा जो वाहन के केबिन में बैठकर यात्रा करे – मृतक केबिन में नहीं बैठा था – बीमा कंपनी उत्तरदायित्व से मुक्त – परंतु अधिकरण भुगतान करो और वसूलो का आदेश कर सकती है।

152 **214**

Sections 149 and 166 – Theft of vehicle – Insurance Company failed to lead any evidence to prove the violation of any specific terms and condition of policy – Held, insurance company liable to pay compensation.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 149 एवं 166 – वाहन की चोरी – बीमा कंपनी पालिसी के किसी विशिष्ट नियम और शर्त के उल्लंघन को साबित करने वाला प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रही – अभिनिर्धारित, बीमा कम्पनी उत्तरदायी है।	154	216
Section 166 – Assessment of compensation – When deceased is a probationer bank employee.		
धारा 166 – क्षतिपूर्ति का निर्धारण – जहां मृतक परिवीक्षाधीन बैंक कर्मचारी हो।	31	47
Section 166 – (i) Assessment of income – NRI – Claimant had worked abroad for sometime – Relying on passport, Tribunal should take a note of it.		
(ii) Termination of pregnancy – Married women, aged about 28 years at the time of accident, went through trauma and agony of miscarriage for which further compensation of Rs. 2,00,000/- awarded.		
धारा 166 – (i) आय का आंकलन – एन.आर.आई. – आवेदक ने विदेश यात्रा की है और कुछ समय तक काम किया है – पासपोर्ट पर भरोसा करते हुए अधिकरण को इस पर ध्यान देना चाहिये।		
(ii) गर्भावस्था की समाप्ति – दुर्घटना के समय विवाहित महिला की आयु लगभग 28 वर्ष, गर्भपात के आघात और पीड़ा से गुजरी, जिसके लिये 2,00,000/- रुपये का अतिरिक्त प्रतिकर प्रदान किया गया।	192	270
Section 166 – Assessment of income – Revised salary and pay benefits – Actual income of deceased is to be considered.		
धारा 166 – आय का आंकलन – पुनरिक्षित वेतन एवं वेतन लाभ – मृतक की वास्तविक आय पर विचार किया जाना चाहिए।	195	276
Section 166 – Assessment of permanent disability – At the time of accident appellant aged 50 years 5 months was working as a gunman in a hotel – Due to accident, his right leg above the knee was amputated and thereby terminated from service – A person with his right leg amputated cannot perform the duty of a gunman – This is his functional disability – Considering the aforesaid facts, the loss of earning capacity of the appellant assessed by Tribunal as 100%, held proper.		
धारा 166 – स्थाई निर्योग्यता का आंकलन – दुर्घटना के समय 50 वर्ष 5 माह की आयु वाला आवेदक होटल में गनमैन के रूप में कार्यरत था – दुर्घटना के कारण दाहिना पैर घुटने के ऊपर से विच्छेदित हुआ – उसकी सेवा समाप्त की गई – एक व्यक्ति जिसका दाहिना पैर विच्छेदित हुआ हो गनमैन के रूप में अपना कार्य नहीं कर सकता – यह उसकी कार्यात्मक अयोग्यता है – उपरोक्त तथ्यों को विचार में लेते हुए आवेदक की अर्जन क्षमता में हानि अधिकरण द्वारा सौ प्रतिशत उचित ही निर्धारित की गई।	258	402

Section 166 – (i) Compensation – Agricultural land – Deceased was cultivating land of other family members in addition to his own land, which is proved by documentary evidence – While calculating actual income, this factor should also be considered and future prospects on total income also needs to be calculated.

(ii) Loss of consortium – Should be awarded to all three categories of applicants separately i.e. Spousal Consortium, Parental Consortium and Filial Consortium (for each child) at the rate of Rs. 40,000/- each.

धारा 166 – (i) प्रतिकर – कृषि भूमि – मृतक अपनी भूमि के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों की भूमि पर भी खेती करता था जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है, वास्तविक आय की गणना करते समय इस कारक पर भी विचार करना चाहिए और कुल आय पर भविष्य की संभावना की भी गणना की जानी चाहिए।

(ii) साहचर्य की हानि – तीनों श्रेणियों के आवेदकों को अलग-अलग प्रदान की जाना चाहिये, यानि पति-पत्नी को साहचर्य की हानि, माता-पिता को साहचर्य की हानि एवं प्रत्येक बच्चे को साहचर्य की हानि, 40,000/- रुपये की दर से प्रदान की जाना चाहिये।

193 **272**

Section 166 – Compensation – Assessment on the basis of last year Income Tax Return to be made and not on the average of last three years Income Tax Returns.

धारा 166 – प्रतिकर – निर्धारण पिछले वर्ष के पत्रक अनुसार किया जाएगा न कि पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर।

155 **217**

Section 166 – Compensation – Assessment of – Dependents are young wife and minor son without experience – It cannot be expected from them to run the business in the same manner as that of deceased – Loss of income due to death would be at least 50% of normal way in which the business was conducted.

धारा 166 – प्रतिकर – निर्धारण – आश्रित युवा पत्नी एवं नाबालिक पुत्र जिन्हे कोई पूर्व अनुभव नहीं – यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे मृतक की तरह व्यवसाय संचालित कर सकते हैं – मृत्यु हो जाने से व्यवसाय जिस प्रकार संचालित होता था उसमे कम से कम 50 प्रतिशत की हानि होना सामान्य है।

156 **218**

Section 166 – Compensation – Assessment in case of deceased lady who was homemaker and took tuitions and was pregnant at the time of accident resulting in loss of foetus.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 166 – प्रतिकर – गृहकार्य एवं ट्यूशन पढ़ाने वाली मृतक महिला के संबंध में प्रतिकर निर्धारण किया गया जो कि घटना के समय गर्भ धारण किये हुई थी और भ्रूण की मृत्यु हो गई।	157	219
Section 166 – Compensation – Assessment in case of 12 year old injured – Accident caused amputation of right leg sustaining permanent disability to the extent of 97%.		
धारा 166 – प्रतिकर – 12 वर्षीय आहत के संबंध में प्रतिकर निर्धारण – दुर्घटना के फलस्वरूप दाये पैर के कट कर अलग हो जाने पर 97 प्रतिशत तक की स्थाई निःशक्तता कारित हुई।	158	220
Section 166 – Compensation – Permanent disability – Amputation of right arm – Computation of compensation.		
धारा 166 – प्रतिकर – स्थायी निर्योग्यता-दाहिनीभुजा का विच्छेदन – प्रतिकर की गणना।	64	96
Section 166 – Compensation – Permanent disability – Amputation of both legs – Injured would not be able to do any manual work – Assessed disability at 100%.		
धारा 166 – प्रतिकर – स्थायी निर्योग्यता – दोनों पैरों का विच्छेदन – आहत किसी प्रकार का शारीरिक कार्य नहीं कर पायेगा – 100 प्रतिशत अक्षमता का आंकलन किया गया।	194	275
Section 166 – Composite negligence – When this theory does not arise ?		
धारा 166 – संयुक्त उपेक्षा – कब यह सिद्धांत उत्पन्न नहीं होता ?	111	158
Section 166 – Contributory negligence – Proof.		
धारा 166 – योगदायी उपेक्षा – प्रमाण।	65	97
Section 166 – (i) Motor vehicle accident – Quantum of compensation in injury cases.		
(ii) Computation of compensation – Deceased employed as Principal in a Law College was aged between 50 to 60 years – Claimants were wife of deceased and four children – Income assessed relying upon statement of accountant of Law College along with additional income from checking examination copies – Awarded Rs.40,000/- to each claimant for loss of consortium plus compensation in other conventional heads.		
धारा 166 – (i) मोटर यान दुर्घटना – उपहति के मामलों में प्रतिकर का परिमाण।		
(ii) प्रतिकर की गणना – मृतक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत जिसकी आयु 50-60 वर्ष के बीच – दावेदार मृतक की पत्नि और चार बच्चे – लॉ कॉलेज		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
के अकाउंटेंट के बयान के आधार पर आय का आकलन किया गया, साथ ही परीक्षा की कॉपी की जाँच से अतिरिक्त आय – साहचर्य की हानि के लिए प्रत्येक दावेदार को रु 40,000/- प्रदाय किया गया और अन्य पारंपरिक मदों में भी प्रतिकर दिया गया।	259	403
Sections 166 and 168 – (i) Accident caused by harvester No. 4598 – Whether registration of harvester is required? Held, No.		
(ii) Harvester mounted on tractor – Harvester not included in Schedule – Additional premium not required – Additional premium is payable in case of trailers mentioned in Schedule of trailers.		
धाराएँ 166 एवं 168 – (i) हारवेस्टर क्रमांक 4598 से दुर्घटना कारित – क्या हारवेस्टर का पंजीयन आवश्यक ? अभिनिर्धारित, नहीं।		
(ii) ट्रेक्टर से जुड़ा हुआ हारवेस्टर – हारवेस्टर अनुसूची में सम्मिलित नहीं – अतिरिक्त प्रीमियम आवश्यक नहीं – ट्रेलरों की अनुसूची में वर्णित ट्रेलरों के मामले में अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान योग्य।	66	97
Sections 166 and 168 – (i) Assessment of compensation – Salary drawn by deceased three years before the accident is unreliable guide to assess notional income.		
(ii) Dependant – Cannot be restricted to mean those who are financially dependant – Minor children are emotionally dependant on mother, who lost care and guidance of their mother at a very young age – Tribunal ought to have factored in loss of dependency.		
धाराएँ 166 एवं 168 – (i) क्षति पूर्ति का निर्धारण – मृतिका द्वारा 3 वर्ष पूर्व की जार ही अर्जित आय के आधार पर काल्पनिक आय का निर्धारण अनुचित है।		
(ii) आश्रित – केवल वित्तीय आश्रित तक सीमित नहीं किया जा सकता – अव्यस्क बच्चे जिन्होंने बहुत छोटी आयु में माँ की देखभाल एवं सन्तान को छोटी आयु में खोया भी आश्रित है – अधिकरण को आश्रितता की हानि के समय यह कारक भी ध्यान रखना चाहिये।	32	47
Sections 166 and 168 – (i) Compensation – Future medical expenses necessary to be considered.		
(ii) Loss of marriage prospects – Claimant who has suffered total disability deserves a suitable compensation under this head.		
(iii) Life time attender – Charges at the rate of Rs. 5000/- per month – Using multiplier of 18, considering the age of claimant, is just and proper.		
धाराएँ 166 और 168 – (i) प्रतिकर – भविष्यवर्ती चिकित्सीय व्यय को विचार में लेना आवश्यक।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) विवाह की संभावना की हानि – आवेदक जो पूरी तरह से निर्योग्य है वह इस मद में उचित प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है।		
(iii) आजीवन सहायक – 5000/- रूपये प्रतिमाह की दर से शुल्क – आवेदक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 के गुणांक का उपयोग उचित एवं न्यायसंगत है।	196	278
Sections 166 and 168 – (i) Motor accident case – Determination of compensation – Income Tax Return (ITR) being statutory document, may be considered for computation of annual income.		
(ii) The Act being beneficial legislation concept of ‘Just and fair’ compensation is of paramount importance.		
(iii) Calculation of ‘Just and fair’ compensation – Explained.		
धाराएं 166 एवं 168 – (i) मोटर दुर्घटना प्रकरण – प्रतिकर का निर्धारण – आयकर रिटर्न वैधानिक दस्तावेज होने से वार्षिक आय की गणना में विचार योग्य हो सकता है।		
(ii) अधिनियम लाभकारी विधान होने से ‘उचित एवं न्यायसंगत’ प्रतिकर की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है।		
(iii) ‘उचित एवं न्यायसंगत’ प्रतिकर की गणना – व्याख्या की गई।	67	98
Section 168 – (i) Compensation – It becomes duty of court to at least restore the claimant as best as possible to the position he was in, before the occurrence of the disability.		
(ii) Prosthetic limb – Cost of.		
(iii) Future prospects – Denial – On the ground that income had increased after the accident is not enough as the rise in income may be attributed to multiple other factors also.		
धारा 168 – (i) प्रतिकर – न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि दावेदार को यथासंभव कम से कम उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किया जावे जिस स्थिति में वह निर्योग्यता के पूर्व था।		
(ii) कृत्रिम अंग – मूल्य।		
(iii) भविष्य की संभावनाएं – अस्वीकृति – दुर्घटना के पश्चात् आय में वृद्धि होने के आधार पर पर्याप्त नहीं है क्योंकि आय में वृद्धि और भी अन्य कारकों के कारण हो सकती है।	197	279
Section 168 – Motor vehicle accident – Claim petition – Compensation – Final report filed in criminal case – Effect – Opinion in the final report would not have bearing on the claim petition – Claim petition to be considered on its own merits.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

धारा 168 – मोटरयान दुर्घटना – दावा याचिका – प्रतिकर – दांडिक मामले में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन – प्रभाव – अंतिम प्रतिवेदन में दी गई राय दावा याचिका पर कोई प्रभाव नहीं रखेगी – दावा याचिका अपने स्वयं के गुण-दोष पर विचार की जाएगी।

260 (i) 405

Section 168 (1) – Compensation – Road accident – Deceased aged 12 years – It is just and proper to accept the notional income of ₹ 30,000/- p.a. including future prospects and using multiplier of 15.

धारा 168 (1) – प्रतिकर – सड़क दुर्घटना – मृतक की आयु 12 वर्ष – भविष्य की संभावनाओं को सम्मिलित करते हुए अनुमानित आय 30,000 रुपये प्रतिवर्ष स्वीकार करना और 15 के गुणक का प्रयोग उचित और न्यायसंगत है।

68 101

MUSLIM LAW:

मुस्लिम विधि:

Jurisdiction – Examination of the authenticity of *Hiba*.

क्षेत्राधिकार – *हिबा* की वैधानिकता का परीक्षण।

33 50

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

Sections 2 (xvii) (a) and 15 – Seizure – Once it is established that the seized ‘poppy straw’ tests positive for the contents of ‘morphine’ and ‘meconic acid’, no other test would be necessary for establishing the guilt of the accused.

धाराएं 2 (xvii) (क) एवं 15 – जब्ती – एक बार यह निर्धारित हो जाता है कि जब्तशुदा ‘पॉपी स्ट्रॉ’ में ‘मॉर्फिन’ एवं ‘मेकोनिक एसिड’ की अंतर्वस्तु निहित है तो अभियुक्त के दोषसिद्धि के निर्धारण हेतु अन्य किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

60 (i) 91

Sections 8(b), 18 (c), 29, 46 and 47 – (i) Illegal cultivation – Duty of ‘land holder’ enumerated.

(ii) Neglect in furnishing information of illegal cultivation by land holder or any officer of Government – Attracts punishment u/s 32 of the Act.

(iii) Intentionally aiding by illegal omission in not furnishing timely information about illegal cultivation – Whether crime may or may not have been committed – Attracts abetment for commission of offence u/s 29 of the Act.

धाराएं 8 (ख), 18 (ग), 29, 46 एवं 47 – (i) अवैध खेती – ‘भूमि धारक’ का कर्तव्य प्रगणित।

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) भूमि धारक अथवा शासन के किसी अधिकारी द्वारा अवैध खेती की सूचना देने में उपेक्षा – अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत दंडनीय।		
(iii) अवैध खेती की समयबद्ध सूचना देने में अवैध लोप द्वारा साशय मदद करना – अपराध घटित हुआ हो अथवा नहीं – अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण आकर्षित।	112	158
Sections 8 (c) and 20 (b) (ii) (c) – Discharge – Applicant was impleaded on the basis of memorandum of co-accused – No other evidence against accused was available to connect him to offence – Charge quashed.		
धाराएं 8(ग) एवं 20 (ख) (ii) (ग) – उन्मोचन – सह अभियुक्त के मेमोरेण्डम के आधार पर आवेदक को आलिप्त किया गया – अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी जो उसे अपराध से संबद्ध करें – आरोप अपास्त किया गया।	198	281
Sections 20 (b) (ii) (c) and 54 – Illegal possession of contraband article – Burden of proof on accused – It must first be established that a recovery was made from the accused.		
धाराएं 20 (बी) (ii) (सी) और 54 – वर्जित वस्तु का अवैध आधिपत्य – सबूत का भार अभियुक्त पर – पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त से बरामद की गई थी।	34	50
Sections 37 and 67 – See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 37 एवं 67 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	69	103

NATIONAL HIGHWAYS ACT, 1956

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

Section 3 H (4) – (i) Acquisition of land – Apportionment of compensation – Jurisdiction – Special Land Acquisition Officer determined compensation – Dispute arose between claimants with respect to apportionment – Held, dispute on apportionment of compensation or payment to any person can only be decided by the Principal Civil Court of original jurisdiction i.e. District Judge – Procedure of referral, explained.

(ii) Apportionment of compensation – General principles.

धारा 3 ज (4) – (i) भूमि का अर्जन – प्रतिकर का प्रभाजन – क्षेत्राधिकार – विशिष्ट भूमि अर्जन अधिकारी ने प्रतिकर निर्धारित किया – दावेदारों के मध्य प्रभाजन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ – अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिकर के प्रभाजन अथवा किसी व्यक्ति को भुगतान के संबंध में विवाद का निपटारा केवल

Act/ Topic	Note No.	Page No.
मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्यायालय अर्थात जिला न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है – निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया समझाई गयी।		
(ii) प्रतिकर का प्रभाजन – सामान्य सिद्धांत।	261	407

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

Sections 15, 56 and 138 – Part payment – Loan partly or wholly paid before presentation of cheque – Lack of endorsement on the cheque – Offence u/s 138 not attracted unless specific endorsement to this effect is made on the cheque.

धाराएं 15, 56 एवं 138 – आंशिक भुगतान – चैक प्रस्तुति के पूर्व ऋण का आंशिक अथवा पूर्णतः भुगतान – चैक पर पृष्ठांकन का अभाव – धारा 138 का अपराध तब तक आकर्षित नहीं जब तक कि चैक पर इस आशय का विनिर्दिष्ट पृष्ठांकन न हो।

113 160

Sections 118, 138 and 139 – Legal debt – Defence – Once it is found that the Income Tax Return of the complainant did not disclose that he lent amount to the accused and the declared income was not sufficient to give loan – Defence raised by the accused satisfies the standard of preponderance of probability.

धाराएं 118, 138 एवं 139 – विधिक ऋण – बचाव – जब एक बार यह पाया जाता है कि परिवादी के आयकर रिटर्न में यह खुलासा नहीं किया गया था कि उसने अभियुक्त को राशि उधार दी थी और घोषित आय ऋण देने हेतु पर्याप्त नहीं थी – अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव अधिसंभाव्यता की प्रबलता के मानक को संतुष्ट करता है।

199 282

Section 138 – Non-appearance of complainant – Effect – Where complainant had already been examined as a witness in the case – Not appropriate to pass an order of acquittal.

धारा 138 – परिवादी की अनुपस्थिति – प्रभाव – जहां परिवादी का प्रकरण में साक्षी के रूप में परीक्षण किया जा चुका था – दोषमुक्ति का आदेश पारित करना उचित नहीं।

114 162

Section 138 – Summons to produce document – Necessity and desirability of documents established – Trial Court ought to have called the documents to confront the witnesses – Application filed by the accused allowed.

धारा 138 – दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये समंस – दस्तावेज की आवश्यकता और वांछनीयता स्थापित – विचारण न्यायालय को ऐसे दस्तावेजों को साक्षी से सामना कराने हेतु आहूत करना होगा – अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत।

159 222

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 138 and 139 – Dishonour of cheque – Effect when cheque is filled by a person other than the drawer and signature and delivery of cheque by accused to complainant admitted.		
धाराएं 138 एवं 139 – चेक का अनादरण – लेखीवाल(जारीकर्ता) के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा चेक भरा गया एवं अभियुक्त द्वारा चैक पर हस्ताक्षर एवं परिवादी को प्रदाय करना स्वीकृत होने का प्रभाव।	70	104
Sections 138 and 141 – Dishonour of Cheque – Disputed cheque was given by the accused on behalf of the company – Before arraying company as an accused in complaint case, the petitioner cannot be prosecuted for the offence u/s 138 of the Act.		
धाराएं 138 एवं 141 – चैक का अनादरण – विवादित चैक कंपनी की ओर से अभियुक्त द्वारा दिया गया – कंपनी को अभियुक्त के रूप में संयोजित किये बिना याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध में अभियोजित नहीं किया जा सकता।	160	223
Sections 138, 141 and 142 – Offence by company – When can vicarious liability in terms of section 141 be fastened against persons mentioned in clause (1) or (2) of section 141 of the Act?		
धाराएं 138, 141 एवं 142 – कंपनी द्वारा अपराध – धारा 141 के संदर्भ में कब प्रतिनिहित दायित्व धारा 141 के खंड (1) या (2) में उल्लेखित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपित किया जा सकता है?	161	224
Sections 138 and 142 – Complaint by company – Filing of complaint in the name of company through power of attorney holder is perfectly legal.		
धाराएं 138 एवं 142 – कंपनी द्वारा परिवाद – पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा कंपनी की तरफ से प्रस्तुत किया गया परिवाद पूर्णतः वैध।	115	163
Sections 138 and 142 – Non-impleadment of sole proprietary firm in complaint – When need not be impleaded separately?		
धाराएं 138 एवं 142 – एकल स्वामित्व फर्म को परिवाद में न जोड़ा जाना – कब पृथक से संयोजित करने की आवश्यकता नहीं?	*200	283
Sections 138 and 143A (5) – Whether an accused who had failed to deposit interim compensation could be fastened with any other disability including denial of right to cross-examine the witnesses? Held, No.		
धाराएं 138 एवं 143क (5) – जहाँ अभियुक्त ने अंतरिम प्रतिकर नहीं दिया हो, वहाँ उसे साक्षी का प्रति परीक्षण करने के अधिकार सेवंचित किया जा सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।	35	51

Act/ Topic	Note No.	Page No.
-------------------	-----------------	-----------------

Sections 138 and 147 – Dishonour of cheque – Agreement between the parties to settle dispute amicably – Law permits parties to compound offence even at appellate stage – Cannot be overridden.

धाराएं 138 एवं 147 – चैक का अनादरण – पक्षकारों के मध्य विवाद को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाने का अनुबंध – विधि पक्षकारों को अपीलीय स्तर पर अपराध को शमन करने की अनुमति देती है – अभिभावी नहीं किया जा सकता।

162 **225**

Sections 138 (c) and 141(1) – Offence by Company – Requirement to implead Director as accused – Importance of the word “and” in the section – To implead Director, who is other than Managing Director or signatory of the cheque, it should be averred that he was in charge of the company and was responsible for the conduct of the company – Both conditions cannot be read disjunctively and in absence of any one of them, is not sufficient to attract offence u/s 141(1).

धाराएं 138 (ग) एवं 141(1) – कंपनी द्वारा अपराध – निदेशक को अभियुक्त के रूप शामिल करने हेतु आवश्यकताएं – धारा में “और” शब्द का महत्व – निदेशक जो प्रबंध निदेशक या चैक के हस्ताक्षरकर्ता से भिन्न है, को पक्षकार बनाने हेतु यह प्रकथित किया जाना चाहिए कि वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के संचालन हेतु जिम्मेदार था – दोनों शर्तों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता और इनमें से किसी भी एक का अभाव धारा 141(1) के अंतर्गत अपराध आकर्षित नहीं करता।

262 **408**

PRACTICE AND PROCEDURE:

अभ्यास और प्रक्रिया:

– (i) Judgment writing – Basic elements – Statement of material facts – Legal issue – Deliberation to reach a decision – Conclusion – All elements to be structured in a manner so that they are easily identifiable.

(ii) Judgment/Order – Necessity of structure and clarity in judgment – Emphasis on “IRAC” method – Guidelines issued.

– (i) निर्णय लेखन – मूल तत्व – तात्विक तथ्यों का अभिकथन – विधिक प्रश्न – निर्णय पर पहुंचने हेतु विवेचना – निष्कर्ष – सभी तत्व इस प्रकार संरचित हो की वे सरलता से पहचाने जा सकें।

(ii) निर्णय/आदेश – निर्णय में संरचना एवं स्पष्टता की आवश्यकता – “IRAC” पद्धति पर जोर – दिशानिर्देश जारी।

201 **283**

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

Section 7 – Illegal gratification – Effect when there is no evidence produced on record to prove demand.

धारा 7 – अवैध परितोषण – मांग को साबित करने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने का प्रभाव।

116 164

Sections 7, 13 (1)(d) and 13 (2) – (i) Illegal gratification – Proof of demand.

(ii) Recovery of money – Mere recovery of money by itself cannot prove the charges – It has to be proved beyond reasonable doubt that accused voluntarily accepted the money knowing it to be bribe.

धाराएं 7, 13 (1)(घ) एवं 13(2) – (i) अवैध परितोषण – मांग का प्रमाण।

(ii) धन राशि की बरामदगी – केवल धन की बरामदगी ही आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सकती – यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होगा कि अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक यह जानते हुए कि यह रिश्वत है, धन राशि को स्वीकार किया।

263 411

Sections 7, 13 (1) (d), 13 (2) and 20 – (i) Illegal gratification – Proof of.

(ii) Offer and acceptance – Presumption – Once the fact regarding demand and acceptance or obtainment have been proved, the court has discretion to raise presumption of fact of demand which is rebuttable in nature but distinct from the presumption in law u/s 20 of the Act.

(iii) Culpability – Public servant – In the absence of evidence of complainant due to death or turning hostile or unavailability, court can convict the person on the basis of other evidence.

धाराएं 7, 13 (1) (द), 13 (2) एवं 20 – (i) अवैध परितोषण – प्रमाण।

(ii) प्रस्ताव और अभिप्राप्ति – उपधारणा – एक बार मांग और अभिप्राप्ति अथवा ग्रहण करने से संबंधी तथ्य साबित हो जाते हैं तब मांग के तथ्य की उपधारणा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है जो खण्डनीय स्वरूप की है किंतु अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत विधि की उपधारणा से भिन्न है।

(iii) दोषिता – लोक-सेवक – मृत्यु, पक्षद्रोही हो जाने अथवा अनुपलब्धता के कारण परिवादी के साक्ष्य के अभाव में न्यायालय अन्य साक्ष्य के आधार पर संबंधित व्यक्ति को दोषसिद्ध कर सकता है।

202 285

Sections 13 (1) (e) and 13 (2) – See sections 239 and 240 of the Criminal Procedure Code, 1973.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 13 (1) (ड) एवं 13 (2) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 239 एवं 240।	48	68
Section 19 – (i) Sanction for prosecution – Delay – Consequences – After expiry of three months and additional one month, the aggrieved party would be entitled to approach the writ court concerned to seek appropriate remedy.		
(ii) Sanction for prosecution – Non-compliance of statutory period in granting of sanction shall not be the sole ground for quashing of the criminal proceeding.		
धारा 19 – (i) अभियोजन की मंजूरी – विलंब – परिणाम – तीन माह और अतिरिक्त एक माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् व्यथित पक्ष उपयुक्त उपचार प्राप्त करने हेतु संबंधित रिट न्यायालय में प्रार्थना करने का अधिकारी होगा।		
(ii) अभियोजन की मंजूरी – मंजूरी प्रदान करने में वैधानिक अवधि का अनुपालन नहीं करना आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने का एकमात्र आधार नहीं होगा।	71	104

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

Sections 7, 14, 16 (1) (a) (i) and 19 (2) (a) (ii) – (i) Protection available to vendor – Valid defense in terms of packed food items available.

(ii) Vendor – Not defined in the Act – Means the person who had sold the article of food which is alleged to be adulterated.

धाराएं 7, 14, 16 (1) (क) (i) एवं धारा 19 (2) (क) (ii) – (i) विक्रेता के लिए उपलब्ध संरक्षण – उपलब्ध पैक किए गए खाद्य पदार्थों के संदर्भ में वैध बचाव।

(ii) विक्रेता – अधिनियम में परिभाषित नहीं – इसका अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने भोजन की वह वस्तु बेची थी, जिस पर मिलावटी होने का आरोप है।

203 288

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION RULES, 1955

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955

Rule 12–A – See sections 7, 14, 16 (1) (a) (i) and 19 (2) (a) (ii) of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

नियम 12–क – देखें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धाराएं 7, 14, 16 (1) (क) (i) एवं धारा 19 (2) (क) (ii)।

203 288

PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2002

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

Sections 43 (1), 44 (1) (a) and 44 (1) (c) r/w/s 4 – (i) Aspect regarding cognizance of scheduled offences discussed.

(ii) Determination of jurisdiction of Special Court for trial of offences under the Act – Material facts laid down.

धाराएं 43 (1), 44 (1) (क) एवं 44 (1) (ग) सहपठित धारा 4 – (i) अनुसूचित अपराध के संज्ञान का पहलू विचारित।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण – तात्विक तथ्य बताए गए।

117 166

Section 45 r/w/s 3 and 4 – Money laundering – The provisions of section 45 of the Act shall be applicable in connection with an application filed u/s 438 of CrPC.

धारा 45 सहपठित धाराएं 3 एवं 4 – धन शोधन – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे।

118 167

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

Section 2(d) – Age determination – School register entry was made on the basis of information given by parents – Parents stated in evidence that they were unsure about the date of birth of prosecutrix – School register entry was not believed.

धारा 2(घ) – आयु निर्धारण – स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टी अभिभावक की सूचना के आधार पर दी गई थी – अभिभावक ने यह साक्ष्य दी कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि का लेकर वह अनिश्चित हैं – स्कूल रजिस्टर की प्रविष्टी विश्वसनीय नहीं पाई गई।

204 290

Sections 3 (a), 4, 5 (i), 5 (m) and 6 – See sections 324, 366 and 376-AB of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 3 (क), 4, 5 (झ), 5 (ड) एवं 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 324, 366 एवं 376-कख।

148 208

Sections 3(a), 4, 5(m) and 6 r/w/s 2(1)(a) – Offence against children – Sentencing policy – POCSO Act was enacted to provide more stringent punishments in such offences – Minimum punishments are prescribed for deterrent effect on society – Sentence lesser than the minimum prescribed cannot be imposed even though the accused may have moved ahead in life.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 3(क), 4, 5(ड) और 6 सहपठित धारा 2 (1)(क) – बालकों के विरुद्ध अपराध – दण्ड नीति – पॉक्सो अधिनियम इस प्रकार के अपराधों में अधिक कठोर दण्ड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था – समाज पर निवारक प्रभाव के लिए न्यूनतम दण्ड निर्धारित किया गया है – न्यूनतम निर्धारित दण्ड से कम दण्ड नहीं दिया जा सकता, भले ही अभियुक्त जीवन में आगे बढ़ गया हो।	264	416
Sections 5 (I)/6 and 5 (j) (ii)/6 – (i) Child – Effect on bail application when prosecutrix gave evidence that she had eloped with the accused on her own volition.		
(ii) Public awareness – Provisions of the Act do not distinguish between rape and statutory rape.		
धारा 5 (ठ)/6 एवं 5 (ज) (ii)/6 – (i) किशोर – जमानत आवेदन पर प्रभाव जहाँ अभियोक्त्री ने यह साक्ष्य दी कि वह अपनी इच्छा से अभियुक्त के साथ चली गई थी।		
(ii) लोक-जागरूकता – अधिनियम के प्रावधान बलात्संग एवं कानूनी बलात्संग में अंतर नहीं करते।	205	292
PROTECTION OF DEBTORS ACT, 1937 (M.P.)		
ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, 1937 (म.प्र.)		
Sections 3 and 4 – See sections 107 and 306 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 4 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 107 एवं 306।	141	197
PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005		
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005		
Section 12 – See section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 12 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।	45	64
PUBLIC TRUSTS ACT, 1951 (M.P.)		
लोक न्यास अधिनियम, 1951 (म.प्र.)		
Sections 4, 32 and 36 – See sections 2, 3 (e) and 32 of the Society Registrarian Adhiniyam, 1973 (M.P.).		
धाराएं 4, 32 एवं 36 – देखें सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (म.प्र.) की धाराएं 2, 3 (ड) एवं 32।	207	296
REGISTRATION ACT, 1908		

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908

Section 17 – Suit for possession on the basis of title which was acquired through registered sale deed – Legal impact and effect of registered sale deed – Sale deed duly executed and registered, having endorsement of payment of consideration amounting to full transfer of ownership.

Counter-claim – Defendant could not be permitted to raise counter-claim against a co-defendant – Therefore, *inter-se* dispute on validity of sale deed between defendants, could not be considered in a suit filed by plaintiff for possession on the basis of sale deed.

धारा 17 – रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित स्वत्व पर आधारित कब्जे का वाद – रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का विधिक प्रभाव एवं परिणाम – उचित रूप से निष्पादित और रजिस्टर्ड विक्रय विलेख जिसमें प्रतिफल के भुगतान की टीप है, वह स्वत्व के पूर्ण अंतरण के समान है।

प्रतिदावा – प्रतिवादी को सहप्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिदावा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता – इसलिए विक्रय विलेख के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत कब्जे के वाद में विक्रय विलेख की वैधता के संबंध में प्रतिवादी गण के मध्य के विवाद पर विचार नहीं किया जा सकता। **268(i) & (iii) 421**

Sections 17 and 49 – (i) Compulsory registration of document – Effect of non-registration.

(ii) Collateral transaction – Must be independent/divisible – Does not affect right, title or interests of parties.

धारा 17 और 49 – (i) दस्तावेज का अनिवार्य पंजीकरण–अपंजीकरण का प्रभाव।

(ii) संपार्श्विक संब्यवहार – स्वतंत्र/विभाज्य होना चाहिए – पक्षकारों के अधिकार, शीर्षक या हित को प्रभावित नहीं करता। **36 52**

REPRESENTATION OF PEOPLES ACT, 1951**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**

Section 29A (5) – See sections 420, 463, 465, 468, 471 r/w/s 120 B of the Indian Penal Code, 1860

धारा 29क (5) – देखें धाराएं 420, 463, 465, 468, 471 सहपठित धारा 120 ख भारतीय दण्ड संहिता, 1860 **255 397**

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 24 (1) – Initiation of proceedings of land acquisition under the Act, 1894 – For the purpose of section 24(1) of the Act, 2013 – When notification u/s 4(1) of the Act, 1894 is issued and published in official gazette of the appropriate Government.		
(ii) Preliminary notification – Importance of.		
(iii) Determination of compensation – Applicability of law – The proceeding under the Act of 1894 shall be treated as initiated on publication of notification u/s 4 of the Act of 1894 and provision of the said Act will be applicable – However, for determination of compensation amount, the provision of Act of 2013 shall be applied.		
धारा 24 (1) – (i) अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का प्रारंभ – अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) के उद्देश्य से – तब प्रारंभ होगी जब अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी हुई और समुचित सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई।		
(ii) प्रारंभिक अधिसूचना – महत्व।		
(iii) प्रतिकर का निर्धारण – विधि की प्रयोज्यता – अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना से कार्यवाही प्रारंभ होना मानी जाएगी और इसी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे – परंतु प्रतिकर के निर्धारण हेतु अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।	206	294
Section 24 (2) – Lapse of acquisition proceeding – Whether failure to take possession of acquired land or non-payment of compensation leads to lapse of acquisition proceedings? Held, No – The word “OR” mentioned in between taking of possession or payment of compensation in section 24 (2) of the Act is to be read as “AND”.		
धारा 24 (2) – अधिग्रहण कार्यवाही का व्यपगत होना – क्या अधिग्रहीत भूमि का कब्जा लेने में विफलता या प्रतिकर का भुगतान न करने से अधिग्रहण की कार्यवाही व्यपगत हो जाती है? अभिनिर्धारित, नहीं – अधिनियम की धारा 24(2) में कब्जा लेने या प्रतिकर के भुगतान के बीच वर्णित “या” शब्द को “और” के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।	119	169
RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005		
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005		
Section 4 (2) – See sections 173 and 207 of Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 4 (2) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 173 एवं 207।	90	132

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

Sections 3 (1) (w) (i) and 3 (2) (v) – See sections 53, 164-A (2), 167 (2) and 173 (2) (h) of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 3 (1) (ब) i एवं 3 (2) (v) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 53, 164-क (2), 167 (2) एवं 173 (2) (ज)। **88** **131**

SOCIETY REGISTRAR ADHINIYAM, 1973 (M.P.)

सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (म.प्र.)

Sections 2, 3 (e) and 32 – (i) Creation of trust – Before passing the order, Civil Court can always see whether provision of the particular Act have been complied or not.

(ii) Applicabilty of the Act – Suit filed by deity through society registred under Adhinyam, 1973 – Subsequently, property was registered as Trust under Act, 1951 – When the property is administered by other enactment then section 36 of the Act, 1951 will not be applicable.

धाराएं 2, 3 (ड) एवं 32 – (i) न्यास का गठन – आदेश पारित करने के पूर्व सिविल न्यायालय यह देख सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं।

(ii) अधिनियम का लागू होना – अधिनियम, 1973 के अंतर्गत मूर्ति की ओर से व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया – तत्पश्चात संपत्ति का पंजीयन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत किया गया – जब संपत्ति का नियंत्रण अन्य अधिनियम से किया जा रहा हो तो अधिनियम, 1951 की धारा 36 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

207 **296**

Sections 18, 32 and 37(2) – Cognizance – Effect when complaint filed by person other than Registrar.

धाराएं 18, 32 एवं 37(2) – संज्ञान – प्रभाव जहाँ परिवाद रजिस्ट्रार के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। **208** **298**

SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

Section 28 – See section 10-A of the Divorce Act, 1869.

धारा 28 – देखें विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10-क।

94 **137**

Section 40-B (3) – See Order 9 Rule 13 of the Civil Procdedure Code, 1908.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 40-ख (3) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 9 नियम 13।	72	108

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

Sections 9 and 22 – (i) Specific performance of contract – Whether prayer clause is a *sine qua non* for granting decree of refund of earnest money? Held, Yes.

(ii) Time is the essence of contract – Provision of penalty clause is provided in the event of breach of contract – Actual loss or damage need not be proved.

धाराएं 9 एवं 22 – (i) अनुबंध का विनिर्दिष्ट अनुपालन – क्या अग्रिम धन वापसी की डिक्री देने के लिए अनुतोष प्रार्थित करना अनिवार्य है? अवधारित, हाँ

(ii) समय – अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में शास्ति संबंधी शर्त का प्रावधान – वास्तविक हानि या क्षति का प्रमाणित होना आवश्यक नहीं। **120** **171**

Section 10 – (i) Amendment in the Act – Prospective in nature and cannot apply to those transactions that took place prior to its coming into force.

(ii) Performance of contract – Limitation – When the time period for performance is not fixed then the purchaser can take recourse to the notice issued but such circumstances do not come into play when fixed time period was clearly mandated in the contract.

(iii) Contract to sell immovable property – Whether time is the essence of contract?

धारा 10 – (i) अधिनियम में संशोधन – प्रकृति में भविष्यवर्ती एवं उन संव्यवहारों पर लागू नहीं जो कि इसके प्रभाव में आने से पूर्व के हैं।

(ii) संविदा का पालन – परिसीमा – जब पालन हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं हो तब क्रेता जारी सूचनापत्र का अवलंब ले सकता है किंतु जब संविदा में निर्धारित समय सीमा स्पष्टतः आदेशित हो तब उक्त परिस्थितियाँ प्रचलन में नहीं आएगी।

(iii) अचल संपत्ति के विक्रय की संविदा – क्या समय संविदा का सार है?

73 **109**

Section 10 and 15 (b) – Suit for specific performance of contract – Conditional sale deed registered with right to repurchase – Enforceable – Right of repurchase always assignable or transferable and cannot be treated as personal to the vendor, unless provided in the terms of the sale-deed itself – Implied prohibition of transfer or assignment cannot be inferred – However, assignment

Act/ Topic	Note No.	Page No.
of obligation is not possible without the consent of the other party – Law discussed and explained.		
धारा 10 एवं 15 (ख) – संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद – पुनः क्रय के अधिकार के साथ सशर्त विक्रय विलेख रजिस्टर्ड – प्रवर्तनीय – पुनः क्रय का अधिकार हमेशा समनुदेशनीय अथवा अंतरणीय होता है एवं इसे विक्रेता का व्यक्तिगत अधिकार होना मान्य नहीं किया जा सकता, जब तक कि विक्रय विलेख की शर्तों में ही इसका उल्लेख न हो – अंतरण अथवा समनुदेशन की विवक्षित रोक का अनुमान नहीं लगाया जा सकता – तथापि, दायित्व का समनुदेशन दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना संभव नहीं – विधि पर विचार कर स्पष्ट किया गया।	265	417
Section 16 – Readiness and Willingness – Effect of non-production of account and pass books.		
धारा 16 – तैयारी और तत्परता – खाता और पासबुक प्रस्तुत न करने का प्रभाव।	121	172
Section 16 (c) – See Order 21 Rules 84, 85 and 90 of Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 16 (ग) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 21 नियम 84, 85 और 90।	84	125
Section 16 (c) – Specific performance of contract – Effect when subsequent deposit of balance consideration was made by the plaintiff after lapse of seven years.		
धारा 16 (ग) – संविदा का विनिर्दिष्ट पालन – सात वर्ष व्यतीत होने के उपरांत अवशेष प्रतिफल का पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर वादी द्वारा जमा किये जाने पर प्रभाव।	74	111
Section 20 – Suit for specific performance – Bar of limitation of 3 years when no time is fixed for performance of contract – Time period shall run from the date plaintiff had noticed that the performance was refused by defendant – Suit was held to be barred by limitation.		
धारा 20 – विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद – संविदा के अनुपालन हेतु जहां कोई समय निश्चित नहीं है वहां परिसीमा काल तीन वर्ष है – समय सीमा तब से आरंभ होगी जब वादी को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी ने अनुपालन से इंकार कर दिया है – वाद अवधि बाह्य निर्धारित किया गया।	256	399
Section 20 – Suit for specific performance of contract – When adverse inference can be drawn?		
धारा 20 – संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद – कब प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है?	75*	112

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 21 – Suit for specific performance – Effect of words “in addition to” incorporated in Section 21 of the Act.		
धारा 21 – विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद – अधिनियम की धारा 21 में सम्मिलित शब्द “अतिरिक्त” का प्रभाव।	8 (ii)	7
Section 28 – Decree of specific performance – Delay in paying balance consideration – Held, discretion has to be exercised judiciously and delay ought not to have been condoned.		
धारा 28 – विनिर्दिष्ट अनुतोष की डिक्री – वादी द्वारा बकाया विक्रय राशि देने में विलम्ब किया गया – अभिनिर्धारित, विवेकाधिकार का उपयोग न्यायसंगत रूप से किया जाना चाहिए एवं विलंब को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए था।	209	299
Section 34 – (i) Partition deed – Certified copy is admissible only after getting permission to file secondary evidence.		
(ii) Relinquishment deed – Admitted only when original registered deed was presented or permission to file a copy as secondary evidence was granted.		
धारा 34 – (i) विभाजन विलेख – द्वितीय साक्ष्य की अनुमति लेने के पश्चात् ही प्रमाणित प्रतिसाक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकती है।		
(ii) परित्याग पत्र – केवल तभी साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है जब असल पंजीकृत विलेख प्रस्तुत किया जाये या द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रतिप्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जावे।	37	53
Section 34 – Possession – Relief – To get decree of possession over suit land, plaintiff has to prove that he has a better right in form of ownership or entitlement to possession than the person who is in possession.		
धारा 34 – आधिपत्य – अनुतोष – आधिपत्य की आज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु यह प्रमाणित करना होगा कि वादी के पास आधिपत्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति से बेहतर स्वामित्व या आधिपत्य रखने का अधिकार है।	211	303
Section 34 – Possession of one co-owner is possession of all co-owners.		
धारा 34 – एक सहस्वामी का कब्जा, सभी सहस्वामी का कब्जा मान्य।	76 (i)	113
Section 34 – (i) Sale by co-sharer – Effect on validity of sale deed where father of plaintiff had sold the share of the undivided joint Hindu family property to be received by the plaintiff during his minority.		
(ii) Appeal in consolidated suits – Aggrieved party is required to file two appeals even if a common judgment is passed in two civil suits.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 34 – (i) सह-अंशधारी द्वारा विक्रय – विक्रय पत्र की वैधता पर प्रभाव जहाँ वादी के पिता ने अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में अवयस्क वादी को प्राप्त होने वाले भाग का भी विक्रय कर दिया था।		
(ii) समेकित वादों में अपील – एकल अपील की पोषणीयता – व्यथित पक्षकार से अपेक्षित है कि वह दो अपील प्रस्तुत करे यद्यपि दो व्यवहार वाद में एक ही निर्णय पारित किया गया है।	210	301
Section 34 – (i) Suit for declaration – Cancellation of sale deed was necessary only where it is alleged to be voidable on facts.		
(ii) Legal maxim <i>non est factum</i> explained.		
धारा 34 – (i) घोषणा हेतु वाद – जहां तथ्यों से विक्रय विलेख शून्यकरणीय होना आक्षेपित है वहीं उसका रद्द कराया जाना आवश्यक है।		
(ii) लीगल मैग्जिम <i>नॉन एस्ट फैक्टम</i> को समझाया गया।	266	418
Section 34 – When suit is barred by proviso to Section 34 for not claiming relief of possession? Proper approach.		
धारा 34 – कब्जे के अनुतोषकी मांग नहीं करने के कारण कब वाद धारा 34 के परंतुक से वर्जित है? उचित दृष्टिकोण।	77	113
Sections 34 and 38 – Suit for declaration and permanent injunction – Registered sale deed executed by Power of Attorney holder (defendant) in favour of his son – Presumption of valid execution of registered document and proof of contents of the same are two different aspects.		
धाराएं 34 एवं 38 – घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश के लिए वाद – पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक (प्रतिवादी) द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित – रजिस्टर्ड दस्तावेज के उचित निष्पादन की उपधारणा एवं उसकी अंतर्वस्तु का प्रमाणन दो पृथक पहलू हैं।	267	419
Sections 34 and 38 – (i) Suit for possession and permanent injunction – When appellants were not a ‘transferee’ within the meaning of section 51 of the Act?		
(ii) Principle of acquiescence – Appellants had done construction without a <i>bona fide</i> belief of land being their own – Doctrine of acquiescence not applicable.		
धाराएं 34 एवं 38 – (i) आधिपत्य एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद – कब अपीलार्थी अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत ‘अंतरिती’ नहीं माने जा सकते?		
(ii) उपमति का सिद्धांत – अपीलार्थी ने बिना इस सद्भावी विश्वास के निर्माण किया था कि भूमि उसकी स्वयं की है – उपमति का सिद्धांत लागू नहीं होता।	212	304

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

STAMP ACT, 1899

स्टाम्प अधिनियम, 1899

Sections 33 and 35 (c) – Stamp duty – Under section 35 (c) of the Act, if agreement was made of two or more letters and any of the letter bears proper stamp, agreement to sale shall be deemed to be duly stamped.

धाराएं 33 एवं 35 (ग) – स्टाम्प शुल्क – अधिनियम की धारा 35(ग) के अनुसार, जहां करार दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने और किसी एक पर उचित स्टॉम्प लगा हो वहां करार सम्यक रूप से स्टॉम्पित है, समझा जाएगा ।

213 306

Section 35 – See sections 17 and 49 of the Registration Act, 1908.

धारा 35 – देखें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धाराएं 17 और 49 ।

36 52

SUCCESSION ACT, 1925

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

Section 63 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963 and section 68 of the Evidence Act, 1872.

धारा 63 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68।

76 113

TRADE MARKS ACT, 1999

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

Section 29 (2) (c) – (i) Infringement of Trade Mark – Suit for injunction – Plea of distinctive features taken by the respondent – Held, subsequent registration does not entitle the respondent to use deceptively similar trade mark.

(ii) Territorial jurisdiction – Cause of action has arisen within the territorial jurisdiction of Jabalpur inasmuch as defendants are carrying business in Jabalpur, therefore, Jabalpur court has jurisdiction to try the suit in respect of the registered trade mark.

धारा 29 (2) (ग) – (i) व्यापार चिन्ह का अतिलंघन – व्यादेश हेतु वाद – प्रत्यर्थी द्वारा विशिष्ट लक्षण का अभिवाक् लिया गया – अभिनिर्धारित, पश्चात्वर्ती पंजीकरण प्रत्यर्थी को भ्रामक समरूप व्यापार चिन्ह लेने हेतु अधिकृत नहीं करता है ।

(ii) क्षेत्रीय अधिकारिता – वादकारण जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न हुआ जैसाकि प्रतिवादीगण जबलपुर में व्यवसाय कर रहे हैं, इस प्रकार जबलपुर

Act/ Topic	Note No.	Page No.
न्यायालय को पंजीकृत ट्रेडमार्क के संबंध में वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।	163	226
TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882		
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882		
Section 5 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 5 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34।	37	53
Section 6 (a) – See section 8 (a) of Hindu Succession Act, 1956.		
धारा 6 (क) – देखें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8(क)।	140	195
Section 48 – Multiple sale deeds – Executed by owner/ <i>Bhumiswami</i> of the same land – Principle of priority of rights created by transfer applies – Each previous sale deed will prevail over the later sale deeds.		
धारा 48 – एकाधिक विक्रय विलेख – एक ही स्वामी/भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित – अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता का सिद्धांत लागू – पूर्ववर्ती विक्रय विलेख पश्चात्वर्ती विक्रय विलेख पर अभिभावी होंगे।	122	174
Section 51 – See sections 34 and 38 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 51 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 34 एवं 38।	212	304
Section 53 - A – (i) Suit for possession – When can protection u/s 53-A of the Act, 1882 be claimed?		
(ii) Adverse possession – Agreement to sale was executed between parties – Possession was permissive – Plea of adverse possession not accepted.		
धारा 53 – क – (i) आधिपत्य हेतु वाद – कब अधिनियम की धारा 53-क का संरक्षण अधियाचित किया जा सकता है?		
(ii) विरोधी आधिपत्य – उभयपक्ष के मध्य विक्रय हेतु अनुबंध निष्पादित हुआ था – आधिपत्य अनुमत था – विरोधी आधिपत्य का अभिवाक् स्वीकार नहीं किया गया।	214	307
Section 54 – See sections 17 and 103 of the Evidence Act, 1872 and section 17 of the Registration Act, 1908		
धारा 54 – देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 17 एवं 103 और रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17	268	421
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967		
Sections 39, 40 and 43 D (5) – See section 439 (2) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 39, 40 एवं 43 घ (5) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा	439 (2)।	
	179	250

WORKMEN'S COMPENSATION ACT, 1923

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

Sections 2 (1) and 4 (1)(b) – Assessment of compensation – Unskilled labour – Claimant not skilled for performing any other work with one hand thereby suffering 100 % loss of earning capacity – Compensated accordingly.

धाराएं 2 (1) और 4 (1)(ख) – प्रतिकर का आकलन – अकुशल श्रमिक – दावेदार एक हाथ से कोई अन्य कार्य करने के लिए कुशल नहीं है, दावेदार को कुल कार्यात्मक निर्योग्यता के परिणामस्वरूप अर्जन क्षमता का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है – तदनुसार प्रतिकर दिया गया।

269 423

PART - II A

(GUIDELINES)

- | | |
|--|-----------|
| 1. Guidelines issued by Hon'ble Supreme Court to be followed in Motor Accident Claim Cases. | 1 |
| 2. Guidelines issued by Hon'ble Supreme Court to be followed in matters pertaining to Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. | 5 |
| 3. Guidelines issued with regard to accused who are Foreign Nationals. | 7 |
| 4. Guidelines issued by Hon'ble Supreme Court to be followed in civil matters. | 11 |
| 5. Guidelines to be followed in matters pertaining to SARFAESI Act. | 14 |

PART - III

Act/ Topic	Note No.	Page No.
-------------------	-----------------	-----------------

(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

1. Notification dated 24.02.2023 regarding jurisdiction in Motor Accident Claim Cases.		1
2. Notification dated 22.03.2023 regarding date of enforcement of Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022.		3
3. Notification dated 22.06.2023 of the Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh regarding Amendment in Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994.		5
4. Notification dated 12.07.2023 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi regarding disposal of wild animal articles.		13
5. Notification dated 02.08.2023 of the Department of Law and Legislative Affairs Government of Madhya Pradesh regarding admissibility of documents.		14
6. Notification dated 20.09.2023 of the High Court of Madhya Pradesh regarding guidelines to be followed in matters of detention.		15
7. Notification dated 22.11.2023 of the High Court of Madhya Pradesh regarding amendment in Civil Court.		17

PART - IV

(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)

1. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Seizure, Storage, Sampling and Disposal) Rules, 2022.		1
2. मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022).		23
3. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022.		24
4. The Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) Act, 2022.		24
5. Notification dated 16.05.2023 regarding amendment in Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal).		28
6. The Mediation Act, 2023.		31

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
1	A. Valliammai v. K.P. Murali and ors.	AIR 2023 SC 4375	256	399
2	Abhishek Parashar v. Neha Parashar	2023 (1) MPLJ 648 (DB)	99	142
3	Ajai alias Ajju & ors. v. State of Uttar Pradrsh	2023 (1) Crimes 204 (SC)	89	131
4	Ajay Dabra v. Pyare Ram and ors.	2023 (2) MPLJ 38 (SC)	109	155
5	Ajmal v. State of Kerala	(2022) 9 SCC 766	24	36
6	Akhilesh Kumar alias Hansu and anr. v. Saradchandra Bhate and anr.	2023 (2) MPLJ 401	129	182
7	Aman Sharma and anr. v. Umesh and ors.	(2022) 8 SCC 798	9	10
8	Amanullah Khan v. State of Haryana and anr.	AIR 2022 SC 4158	*29	45
9	Amrik Singh v. State of Punjab	(2022) 9 SCC 402	20	28
10	Anand Deep Singh and ors. v. State of Madhya Pradesh and ors.	AIR 2022 MP 145 (DB)	*5	5
11	Anand Kumar and anr. v. Lakhan	2023 (1) MPLJ 457	54	78
12	Anbazhagan v. State Represented by the Inspector of Police	AIR 2023 SC 3660	246	377
13	Anil Kumar Jain v. Maniram Singraha and ors.	2022 (4) MPLJ 177	6	6
14	Anil Kumar Lohadiya v. Ramlal Gupta (deceased) through LRs.	ILR 2023 MP 736	160	223
15	Anil Kumar Modi and ors. v. Tarsem Kumar Gupta	(2023) 2 SCC 201	126	178
16	Anil Patel v. State of M.P.	ILR 2023 MP 1265	198	281
17	Anil Tiwari v. Laxmi Devi (Dead) and ors.	AIR 2023 MP 1	171	239

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
18	Anjali and ors. v. Lokendra Rathod and ors.	2023 (1) MPLJ 415 (SC)	67	98
19	Anjana Narayan Kamble v. Branch Manager, Reliance General Ins. Co. Ltd. and anr.	2023 ACJ 346	110	156
20	Ankit Kothari v. State of M.P.	ILR 2023 MP 1283 (DB)	176	245
21	Anoop Mishra & ors. v. Alka Dubey & ors.	ILR 2023 MP 1277	208	298
22	Arvind Kumar v. State of NCT, Delhi	AIR 2023 SC 3653	247	382
23	Ashish Chaturvedi v. State of M.P.	ILR 2023 MP 155 (DB)	103	146
24	Ashish Tiwari v. State of M.P. and ors.	2023 (2) MPLJ 647 (DB)	191	269
25	Ashok Kumar v. Vimla Devi & anr.	ILR 2023 MP 668	151	213
26	Ashok Shewakramani and ors. v. State of Andhra Pradesh and anr.	(2023) 8 SCC 473	262	408
27	Avinash Kumar Ray v. Dr. Ku. Chhaya Ray and ors.	2023 (1) MPLJ 515	81	119
28	Avtar Singh & anr. v. State of Punjab	2023 (2) Crimes 12 (SC)	96	140
29	Awdhesh Kumari and ors. v. Harishchandra and ors.	2022 ACJ 2440 (SC)	*65	97
30	B.V. Sessaiah v. State of Telangana and anr.	2023 (2) MPLJ 281 (SC)	162	225
31	Babanrao Rajaram Pund v. Samarth Builders and Developers and anr.	(2022) 9 SCC 691	1	1
32	Babla v. State of M.P..	ILR 2023 MP 1437 (DB)	245	375
33	Baini Prasad (D) thr. LRs. v. Durga Devi	2023 (2) MPLJ 551	212	304

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
34	Bajesingh & anr. v. Leelabai & anr.	ILR 2023 MP 1218	214	307
35	Balwantbhai Somabhai Bhandari v. Hiralal Somabhai Contractor (deceased) rep. by LRs.	AIR 2023 SC 4390	227	333
36	Basawaraj v. Padmavathi and anr.	(2023) 4 SCC 239	121	172
37	Bhagwan Singh v. Dilip Kumar	AIR 2023 SC 4165	235	352
38	Bhagwantibai and ors. v. Rajendra Kumar	AIR 2022 MP 120	43	62
39	Bharat Sanchar Nigam Limited v. M/s. Nemichand Damodardas and anr.	AIR 2022 SC 3458	61	93
40	Bhimashankar Sahakari Sakkare Karkhane Niyamita v. Walchandnagar Industries Limited (WIL)	(2023) 8 SCC 453	217	311
41	Bimla Tiwari v. State of Bihar and ors.	2023 (1) Crimes 271 (SC)	93	136
42	BLS Infrastructure Limited v. Rajwant Singh and ors.	(2023) 4 SCC 326	114	162
43	Brij Raj Oberoi v. Secretary, Tourism and Civil Aviation Department and anr.	AIR 2022 SC 3815	3	4
44	Bugdad v. State of M.P.	ILR 2023 MP 580	134	189
45	C.S. Ramaswamy v. V.K. Senthil and ors.	2023 (1) MPLJ 572 (SC)	83	123
46	Central Bureau of Investigation v. Narottam Dhakad	AIR 2023 SC 4066	230	240
47	Central Bureau of Investigation v. P.S. Jayaprakash and anr.	(2023) 1 SCC 314	*51	75
48	Central Bureau of Investigation v. Vikas Mishra alias Vikash Mishra	(2023) 6 SCC 49	174	243

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
49	Chandra Shekhar v. State of M.P.	ILR 2023 MP 1462 (DB)	263	411
50	Chaus Taushif Alimiya and anr. v. Memon Mahmmd Umar Anwarbhai and ors.	2023 ACJ 726	196	278
51	Chherturam alias Chainu v. State of Chhattisgarh	(2022) 9 SCC 571	23	35
52	Chokhelal and ors. v. Ashwani Kumar and ors.	AIR 2022 MP 157	21	30
53	Chotkau v. State of Uttar Pradesh	(2023) 6 SCC 742 (3 Judge Bench)	253	393
54	Damodhar Narayan Sawale (D) through LRs. v. Tejrao Bajirao Mhaske and ors.	AIR 2023 SC 3319	268	421
55	Danish Rayin v. State of M.P. & ors.	ILR 2023 MP 1378	239	364
56	Dashrathbhai Trikambhai Patel v. Hitesh Mahendrabhai Patel and anr.	(2023) 1 SCC 578	113	160
57	Dauvaram Nirmalkar v. State of Chhattisgarh	AIR 2022 SC 3620	25	40
58	Dayaram v. Smt. Laxmi Agrawal	ILR 2023 MP 263	133	187
59	Deepak Gaba and ors. v. State of Uttar Pradesh and anr.	2023 (1) Crimes 1 (SC)	150	212
60	Delhi Development Authority v. Diwan Chand Anand and ors.	(2022) 10 SCC 428	41	60
61	Derha v. Vishal and anr.	AIR 2023 SC 4180	241	369
62	Desh Raj and ors. v. Rohtash Singh	(2023) 3 SCC 714	120	171
63	Dharamdas Tirathdas Constructions Pvt. Ltd., Indore v. Union of India and anr.	2023 (2) MPLJ 111	79	116
64	Dheeraj Rohra v. Shyam Bihari Pandey	2023 (2) MPLJ 104	123	175

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
65	Dheeraj Singh v. Greater Noida Industrial Development Authority and ors.	AIR 2023 SC 3110	225	328
66	Dilip Kumar Puri v. State of M.P. & anr.	ILR 2023 MP 1508	229	338
67	Dilip Sikdar v. State of M.P. and anr.	ILR 2023 MP 174	88	131
68	Dr. S.M. Mansoori (Dead) Through Legal Representatives v. Surekha Parmar and ors.	(2023) 6 SCC 156	175	244
69	Dwarika Prasad Patel v. Smt. Marri	ILR 2023 MP 1200	182	257
70	Elumalai @ Venkatesan and anr. v. M. Kamala and ors. and etc.	2023 (2) MPLJ 1 (SC)	140	195
71	Essar House Private Limited v. Arcelor Mittal Nippon Steel India Limited	AIR 2022 SC 4294 (3 Judge Bench)	2	3
72	Fatima Bi (Smt.) (dead) & ors. v. Ku. Najnin & ors.	ILR 2023 MP 512	122	174
73	Firoz Khan v. State of M.P. and ors.	2022 (4) MPLJ 4	33	50
74	G . Vivek v. National Insurance Co. Ltd. and anr.	2023 ACJ 585 (SC)	158	220
75	G.N.R. Babu @ S.N. Babu v. Dr. B.C. Muthappa and ors.	AIR 2022 SC 4213	*4	5
76	Ganpatlal v. Ganga Bai & ors.	ILR 2023 MP 496	77	113
77	Gas Point Petroleum India Ltd. v. Rajendra Marothi and ors.	2023 (2) MPLJ 216 (SC)	84	125
78	Geeta Paliwal and ors. v. Sitaram and ors.	2023 (2) MPLJ 513	190	268
79	Gopal Krishna Gautam @ Pandit v. Union of India	ILR (2023) MP 561	112	158

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
80	Government of NCT of Delhi and anr. v. Ram Prakash Sehrawat and ors.	(2023) 2 SCC 348	119	169
81	Govind v. State of M.P.	ILR 2023 MP 342	141	197
82	Gujrat Composite Limited v. A Infrastructure Limited and ors.	(2023) 7 SCC 193	165	230
83	Guna Mahto v. State of Jharkhand	(2023) 6 SCC 817	244	374
84	Gurmail Singh and anr. v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2022) 10 SCC 684	107	152
85	Harpreet Kaur and ors. v. Mohinder Yadav and ors.	2023 ACJ 799	193	272
86	Haryana State Industrial and infrastructure Development Corporation Limited and ors. v. Deepak Aggarwal and ors.	(2023) 6 SCC 512 (3 Judge Bench)	206	294
87	Hasananand v. Vinod & anr.	ILR 2023 MP 1391	222	324
88	Hazara Bi (dead) and ors. v. Abdul Karim	2023 (1) MPLJ 500	80	118
89	Hindustan Bidi Manufacturing, Nadia v. Sunderlal Chhabilal and anr.	2022 (4) MPLJ 582	163	226
90	In Reference v. Ramjag Bind	ILR 2023 MP 717 (DB)	143	201
91	Indira Devi v. Veena Gupta and ors.	(2023) 8 SCC 124	265	417
92	Indra Bai v. Oriental Insurance Co. Ltd. and anr.	(2023) ACJ 1473	269	423
93	Jabir and ors. v. State of Uttarakhand	AIR 2023 SC 488	185	260
94	Jagdish Singh Kaurav v. Sate of M.P. & ors.	ILR 2023 MP 326	137	192
95	Jagtar Singh v. State of Punjab	2023 (2) Crimes 14 (SC)	116	164
96	Janki Prasad v. Rambali Lodhi and ors.	2023 (2) MPLJ 668	210	301

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
97	Jaycee Housing Private Limited and ors. v. Registrar (General), Orissa High Court, Cuttack and ors.	(2023) 1 SCC 549	86	128
98	John Anthonisamy alias John v. State	(2023) 3 SCC 536	144	202
99	Juhru & ors. v. Karim & anr.	2023 (1) Crimes 237 (SC)	136	191
100	Kailash and anr. v. Kaluram and ors.	ILR 2023 MP 817	169	235
101	Kalicharan and ors. v. State of Uttar Pradesh	(2023) 2 SCC 583	91	134
102	Kamal Khudal v. State of Assam	AIR 2022 SC 3341	55	80
103	Kamla Neti (Dead) through LRs v. Special Land Acquisition Officer and ors.	(2023) 3 SCC 528	102	145
104	Kamod Singh v. State of M.P.	ILR 2023 MP 1421 (DB)	251	390
105	Katta Sujatha Reddy and anr. v. Siddamsetty Infra Projects Private Limited and ors.	(2023) 1 SCC 355	73	109
106	Kekhriesatuo Tep and ors. v. National Investigation Agency	(2023) 6 SCC 58	179	250
107	Krishna Gopal Khandelwal v. Poonamchand Paharia (dead) through LRs. Smt. Prabhawati and ors.	2023(3) MPLJ 622	215	309
108	Ku. Mangla Deshore v. Mst. Krishna Bai (dead) by LRs. A. Madhusudan and ors.	2023 (1) MPLJ 330	62	94
109	Kunal Kant Saxena v. Sangeeta and anr.	2023 (2) MPLJ 234 (DB)	*101	145
110	Kunti and anr. v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2023) 6 SCC 109	188	266

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
111	L.K. Chauhan v. Munija Akeel	ILR 2023 MP 921	200	283
112	Lalankumar Singh & ors. v. State of Maharashtra	2022 (4) Crimes 412 (SC)	47	67
113	Laxmi Devi Kushwah and ors. v. Uttam Singh Rathore and anr.	2023 ACJ 675	152	214
114	Laxmi Srinavasa R and P Boiled Rice Mill v. State of A.P. and anr.	2023 (1) MPLJ 410 (SC)	63	95
115	Lee Anne v. Arunoday Singh	2023 (1) MPLJ 264	72	108
116	Life Insurance Corporation of India v. Sanjeev Builders Pvt. Ltd. and anr.	AIR 2022 SC 4256	8	7
117	M/s. Alpine Housing Development Corporation Pvt. Ltd. v. Ashok S. Dhariwal and ors.	AIR 2023 SC 558	167	231
118	M/s. Patil Automation Private Limited and ors. v. Rakheja Engineers Private Limited	AIR 2022 SC 3848	11	12
119	M/s. Shivali Enterprises v. Smt. Godawari (Deceased) thr. LRs. and ors.	AIR 2022 SC 4388	*75	112
120	M/s. Trinity Infraventures Ltd. and ors. Etc. v. M.S. Murthy and ors. Etc.	AIR 2023 SC 3361	218	314
121	Majid Beg and ors. v. Shri Tej Pratap Singh	ILR (2023) MP 97 (DB)	87	129
122	Manager, Magma HDI General Insurance Co. Ltd., Kolkata v. Puja Bhalavi and ors.	2023 (1) MPLJ 454	66	97
123	Manish Singh Malukani and ors. v. Hari Prasad Gupta and anr.	AIR 2022 MP 150	*36	53
124	Manoj Pratap Singh v. State of Rajasthan	(2022) 9 SCC 81 (3 Judge Bench)	146	204

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
125	Maringmei Acham v. M. Maringmei Khuripou	(2023) 2 SCC 473	*130	184
126	Mathew Alexander v. Mohammed Shafi and anr.	AIR 2023 SC 3349	260	405
127	Md. Asfak Alam v. State of Jharkhand and anr.	AIR 2023 SC 3610	232	344
128	Meena Devi v. Nunu Chand Mahto and ors.	2022 ACJ 2478	68	101
129	Mekala Sivaiah v. State of Andhra Pradesh	AIR 2022 SC 3378	58	85
130	Milind v. State of M.P.	ILR 2023 MP 407	138	193
131	Mita India Pvt. Ltd. v. Mahendra Jain	2023 (1) Crimes 233 (SC)	115	163
132	Mohamed Ali v. V. Jaya and ors.	(2022) 10 SCC 477	40	58
133	Mohammad Shafi and ors. v. Chand Khan and ors.	2023(3) MPLJ 631	219	316
134	Mohammad Wajid and anr. v. State of U.P. and ors.	AIR 2023 SC 3784	254	395
135	Mohammed Zubair v. State of NCT of Delhi and ors.	AIR 2022 SC 3649 (3 Judge Bench)	12	14
136	Mohd. Arif alias Ashfaq v. State (NCT of Delhi)	(2023) 3 SCC 654	*97	141
137	Mohd. Muslim v. State of Uttar Pradesh (Now Uttarakhand)	AIR 2023 SC 3086	228	335
138	Mohd. Sabeer alias Shabir Hussain v. Regional Manager, U.P. State Road Transport Corporation	AIR 2023 SC 186	197	279
139	Muhammed v. United India Insurance Co. Ltd. and ors.	2023 ACJ 894	192	270
140	Mukesh Singh v. State (NCT of Delhi)	AIR 2023 SC 4097	237	359
141	Munna Lal v. State of Uttar Pradesh	2023 (1) Crimes 294 (SC)	106	150

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
142	Munna Prasad Verma v. State of U.P. and anr.	2022 (3) Crimes 280 (SC)	*27	43
143	N. Ramkumar v. State rep. by Inspector of Police	AIR 2023 SC 4246	252	392
144	Naim Ahmed v. State (NCT of Delhi)	2023 (1) Crimes 318 (SC)	104	148
145	Narcotics Control Bureau v. Mohit Aggarwal	AIR 2022 SC 3444 (3 Judge Bench)	69	103
146	Narendra v. Narendra and anr.	ILR 2023 MP 836	164	229
147	National Insurance Co. Ltd., Jabalpur v. Sunita and ors.	2023 (1) MPLJ 711	154	216
148	Naveen v. State of Haryana and ors.	2022 (4) Crimes 439 (SC)	49	70
149	Neeraj Dutta v. State (Govt. of NCT of Delhi)	AIR 2023 SC 330 (5 Judge Bench)	202	285
150	Nerella Chiranjeevi Arun Kumar v. State of Andhra Pradesh and anr.	2022 (3) Crimes 279 (SC)	*46	67
151	New Okhla Industrial Development Authority (Noida) v. Yunus and ors.	(2022) 9 SCC 516	30	45
152	Nidhi and ors. v. Mahaveer Singh and ors.	2022 ACJ 2360	31	47
153	Nirmala Devi v. State of Himachal Pradesh	AIR 2023 SC 3683	248	384
154	Nisha Kotwani and ors. v. Hamid Khan and ors.	2023 (1) MPLJ 601	111	158
155	No.15138812YL/Nk Gursewak Singh v. Union of India and anr.	AIR 2023 SC 3569	249	385
156	Noor Mohammed v. Khurram Pasha	AIR 2022 SC 3592 (3 Judge Bench)	34	51
157	OMFR Pipes and Products, Bhopal and anr. v. Itarsi Pipe Sales, Itarsi and ors.	2023 (2) MPLJ 210 (DB)	82	121

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
158	Omprakash Sahni v. Jai Shankar Chaudhary and anr.	(2023) 6 SCC 123	178	248
159	Omprakash v. Ashok & ors.	ILR 2023 MP 267	132	185
160	Oriental Bank of Commerce v. Prabodh Kumar Tiwari	2022 (3) Crimes 345 (SC)	70	104
161	P. Shyamala v. Gundlur Masthan	2023 (2) MPLJ 562	209	299
162	P. Vijay Nataraj and ors. v. State and anr.	(2022) 9 SCC 280	28	43
163	Pappu v. State of Uttar Pradesh	(2022) 10 SCC 321 (3 Judge Bench)	56	82
164	Parvez Parwaz and anr. v. State of Uttar Pradesh and ors.	2022 (3) Crimes 360 (SC) (3 Judge Bench)	16	24
165	Pawan Kumar Goel v. State of U.P. and anr.	2023 (2) MPLJ 19 (SC)	161	224
166	Pradeep Singh Sengar and ors. v. Dilip Budhani and ors.	2023(3) MPLJ 613	220	321
167	Prakashveer v. Murti Shri Dwarikadheesh Maharaj Virajman Mandir Thakur Dwarikadheeshji Morar, Gwalior Society and anr.	2023 (2) MPLJ 584	207	296
168	Praveen Malpani v. M/s. Vijay Electricals & ors.	ILR 2023 MP 247	*139	195
169	Prem Kumar v. Rajnish	ILR 2023 MP 197	159	222
170	Prem Singh v. State of NCT of Delhi	AIR 2023 SC 193	186	261
171	Premchand v. State of Maharashtra	(2023) 5 SCC 522	177	246
172	Premlal Kadak and ors.v. Madhukar Kadak and ors.	2022 (4) MPLJ 116	37	53
173	Pritinder Singh alias Lovely v. State of Punjab	(2023) 7 SCC 727	236	355
174	Pritish Nandi & anr. v. Not Mentioned	ILR 2023 MP 478	94	137

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
175	Pushpalata v. Vijay Kumar (Dead) thr. L.Rs. and ors.	2023 (1) MPLJ 305 (SC) (3 Judge Bench)	38	55
176	Pushpendra Kumar Sinha v. State of Jharkhand	AIR 2022 SC 3983 (3 Judge Bench)	18	26
177	R. Krsna Murtii v. R.R. Jagadesan	AIR 2022 SC 3477	42	61
178	Radhey Shyam and ors. v. State of Rajasthan	(2023) 6 SCC 151	180	251
179	Raghuvansh and ors. v. Ramkali and ors.	2023(3) MPLJ 655	238	362
180	Rahul Ganpatrao Sable v. Laxman Maruti Jadhav (dead) through LRs and ors.	(2023) ACJ 1465 (SC)	259	403
181	Rajan v. Anil Varghese and anr.	2023 ACJ 816	194	275
182	Rajaram Sriramulu Naidu (Since Deceased) Through LRs. v. Maruthachalam (Since Deceased) Through Lrs.	AIR 2023 SC 471	199	282
183	Rajaram v. State of Madhya Pradesh and ors.	AIR 2023 SC 94	181	252
184	Rajendra Singh Lodhi and ors. v. State of M.P. and anr.	ILR 2023 MP 892	184	259
185	Rajkumar Agarawal (M/s) v. Union of India and ors.	2023 (2) MPLJ 593 (DB)	166	231
186	Rajnish v. Neha and anr.	2022 (4) Crimes 371 (SC)	45	64
187	Raju @ Rajkumar v. State of M.P.	ILR 2023 MP 319	*149	212
188	Ram Gopal v. State of Madhya Pradesh	2023 (1) Crimes 210 (SC)	105	149
189	Ramabora alias Ramaboraiah and anr. v. State of Karnataka	AIR 2022 SC 3726	14	20
190	Ramanand @ Nandlal Bharti v. State of Uttar Pradesh	2022 (4) Crimes 580 (SC)	59	86

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
191	Ramathal and ors. v. K. Rajamani (Dead) through LRs. and anr.	AIR 2023 SC 3978	266	418
192	Ramesh Kumar v. State of NCT of Delhi	(2023) 7 SCC 461	233	347
193	Ramesh v. Karan Singh and anr.	2022 ACJ 2658 (SC)	*64	96
194	Ramkali (dead) by L.Rs. Anand Kishore Shukla and ors. v. Muritkumari (dead) by L.Rs. Gopal Krishan Pandey and ors.	2023 (1) MPLJ 367	76	113
195	Rana Ayyub v. Directorate of Enforcement	(2023) 4 SCC 357	117	166
196	Ratan Lalchandani v. Gopaldas Kukreja	2023 (2) MPLJ 376 (DB)	124	176
197	Ravi Dhingra v. State of Haryana	(2023) 6 SCC 76	187	263
198	Richa v. Pradhuman	2023 (1) MPLJ 421 (DB)	53	77
199	Ritu v. Sushil	2023 (1) MPLJ 255	52	75
200	Rohit Bishnoi v. State of Rajasthan and anr.	AIR 2023 SC 3547	234	350
201	Rupali Kailas Mamode v. National Insurance Co. Ltd. ors.	2023 ACJ 327	155	217
202	S. Chandrasekharan and ors. v. M. Dinakar and anr.	2022 ACJ 2362	32	48
203	Sangeeta Grover (Smt.) v. Ranjan Grover	ILR (2023) MP 127	100	144
204	Sanjay Ingle and anr. v. Panchfula Bai and anr.	ILR 2023 MP 489	98	141
205	Sanjeet Kumar Singh @ Munna Kumar Singh v. State of Chhattisgarh	2022 (3) Crimes 348 (SC)	35	52
206	Santosh Markam v. State of M.P.	ILR 2023 MP 281 (DB)	148	208
207	Sanwarlal Agrawal and ors. v. Ashok Kumar Kothari and ors.	(2023) 7 SCC 307	168	234

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
208	Sarnam Singh v. Shriram General Insurance Co. Ltd. and ors.	AIR 2023 SC 3601	258	402
209	Satendra Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation and anr.	2022 (3) Crimes 290 (SC)	13	15
210	Satya Narayan Ramniwas Petrol Pump (M/s) v. State of M.P. & ors.	ILR 2023 MP 517	78	115
211	Satyanarayan Verma v. Sandeep Yadav & anr.	ILR 2023 MP 1171	213	306
212	Saurav Das v. Union of India and ors.	2023 (1) Crimes 279 (SC)	90	132
213	Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti, Krishi Upaj Mandi, Neemuch v. Tarabai thru. L.Rs.	AIR 2022 MP 132	10	11
214	Shishpal alias Shishu v. State (NCT of Delhi)	(2022) 9 SCC 782	22	31
215	Shiv Kumar v. State of Madhya Pradesh	2022 (3) Crimes 399 (SC)	26	42
216	Shri Kumar and ors. v. Gainda Lal and ors.	2023 ACJ 588 (SC)	157	219
217	Shyam Sel and Power Limited and anr. v. Shyam Steel Industries Limited	(2023) 1 SCC 634	44	63
218	Shyam Singh Tomar v. State Bank of India	AIR 2023 MP 35	170	236
219	Shyno M. Aykara and ors. v. New India Assurance Co. Ltd. and anr.	2023 ACJ 901	195	276
220	Smriti Debbarma (dead) Through Legal Representative v. Prabha Ranjan Debbarma and ors.	AIR 2023 SC 379	211	303
221	Smt. Roopa Soni v. Kamalnarayan Soni	AIR 2023 SC 4187	240	365

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
222	Smt. Ved Kumari v. Municipal Corporation of Delhi through its Commissioner	AIR 2023 SC 4155	223	325
223	Solomon Selvaraj and ors. v. Indirani Bhagawan Singh and ors.	2023 (1) MPLJ 300 (SC)	39	56
224	SOW Pushpa Goyal & ors. v. Daya Ram (dead) through LRs. & ors.	ILR 2023 MP 254	128	181
225	Sri Mahavir Agency and anr. v. State of West Bengal and anr.	(2023) 6 SCC 103	203	288
226	State Bank of India and anr. v. Ajay Kumar Sood	(2023) 7 SCC 282	201	283
227	State of Himachal Pradesh v. Nirmal Kaur @ Nimmo and ors.	2022 (4) Crimes 527 (SC)	60	91
228	State of M.P. v. Rajdeep Buildcon Pvt. Ltd. Ahmadnagar	2023 (2) MPLJ 439	125	177
229	State of Madhya Pradesh v. Jad Bai	(2023) 6 SCC 552	183	258
230	State of Punjab v. Kewal Krishan	AIR 2023 SC 3226	250	387
231	State of Uttar Pradesh v. Sonu Kushwaha	(2023) 7 SCC 475	264	416
232	State through Deputy Superintendent of Police v. R. Soundirarasu etc.	AIR 2022 SC 4218	48	68
233	State through the Inspector of Police v. Laly @ Manikandan and anr.	2022 (4) Crimes 493 (SC)	57	84
234	Subhanshu Soni v. State of M.P. and ors.	2023(3) MPLJ 685	257	400
235	Sudhamayee Pattnaik and ors. v. Bibhu Prasad Sahoo and ors.	AIR 2022 SC 4304	7	7

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
236	Sukhbir Singh Badal v. Balwant Singh Khera and ors.	AIR 2023 SC 3053	255	397
237	Sukhpal Singh Khaira v. State of Punjab	(2023) 1 SCC 289 (5 Judge Bench)	50	71
238	Sundar @ Sundarrajan v. State by Inspector of Police	2023 (2) Crimes 29 (SC) (3 Judge Bench)	147	206
239	Sunil v. Bashir Khan and ors.	2023(3) MPLJ 682	221	323
240	Supriya Jain v. State of Haryana and anr.	(2023) 7 SCC 711	243	373
241	Surendra Rathore v. Vishwanath Bhasin and anr.	2023 (2) MPLJ 422	173	242
242	Surendra Singh v. State of Rajasthan and anr.	2023 (2) Crimes 117 (SC)	142	199
243	Sureshchandra & ors. v. Girirajsingh & ors.	ILR 2023 MP 1405	226	330
244	Sushma H.R. and anr. v. Deepak Kumar Jha and ors.	2023 ACJ 331	156	218
245	T.R. (Tulsiram) Kori v. Raja Singh	AIR 2023 MP 113	267	419
246	Tarun v. Goma and ors.	ILR (2023) MP 135	131	184
247	Tejlal v. Pragyand and anr.	2023 (2) MPLJ 665	172	240
248	Tejmal Karnawat v. Chandrakanta Kashyap & anr.	ILR 2023 MP 1397	216	310
249	The Directorate of Enforcement v. M. Gopal Reddy & anr.	2023 (2) Crimes 2 (SC)	118	167
250	Trilochan Singh v. Indrajeet Kaur	2023 (2) MPLJ 141	*85	127
251	Tulsiram & ors. v. Rajaram & ors.	ILR 2023 MP 481	95	139
252	U.N. Krishnamurthy (Since Deceased) thr. LRs. v. A.M. Krishnamurthy	AIR 2022 SC 3361	74	111
253	Udayakumar v. State of Tamil Nadu	2023 (2) Crimes 58 (SC)	108	154

S. No.	CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
254	Udayakumar v. State of Tamil Nadu	2023 (2) Crimes 58 (SC)	145	203
255	Uggarsain v. State of Haryana and ors.	(2023) 8 SCC 109	242	371
256	Umrao Singh Mourya v. State of M.P.	ILR 2023 MP 536	92	136
257	Veekesh Kalawat v. State of M.P. & anr.	ILR 2023 MP 1287	205	292
258	Venkatesh @ Chandra & anr. etc. v. State of Karnataka	2023 (1) Crimes 214 (SC)	135	190
259	Vijay @ Cheeku v. State of M.P.	ILR 2023 MP 1243	204	290
260	Vijay Rajmohan v. Central Bureau of Investigation (Anti-Corruption Branch)	(2023) 1 SCC 329	71	104
261	Vikas Rathi v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2023) 6 SCC 702	231	342
262	Vikram Shrivastava v. Rampur Finance Corporation Pvt. Ltd. & ors.	ILR 2023 MP 1501 (DB)	224	327
263	Vikramjit Kakati v. State of Assam	AIR 2022 SC 3597	17	25
264	Vinod Kumar and ors. v. District Magistrate, Mau and ors.	AIR 2023 SC 3337	261	407
265	Vishan Singh v. Daulat Singh and ors.	2023 ACJ 576	153	216
266	Wonder Cement Ltd. Indore v. Rameshwar Pratap Singh (dead) thr. L.Rs. and ors.	2023 (2) MPLJ 363	127	179
267	X v. State of Madhya Pradesh	(2023) 5 SCC 504 (3 Judge Bench)	189	267
268	XYZ v. State of Madhya Pradesh and ors.	2022 CriLJ 3969	15	22
269	Y v. State of Rajasthan and anr.	(2022) 9 SCC 269	19	27

•